SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, all hon. Members are associating themselves with this issue.

GOVERNMENT BILL

The Lokpal and The Lokayuktas Bill, 2011

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Now, Prof. Ram Gopal Yadav. ...*(Interruptions)*... The others may please remain quiet.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने लोकपाल बिल पर चर्चा से पहले मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा समय दिया। श्रीमन्, जब भारत का संविधान बना, तो उसमें जो लोग थे, उनके स्टेचर बहुत बड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द बल्लभ पंत, बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य सारे लोग, जो हिन्दुस्तान की इंटेलेक्चुअल क्रीम थी, वह उस संविधान सभा में थी, जिसने संविधान बनाया। इसके बाद की जो स्थिति है, धीरे-धीरे हमें ऐसा लगता है कि इस देश में उस सबको पलटने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। कानून में यह होता है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध न हो जाए, तब तक उसको निर्दोष माना जाए। लेकिन यह बिल इस तरह का है, जिसमें हर व्यक्ति को दोषी मान कर चला जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर एमपी तक और कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर निचले स्तर के अधिकारी तक, किसी के भी खिलाफ कोई भी व्यक्ति एप्लिकेशन दे सकता है और हम लोगों को, खास तौर से मंत्रियों को एक एसपी स्तर के अधिकारी के सामने, एक डिप्टी स्तर के अधिकारी के सामने अपना बयान देने के लिए जाना पड़ेगा। यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होगी। आगे स्थिति यह होगी कि कोई भी अधिकारी निर्णय लेने से, दस्तखत करने से डरेगा। मंत्री दस्तखत करने से डरेंगे।

बोफोर्स तोप के बाद आज तक हिन्दुस्तान को दूसरी तोप नहीं मिली। एक जांच के कारण, एक डिफेंस सेक्रेटरी के जेल जाने के कारण असर यह हुआ कि हर आदमी कागजों पर दस्तखत करने से डरता है कि हमारी जांच होगी और हम फंस जाएंगे।

आज ही अखबार में आया है, "अगली सरकार के भरोसे सैन्य आधुनिकीकरण, लड़ाकू विमान, तोप, पनडुब्बी खरीद समेत कई सौदे ठंडे बस्ते में"। कोई अधिकारी फाइल पर दस्तखत करना नहीं चाहता है, वह हर फाइल प्रधानमंत्री के पास भेजना चाहता है कि प्रधानमंत्री ही इसके ऊपर दस्तखत करें ताकि जिम्मेदारी हो तो प्रधानमंत्री की हो। इस तरह सब अधिकारी अपनी ड्यूटी से बचना चाहते हैं। इसके माध्यम से आप देश को अनिर्णय की स्थिति में ले जाना चाहते हैं।

इतने दिनों से हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही थी और लोग हमसे इसका कारण पूछ रहे थे। मैं आपके माध्यम से सभी संसद सदस्यों से और देश की जनता से यह कहना चाहता

हूं कि यह विधेयक, जिसे आप ला रहे हैं और पास करने जा रहे हैं, उसके बारे में आज नहीं तो कल, मैं जो कह रहा हूं, वही बात सच साबित होगी।

हम राजनैतिक व्यक्ति हैं, हमारे विरोधी होते हैं। जो भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, वह आपका विरोधी है। आपके भी राजनैतिक विरोधी होंगे या कोई और विरोधी होंगे। जो यह कहें कि हम बिल्कुल सौ परसेंट दूध के धुले हैं, उस एमपी को भी कल लोकपाल आने के बाद एमपी लैड वाले मामले में जेल भेजा जा सकता है। तब उसको कोई रोक नहीं पाएगा।

यदि नीचे की वर्किंग एजेंसी से भी थोड़ी-बहुत गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी अंततोगत्वा एमपी की ही होगी। एमपी के लिए यह कहा जाएगा कि इसी ने बेईमानी की है। कोई अधिकारी फाइल नहीं चलाएगा। और तो छोड़िए, क्लास-III और क्लास-IV के इम्पलॉइज़ भी डरेंगे, क्योंकि कोई भी यह कह सकता है कि साहब, यह इम्प्लॉई फाइल ले जाने के लिए हमसे पैसा मांग रहा था। बस फिर जांच शुरू हो जाएगी, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। सबसे खतरनाक स्थिति तो यह होगी, जब प्रधान मंत्री को किसी जांच करने वाले डिप्टी एसपी या एसपी स्तर के अधिकारी के समक्ष अपनी बात कहनी पड़ेगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लैवल का तो उसका डायरेक्टर होगा।

अगर एक बार आपके खिलाफ जांच शुरू हो जाए, तो चाहे आप निर्दोष साबित हो जाएं, लेकिन जनता की निगाह में आप बे-ईमान साबित हो जाते हैं। जिसके दरवाजे पर एक बार सीबीआई चली जाए, बाद में चाहे वह बिल्कुल निर्दोष साबित क्यों न हो जाए, लेकिन यह मान लिया जाता है कि वह बे-ईमान है। उसके खिलाफ एक प्रचार शुरू हो जाता है। आप देश के सामने वही स्थिति लाना चाहते हैं? आप यह मान कर चल रहे हैं कि हर नेता, सारे के सारे लोग बे-ईमान हैं, केवल लोकपाल ईमानदार है। लोकपाल आएगा कहां से? लोकपाल कौन है?

अभी यहां जजिज़ का नाम लिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज अथवा चीफ जस्टिस लोकपाल होंगे। आप बताइए कि अभी जजिज़ का मामला सामने आया है या नहीं आया? ये लोकपाल होंगे? दूसरी तरफ, जो जनता की दिन-रात सेवा करते हैं, अगर कोई आधी रात में भी दरवाजा खटखटाता है, कोई कष्ट में होता है, तो यहां बैठे हुए ये पॉलिटिकल लोग उनकी मदद करते हैं। क्या वे सब बे-ईमान हैं। क्या वे ईमानदार हैं, जो कभी किसी से मिलते नहीं, अगर मिलने के लिए टाइम लो तो कहेंगे कि पूजा कर रहे हैं या ऑफिस चले गए हैं। जब वे रिटायर हो जाएंगे तो लोकपाल बन जाएंगे और तब वे आपके खिलाफ जांच करेंगे।

मेरी आपसे अपील है कि आप इस मामले पर पुनर्विचार करें। यह देश के हित में नहीं है। जब बहुत इम्पॉर्टेंट मसलों पर निर्णय नहीं हो सकेगा, देश अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाएगा, वह देश के हित में नहीं होगा। प्रधानमंत्री को देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में कई बार तत्काल निर्णय लेना पड़ सकता है। इसमें भी क्वेश्चन उठेगा और इसमें भी जांच होंगी, तो यह देश के हित में नहीं है। इसलिए, मैं कहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और इस लोकपाल विधेयक पर आप यह जो काम करने जा रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी भागीदार नहीं बनेगी और इसलिए हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् कुछ सदस्य सदन से उठ कर बाहर चले गए)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Kapil Sibal to move the Bill. Mr. Narayanasamy had started with it. You can continue.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I rise to commend the Lokpal and the Lokayuktas Bill, 2011 to the distinguished Members of this House.

Sir, since my colleague Narayanasamy has already commended this Bill to the House, I will not take too much time, I would like to state that this House is confronted with a historic opportunity, either to make history or to repeat history, and, I am sure that the distinguished Members of this House will collectively, this day, make history and not repeat it.

Sometimes, we have to rise above our political viewpoints and listen to those outside this House, listen to their expectations from the distinguished Members of this House, and, also listen carefully to the manner in which we have conducted ourselves over the years. I think that never before in the history of this country has such a Bill had such a wide public discussion. I think, ever since Independence eight Lokpal Bills have been initiated in this House, and, with the exception of one in 1985, which was withdrawn, all others lapsed, and, then, we are ail aware of events, which I do not want to mention, which resulted in a Joint Drafting Committee that was set up on the 8th of April, 2011. In the course of the Joint Drafting Committee, we heard the voice of the civil society, and also opined on what should be the nature of the Lokpal and the Lokayuktas Bill. Ultimately, there was an all-Party meeting on 3rd of July, 2011, and, then, we introduced the Lokpal Bill, 2011 in the Lok Sabha on the 4th of August, 2011. The Bill was referred to the Department-related Parliamentary Standing Committee on 8th of August, 2011, and, on 27th of August, the sense of the House was summed up by my Cabinet colleague, who was then the Finance Minister, in the following words, and, I quote, "This House agrees in principle on the Citizens Charter, Lower Bureaucracy to be brought under Lokpal through appropriate mechanism and establishment of Lokayuktas in the States. I will request you to transmit the proceedings to the Department-related Parliamentary Standing Committee for its perusal while formulating its recommendations for the Lokpal."

The Standing Committee had extensive discussions with all concerned stakeholders. In its 48th Report, it made a number of recommendations suggesting major amendments in the Bill as regards the scope and the content of the Bill

including necessary provisions that ought to be incorporated. Then, in the context of the recommendations of the Standing Committee, we withdrew the Bill and introduced a fresh Bill in the Lok Sabha, a more comprehensive Lokpal and the Lokayuktas Bill of 2011, on the 22nd of December, 2011. It was passed on the 27th of December in the Lok Sabha. But when it came to this House, this House adopted a Motion on the 21st of May 2012 and referred the matter to the Select Committee. I must say, and I must compliment-the distinguished Members of the Select Committee, that they very carefully looked at various provisions of the Bill and made very comprehensive recommendations. The Leader of the Opposition here was also responsible in taking a very constructive approach to ensure that we have a comprehensive and well thought-out legislation which should be presented to this House to be passed.

Now, Sir, I want to make it very short, so I just want to give salient features of the Bill as passed by the Lok Sabha and then the salient features of the amendments that are being moved in the context of the recommendations of the Select Committee. Sir, the Bill, as passed by the Lok Sabha, provides broadly for the following:

One, it seeks to establish the institution of the Lokpal at the Centre and the Lokayukta at the level of the State and thus seeks to provide a uniform vigilance and anti-corruption road map for the nation both at the Centre and at the States.

Two, the Lokpal will consist of a Chairperson with a maximum of eight Members of which fifty per cent shall be judicial Members and fifty per cent of the Members of the Lokpal shall come from amongst the SCs, the STs, the OBCs, minorities and women. The selection of the Chairperson and the Members of Lokpal shall be through a Selection Committee consisting of the Prime Minister, the Speaker of the Lok Sabha, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, the Chief Justice of India or a sitting Supreme Court Judge nominated by the Chief Justice of India and an eminent jurist to be nominated by the President of India.

Three, a Search Committee will assist the Selection Committee in the process of selection. Fifty per cent of the'Members of the Search Committee will also be from amongst the SCs, the STs, the OBCs, minorities and women.

Four, the Prime Minister has been brought under the purview of the Lokpal with subject matter exclusions and specific process for handling complaints against the Prime Minister.

Five, Lokpal's jurisdiction will cover all categories of public servants, including officers of Group A and Group B and Group C and Group D employees of

[Shri Kapil Sibal]

Government on complaints referred to the CVC by the Lokpal. The CVC will send its report of PE in respect of Group' A and Group B Officers back to the Lokpal for further decision. With respect to categories of employees from Group C and Group D, the CVC will proceed further in exercise of its own powers under the CVC Act subject to reporting and review by the Lokpal.

Six, the Lokpal will have the power of superintendence and direction over any investigating agency, including the CBI, for cases referred to them by the Lokpal.

Seven, a High-Powered Committee chaired by the Prime Minister will recommend the selection of the Director CBI.

Eight, the Bill also incorporates a number of other significant features. For instance, the Bill incorporates provisions for attachment and confiscation of property acquired by corrupt means even while the prosecution is pending. The Bill lays down timelines. For Preliminary Enquiry, it is three months extendable by three months. For investigation, it is six months which may be extended by six months at a time. For trial, it is one year extendable by one year.

Nine, the Bill proposes to enhance maximum punishment under the Prevention of Corruption Act from seven years to ten years. The minimum punishment under sections 7, 8, 9 and 12 of the Prevention of Corruption Act will now be three years, and the minimum punishment under section 15, Punishment for Attempt, will now be two years.

These are the broad features of the Lokpal Bill which are now accepted. There is a general consensus that has emerged.

Now, I want to touch upon some of the most significant changes in the Bill as recommended by the Select Committee.

First, the Select Committee has recommended to do away with Part III of the Bill which contains provisions relating to State Lokayuktas and the argument was that the State Lokayuktas would be part of Parliamentary legislation that impacts on the federal structure. So, we have accepted that. In its place, the Select Committee has recommended that this part of the Bill may be replaced with a new section, section 63, which contains a mandate for setting up of the institution-of the Lokayukta through enactment of a law by the State Legislature within a period of 365 days from the date of commencement of the Act. The Government has decided to accept this recommendation. So, we will have a Lokpal Bill here and we will hopefully have in 365 days a similar Lokayukta in every State of this country.

Second, the Select Committee has recommended that the fifth Member of the Selection Committee for selection of Lokpal under the category of 'eminent jurist' may be nominated by the President on the basis of recommendation of the first four Members of the Selection Committee, namely, the Prime Minister, the Speaker, Lok Sabha, the Leader of the Opposition, Lok Sabha, and the Chief Justice of India. The Government has decided to accept this recommendation. Third, the Select Committee has recommended that in clause 14(l)(g) of the Bill, the category 'institutions financed by Government' be retained under the jurisdiction of Lokpal, but 'institutions aided by Government' may be excluded. The Government has decided to accept this recommendation. Fourth, in clause 14(l)(h) of the Bill, the Select Committee has recommended exclusion of bodies and institutions receiving donations from the public from the purview of Lokpal. Even though the Government was not in favour of excluding all such bodies receiving donations from the public from the jurisdiction of Lokpal and had agreed only to the limited exclusion of religious and charitable institutions, in the interest of evolving a consensus on the Bill, the Government is willing to accept this recommendation of the Select Committee and drop the relevant official amendment in the Bill as reported by the Select Committee. Fifth, the Select Committee has recommended that the power to grant sanction for prosecution of public servants should be shifted to the Lokpal in place of the Government. The Select Committee had also recommended that the Lokpal may be required to seek comments of the competent authority and the public servant before taking a decision. The Government has decided to accept this recommendation of the Select Committee with a slight modification that we want to give to that particular Government servant, a hearing before that decision is taken by the Lokpal. With that slight modification of a drafting nature, the Committee has also proposed an amendment to clause 23 of the Bill which dispenses with sanction of the competent authority for prosecution and investigation or inquiry ordered by the Lokpal. Here again, it is proposed to accept the recommendation of the Select Committee subject to that modification that so far to fill the gap in the revised provision as contained in draft Bill as reported by the Committee, instead of comments by the Department, an explanation by the public servant concerned will be called for before launching prosecution or called for before taking the inquiry forward by the Lokpal or by the agency concerned. Sixth, another significant recommendation made by the Select Committee is that before taking a decision on filing a chargesheet in a case upon consideration of

[Shri Kapil Sibal]

the investigation report, the Lokpal may authorise its own prosecution wing or the concerned investigating agency to initiate prosecution in special courts. The original Bill, as passed by Lok Sabha, provided for prosecution of the case only by the prosecution wing of the Lokpal. The Government has decided to accept this recommendation of the Select Committee. Seventh, the Select Committee has recommended a number of amendments in the Bill with a view to strengthening the CBI such as, (1) setting up of a Directorate of Prosecution headed by a Director of Prosecution under the overall control of the Director, CBI; (2) appointment of the Director of Prosecution on the recommendation of the CVC; (3) maintenance of a panel of advocates by CBI other than Government advocates with the consent of the Lokpal for handling Lokpalreferred cases; (4) transfer of officers of CBI investigating cases referred by Lokpal with the approval of Lokpal; (5) provision of adequate funds to CBI for investigating cases referred by Lokpal. The Government had originally decided to accept all these recommendations except the recommendation relating to transfer of officers of CBI investigating cases referred by Lokpal with the approval of Lokpal as that would affect the smooth functioning of CBI. However, in the interest of evolving a consensus on the Bill, the Government is willing to accept this recommendation of the Select Committee as well.

Now, broadly speaking, the essence of this legislation is that the investigating agencies will be independent; the appointment of the CBI Director will be done through an independent and transparent process; all public functionaries would be under the Lokpal Bill; the prosecution under the control of the Lokpal will be done through the Director, Prosecution who shall also be appointed independently. The prosecution by the CBI agency with reference to matters referred to it by the Lokpal will also be overlooked by the Lokpal itself. So, there is no element of Governmental interference when you deal with matters of corruption. I think, Sir, this is truly a historic movement. I thank the Prime Minister, the Leader of the UPA Government, the Leader of the Opposition and leaders of all political parties who are sitting here today, who have listened to the voice of millions in this country, who are really fed up with corruption at the highest levels in this country; and at all levels. *...(Interruptions)...* I do not think this is the time to laugh and snigger. In fact, this is the time to celebrate that we have at last reached a consensus. It is time to congratulate all those who have worked very hard for this consensus. We can raise issues of politics, but I don't think this is the time for that. We can

generate political heat and debate, but I don't think it is the time for that. We can criticise for what has happened, in the past, for what we did and what we did not do. I don't think it is the time for that, it is time for us to rise to the occasion to celebrate this consensus; and congratulate all those who have participated effectively, positively to evolve this consensus.

The question was proposed.

विपक्ष के नेता (श्री अरुण जेटली): माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, कानून मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते वक्त कहा कि इतिहास बनता भी है और इतिहास दोहराया भी जाता है। महोदय, आज की बहस, 29 दिसम्बर, 2011 को सारे दिन चली बहस, जो कि मध्य रात्रि को इंटरप्ट हो गयी थी, उसी बहस को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। 29 दिसम्बर, 2011 को जो कुछ हुआ, उस इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है। हवा बदली है, राजनीतिक माहौल बदला है, लेकिन समस्त विपक्ष का वही रवैया है, जो 29 दिसम्बर, 2011 को था। इस बदले हुए राजनीतिक माहौल में और इस बदली हुई हवा में शायद सरकार की समझ थोड़ी बदली है। इसलिए हम 29 दिसम्बर, 2011 को जो कह रहे थे, उस में क्या गुण था और क्या मेरिट थी, यह आज सरकार को समझ आना आरंभ हुआ है।

यह सभी के लिए खुशी की बात है कि इतिहास ने हमें एक और अवसर दिया है कि जो बहस पिछले 46 वर्षों से इस देश में चल रही थी, उसे आज समाप्त कर हम पहल करें और लोकपाल बिल को पारित करें। उस बिल में जो कमियां और कमजोरियां थीं, उनको दूर करें और उन्हें दूर करने के बाद एक विश्वसनीय और क्रेडिबल कानून, जो क्रेडिबल हो और वर्केबल भी हो, उसे देश के सामने पेश करें।

मुझे इस बात का खेद है कि हमारा एक प्रमुख राजनीतिक दल सैद्धांतिक रूप से इस कानून के खिलाफ है और इसलिए वह इस का बहिष्कार कर रहा है। बेहतर होता कि सभी राजनीतिक दल, इस के हर पहलू पर विचार कर सर्वसम्मति से इस कानून को पास करते। समाजवादी पार्टी द्वारा यह कहना कि निर्णय की प्रक्रिया इस देश में समाप्त हो जाएगी, लोग निर्णय करते वक्त डरेंगे, शायद यह अपने आप में ठीक नहीं होगा। यह कानून आने से निर्णय की प्रक्रिया सुधरेगी, लोग गलत कारणों से निर्णय करते वक्त डरेंगे और निर्णय करते वक्त यह भी महसूस करेंगे कि जो मैं फाइल पर लिख रहा हूं या जो निर्णय कर रहा हूं, कल उसे कोई-न-कोई पढ़ने वाला है और इस के ऊपर टिप्पणी करने वाला है। और मेरे द्वारा यह निर्णय करना ईमानदारी के कारण है। मुझे विश्वास है कि आरंभिक दिनों में कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन राजनीति ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम हर रोज सीखते हैं, हर रोज अपने आपको सुधारने का प्रयास करते हैं और इसलिए

[श्री अरुण जेटली]

जो सुधार इस देश में आवश्यक हैं, इस देश के हित और राजनैतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए, उसमें यह कानून बहुत बड़ा योगदान होगा।

उपसभापति जी, यह तो हकीकत है कि जनता के बीच में राजनीति की विश्वसनीयता में और राजनैतिक लोगों के ऊपर विश्वास करने में गिरावट आई है। इसलिए इस हकीकत को हम लोग स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद हम अपने आपको और इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। अगर हम इसे सुधारने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से एक जो प्रक्रिया राजनीति की आरंभ होती है, क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, उसमें हम एक योगदान देंगे। मैंने यह भी आलोचना सुनी है कि सेन्स ऑफ द हाउस वह रेजोलूशन और निर्णय था, जो उस वक्त के वित्त मंत्री ने सदन के सामने पेश किया था और सदन ने स्वीकार किया था, उसमें देश के समक्ष जो वायदा किया गया था, वह इसमें पूरा नहीं हुआ। उसमें एक वायदा यह था कि हम एक प्रभावी लोकपाल इस देश में देंगे। इस लोकपाल में भी, जो आज हम पारित करने जा रहे हैं, सुधार की बहुत गुंजाइश है। क्या यह आदर्श कानून है? आदर्श कानून तो आज तक कभी देश में बना नहीं है, हर कानून में अनुभव के आधार पर सुधार की आवश्यकता होती है और मुझे विश्वास है कि 29 दिसम्बर, 2011 और आज के बीच में आप सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले कल में भी शायद इसमें चार और सुधार करने की आवश्यकता पड़े, अनुभव के आधार पर इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया उसको करेगी। दूसरा वायदा हम लोगों ने यह किया था कि सिटीजन्स चार्टर और उनकी ग्रिवीएंसेज के संबंध में हम लोग कानून बनाएंगे। मैं सरकार से, प्रधान मंत्री जी यहां हैं, आग्रह करूंगा कि कई राज्यों में यह कानून बन चुका है, लोक सभा में यह इंटरोड्यूस हो चुका है, इस कानून को लेकर कोई राजनीतिक विवाद नहीं है, इससे तो प्रशासन का स्तर सुधरेगा, इसलिए इसको शीघ्र लोक सभा के एजेण्डा पर लाकर और उसके बाद इस सदन में लाकर पारित भी किया जाए, ताकि उस सेन्स ऑफ द हाउस रेजोलूशन का जो दूसरा चरण था, उसको भी हम पूरा कर पाएं। इसमें तीसरा विषय था कि हर राज्य के अंदर लोकायुक्त की स्थापना होगी। इस विषय पर कोई यह केवल राजनैतिक बहस नहीं, एक संवैधानिक बहस थी। हम लोगों का यह कहना था और अधिकतर राजनैतिक दल और क्षेत्रीय राजनैतिक दलों की विशेष रूप से यह मान्यता थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लोकायुक्त या लोकपाल के माध्यम से लड़ाई लड़नी है, तो देश के संघीय ढांचे के साथ-साथ वह लड़ी जा सकती है। Federalism and the battle against corruption can co-exist. For implementing that battle against corruption through Lokpal, do we have to dismantle the federal character of India? और 29 दिसम्बर, 2011 की बहस में यह बात प्रमुख कारण थी। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है - International Convention against Corruption, उसको इफेक्ट देने के लिए इस कानून को लाया गया और इसलिए केन्द्रीय सरकार के पास यह अधिकार होगा। अन्य राजनैतिक दलों का यह मानना था कि यह कानून राज्य की सेवाओं के साथ संबंध रखता है, यह केवल क्रिमिनल लॉ नहीं

है। It is not merely a criminal law legislation which could be on the Concurrent List, it also deals with 'Services of the State' and 'Services of the State' is exclusively a State subject. Therefore, can the Central Parliament or Legislature enact a law in relation to action against civil servants exclusively of the State? अन्य राजनैतिक दलों को यह लगता था कि शायद यह करना संभव नहीं होगा। इसलिए सेलेक्ट कमेटी के सुझाव के बाद आज एक सुझाव लाया गया और इसमें एक प्रावधान यह कर दिया गया कि एक वर्ष के अंदर हर राज्य में लोकायुक्त बनाना आवश्यक होगा। केंद्र हर राज्य को एक मॉडल लॉ इसी कानून के आधार पर भेजे। उस कानून को या कुछ संशोधनों के साथ हर राज्य की विधान सभा के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उस लोकायुक्त को भी पारित करे। लोकायुक्त होगा, लेकिन संविधान के दायरे में होगा और हर राज्य की जो संवैधारिक संस्था है - हर राज्य की विधान सभा, यह जिम्मेवारी उसके ऊपर दी गई है और उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि उस कानून को वह बनाए।

उपसभापति जी, इसमें स्टैंडिंग कमेटी रही, कई रिपोर्टें रही। जैसा कि माननीय कानू मंत्री जी ने कहा कि मुझे भी सेलेक्ट कमेटी के सदस्य के रूप में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सहयोगी श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी उस सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने सेलेक्ट कमेटी की प्रोसीडिंग्ज़ चलाई, एक-एक प्रावधान के ऊपर घंटों-घंटों चर्चा चली। समाज के जो सबसे बड़े विशेषज्ञ हो सकते थे, उनको बुलाया गया और 29 दिसंबर, 2011 वाला जो पुराना ड्राफ्ट था, जिसको लेकर हमारे मन में बहुत शंकाएं थीं, उसको सुधारा गया। क्या लोकपाल की नियुक्ति करने में सरकार का पलड़ा भारी रहेगा, यह हमें शक था और इसलिए हम यह कहते थे कि अगर सरकार का पलड़ा भारी रहता है और केंद्र की सरकार और राज्यों में राज्य की सरकार अपने मन में लोकपाल की नियुक्ति कर ले, तो फिर उसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा। पहले ड्राफ्ट में पांच से तीन ऐसे लोग थे जो सरकार का पक्ष ले सकते थे। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक लीडर ऑफ अपोज़िशन थे, दोनों सरकार के दायरे से बाहर थे। लोक सभा के अध्यक्ष उसमें रहेंगे, प्रधान मंत्री जी रहेंगे, पांचवें सदस्य एक ज्यूरिस्ट ऑफ एमिनेंस रहेंगे, जिनको सरकार नियुक्त करती है। इसको हम लोगों ने बदल दिया और बदलकर ये पहले चारों सदस्य जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, लीडर ऑफ अपोज़िशन भी होंगे, लोक सभा के अध्यक्ष भी होंगे, प्रधान मंत्री जी भी होंगे, ये चारों मिलकर पांचवें सदस्य का चयन करेंगे जो एक ज्यूरिस्ट ऑफ एमिनेंस होगा। इस पूरी प्रक्रिया में लोकपाल की नियुक्ति वे लोग करेंगे और इसके संबंध में जो प्रक्रिया है, वे लोग चलाएंगे। जिस लोकपाल के खिलाफ शिकायत होगी, उसको हटाने का अधिकार किसके पास होगा? जो विधेयक सरकार लाई थी, उसमें हटाने का अधिकार और उस कार्रवाई को आरंभ करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास था। केंद्र सरकार चाहे तो राष्ट्रपति जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और जैसा अभी श्री देरेक ओब्राईन ने पश्चिम बंगाल के ह्यूमन राइट्स कमिशन के चेयरमैन के संबंध में एक विषय उठाया था, तो केवल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर सकती है, कोई

[श्री अरुण जेटली]

दूसरा सदस्य चाहे भी तो नहीं कर सकता। उस प्रावधान को बदलकर सांसदों द्वारा जैसे इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, यह अधिकार उसकी तरफ शिफ्ट किया गया। इस रेफरेंस के दौरान, मौजूदा मसला, जिसका जिक्र किया गया कि क्या वे अपने पद पर बने रह सकते हैं? पुराने बिल में सस्पेंड करने का अधिकार केंद्र सरकार को था, वह अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया, ताकि लोकपाल को हटाने या सस्पेंड करने के प्रावधान को भी एक प्रकार से निष्पक्षता दी जा सके। इसके अतिरिक्त लोकपाल का जो अधिकार क्षेत्र है, उसके संबंध में मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार उस पर पुनर्विचार कर ले। जहां सरकारी धन, सरकारी साधन और सरकारी राजस्व का इस्तेमाल होता है, सरकार के संबंध में, सरकारी संस्थाओं के संबंध में, लोकपाल के अधिकार-क्षेत्र में वे लोग आते हैं। The jurisdiction of the Lokpal and Lokayuktas predominantly should be in relation to where Government revenues are involved, where Governmental functions are involved. In the original Bill, you had kept a provision that besides the Government, anybody else, including the private bodies which are raising donations from the public, would also be covered.

The Select Committee unanimously felt that this would overburden the Lokpal. There are hundreds of schools, colleges, religious organizations, temples, mosques, gurudwaras, private NGOs, societies, which have nothing to do with the Governmental functioning. Then, why do you burden the Lokpal with this functioning? There will be separate laws under each of their functioning which will cover them. This is one area where I see, from the new Amendments that you have brought, that you have disagreed with the recommendation of the Select Committee. In the Amendment, moved by Shri Narayanasamy, to the Bill as drafted by the Select Committee, in the special Amendment to clause 3, they have excluded religious organizations.

SHRI KAPIL SIBAL: We are not moving this Amendment. I have already indicated that.

SHRI ARUN JAITLEY: I am glad to hear that. If you go back to the recommendation of the original Select Committee, which is the appropriate and the correct amendment, then, I am in favour of that. Otherwise, to include all private organizations within the Lokpal...

SHRI KAPIL SIBAL: No, we are not.

SHRI ARUN JAITLEY: This will almost be infiltrating into every area of life which, at this stage, is not desirable. I am grateful to the hon. Minister if he is not moving the amendment.

SHRI KAPIL SIBAL: We are moving Amendment Nos. 6, 7 and 8. Other than those, we are not moving any other Amendment.

श्री अरुण जेटली: इसके अलावा जांच करने की जो प्रक्रिया थी, वह बहुत विचित्र प्रकार की थी। जो पुराना कानून आया था, उसकी जांच की प्रक्रिया असंभव प्रकार की थी। मुझे याद है, 29 दिसम्बर की बहस में मैंने कहा था कि जैसे एक जलेबी की शेप होती है, एक जांच ऊपर से नीचे आती जाएगी, फिर घूमती जाएगी और वर्षों तक समाप्त नहीं होगी। वह प्रक्रिया इस प्रकार की थी। सेलक्ट कमेटी ने उसको सिम्प्लीफाई किया है। वे सुझाव अधिकतर स्वीकार किए गए, लेकिन आज जो एक अमेंडमेंट है, उसके संबंध में मैं यह भी स्पष्टीकरण ले लूं कि यह जो सरकार की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को रेकमेंडेशन आया है, विशेष रूप से अमेंडमेंट संख्या 6...

SHRI KAPIL SIBAL: I shall clarify this.

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Minister, I have some suggestions to offer in regard to your Amendment No.6. It is fair enough to say that the Lokpal should hear a delinquent public servant and, therefore, you have introduced, at Page 10, after line 11, the following proviso, and the proviso reads: "Provided that before ordering an investigation under sub-clause b, the Lokpal shall call for an explanation from the public servant so as to determine whether there exists a *prima facie* case for investigation or not." सामान्य तौर पर जिसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, उससे पूछना अपने आपमें न्यायसंगत है, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसमें एक अपवाद करने की जरूरत है। आपने जनरल कह दिया कि किसी इन्वेस्टीगेशन या प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी से पहले उसकी सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार के बहुत अधिक मामले आते हैं। बाहर जितने भी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन सबका भी यह आग्रह है कि इस विषय पर पुनर्विचार कर लें, यह एक गंभीर विषय है। भ्रष्टाचार के संबंध में जितने विषय आते हैं, उनमें किस प्रकार की शिकायतें आती हैं? अगर यह शिकायत आयी कि किसी ने तीन साल पहले आदेश पारित किया था, क्या इससे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट अट्रैक्ट होता है तो आप सुनवाई कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आरोप यह है कि फलां आदमी रिश्वत मांग रहा है और इस जगह पर रिश्वत लेगा तो आपको उसी वक्त रेड करके, छापा मारकर उसको पकड़ना है। ऐसे मामले में आपको उसे पहले कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है।

श्री कपिल सिब्बल: सर, मैं इस बात का स्पष्टीकरण अभी कर देना चाहता हूं।

SHRI ARUN JAITLEY: Let me just complete and then you give a clarification. So, in a case where a search is required or a raid is required, — this will be

[Shri Arun Jaitley]

required in two cases, that is, where disproportionate assets are located and where bribes are being given or taken — the Lokpal should have the power to take such action without giving a public servant an opportunity of hearing.

श्री कपिल सिब्बल: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर छापे की जरूरत है या कोई गलत काम कर रहा है, पैसा दे रहा है या पैसा ले रहा है, उस समय कोई hearing की बात नहीं आएगी, hearing तभी होगी जब prosecution launch होगी, prosecution launch करने से पहले छापे पर कोई हेयरिंग नहीं होगी और इस पर स्पष्टीकरण है। It is before launching prosecution.

SHRI ARUN JAITLEY: No, no; it is after launching investigation. That is my difficulty, Mr. Sibal. There is no need to correct it, please.

SHRI KAPIL SIBAL: "Whether there exists a *prima facie* case for investigation....

SHRI ARUN JAITLEY: The moment you introduce it — at page 10 after line 13 — for prosecution I have no difficulty. Please give him a hearing. But, I have no difficulty with this generalisation that you are making before any investigation. Please put a second proviso after this. It will take just one sentence. It was suggested in the All Party meeting yesterday also that put a second proviso "provided where search and seizure is required, no such opportunity will be required in the first instance." I have no difficulty. Put that proviso and you will absolutely add to the strength of this law. But if you insist on hearing in every case before investigation, that before a search and seizure you have to give a notice...

SHRI KAPIL SIBAL: Section 26 allows search and seizure without any hearing.

SHRI ARUN JAITLEY: Section 26 allows search and seizure but search and seizure takes place when investigation is ordered. You can assume that there is an alternative view also possible at times. I am glad on most other issues you are today conceding to the alternative view. Therefore, as far as this provision is concerned, a search and seizure will take place after an investigation, It can't take place before an investigation. Therefore, please allow search and seizure even without a prior notice. Make a clarificatory amendment so that this provision itself can't be misused. It will help you in recovering disproportionately acquired assets; it will help you in stopping cases of corruption. There is no difficulty. If the intention is common then the language has to be so clear that there is no scope

1.00 P.M.

for ambiguity. Therefore, I have no difficulty. Since the discussion is going to go on for some time,- the hon. Minister can consider this. Sir, with regard to the Central Bureau of Investigation, there are several changes which the Select Committee had suggested, with regard to appointment of a Director and appointment of a Director of Prosecution and with regard to financial powers. Now, with regard to transfer of officials, I had made a suggestion and I heard the Minister rightly that during the pendency of a case if an officer is to be transferred, take the prior nod from the Lokpal. Otherwise, the Government would be entitled to shift anybody arbitrarily. The powers of superintendence in Lokpalreferred cases should vest in the Lokpal itself as far as CBI is concerned. I am glad if that amendment with regard to transfer of officials is accepted, then, what the Select Committee had desired in regard to the CBI is taken care of. Sir, if this one matter of drafting required to prior notice can be sorted out, I have just one last point to make and that last suggestion is, you have provided for religious-based reservations in the matter of appointment. I am aware of the fact that my party may be alone in raising this question. But I must point out that the Constitution does not permit this kind of a reservation at any stage and therefore, we have a serious reservation. I am aware of the fact that many other parties may take the view that Mr. Sibal is taking or his Government is taking. But this Bill, to that extent, suffers from a Constitutional vice that you can't have in matters of appointment of an anti-corruption body, religious-based reservations. There is no scope within our Constitutional framework for this kind of a reservation itself. Having said this, I would once again urge the Minister to kindly consider the language.

We have some time in the course of the next couple of hours to rectify that. And, therefore, the investigative agencies and the Lokpal should be empowered to conduct searches in cases of emergency without a prior notice. Our intention seems to be the same. Therefore, the language should not leave any scope for ambiguity as far as this is concerned.

With these observations, my party will fully support this Bill so that this Bill can be passed today itself.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, if the House agrees, today we will have a lunch-break only for half-an-hour.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, avoid the lunch break.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anyhow, after Satish Chandra Misra's speech, I will take the sense of the House and decide.

SHRI SITARAM YECHURY: No, no. Sir, avoid the lunch break and continue with the debate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Avoid the lunch break? Oh! If that is the sense of the House, I am very happy. There is no lunch break. I think all of you have agreed *...(Interruptions)...* Okay, fine. All right. Thank you, Yechuryji, for that suggestion. I thank Shri Yechury for that suggestion *...(Interruptions)...* आप लोग बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Okay. After the speaks, I will again the sense of the House. मिश्रा जी आप बोलिए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने मुझे मेरी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस *लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011* पर बोलने का मौका दिया है। मैं अपनी पार्टी की लीडर और अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी की चेयरमैन सुश्री मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए अधिकृत किया है, ताकि मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात सदन के सामने रख सकूं।

मान्यवर, इससे पहले भी लोकपाल बिल पर चर्चा हो चुकी है और सदन के बाहर व सदन के अंदर भी काफी चर्चा हुई है। हर जगह बहुजन समाज पार्टी ने, हमारी लीडर सुश्री मायावती जी ने अपना स्टेंड स्पष्ट किया है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। चूंकि हमारी पार्टी हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसलिए इस तरह के बिल का स्वागत करती है और हमेशा यह कहती रही है कि इस बिल को शीघ्र से शीघ्र लाना चाहिए। हम इसके साथ ही सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि वह इस बिल को सदन में लेकर आई है। मैं इस बिल के बारे में कहने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर कल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। वह ऑल पार्टी मीटिंग राज्य सभा की ओर से बुलाई गई थी। हमारी पार्टी को इस मीटिंग की सूचना मीडिया के माध्यम से तब मिली जब शाम को इस बारे में टेलीविजन पर बताया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। हमारे मंत्री श्री कमल नाथ जी यहां पर बैठे हैं, इस ऑल पार्टी मीटिंग की जिम्मेदारी इनकी थी या सरकार की तरफ से अन्य जिस किसी की भी जिम्मेदारी थी, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि कृपया वे यह बताएं कि हमारी पार्टी को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाने की सूचना क्यों नहीं दी गई? अगर सूचना नहीं दी गई, तो जब मीडिया वाले यह पूछ रहे थे कि क्या बी.एस.पी. ने बॉयकाट किया है, तो

कम से कम उस समय मीडिया के सामने तो यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि हमने उन्हें इस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया है, इसलिए वे यहां नहीं आए हैं। यह कहा गया कि वे नहीं आए हैं और बॉयकाट के बारे में पूछा गया तो हमें इस बात का अफसोस है कि इस बात का क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था। जब मीडिया के लोगों ने बाहर यह प्रश्न उठाया तब आज हमारी पार्टी की लीडर ने इसका क्लेरिफिकेशन दिया और यह बात भी कही और हमने इस बात का वहां पर विरोध भी किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): सर, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैंने उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग की सूचना क्यों नहीं दी, तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मुझे भी इसकी सूचना लेट मिली थी। यहां पर सीताराम येचुरी जी भी हैं, इनको भी यह सूचना लेट मिली थी। इसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप था। यह सूचना राज्य सभा सेक्रेटेरिएट आफिस के द्वारा जारी की गई थी। मुझे जिस प्रकार की सूचना मिली, यह काफी लेट मिली थी और येचुरी जी को भी लेट मिली थी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is only a communication gap; it is not deliberate.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have made it clear now.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: सर, इससे एक गलत मैसेज जाता है कि एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो कि शुरू से, पहले दिन से ही लोकपाल बिल के लिए अपना ऐसा पक्ष रख रही है कि हम उसके सपोर्ट में हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोकपाल बिल आए, उस पार्टी के बारे में यह प्रचार हो, मीडिया में यह आए कि उन्होंने बायकाट किया, यह सही नहीं था, इसलिए हमने आपके सामने अपनी बात को रखा है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं यह मानता हूं कि यह एक बहुत ही अर्जेन्ट मैटर है, बहुत जरूरी मैटर है, मैं यह भी मानता हूं कि जिस तरीके से हर तरफ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस देश के लिए जरूरी है कि इस तरह का बिल आए, जिससे इस पर कुछ रोकथाम लगे, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते, दस दिन से सदन नहीं चल सका और यह इसलिए नहीं चल सका, क्योंकि हाउस एडजर्न हो जाता था। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आज एक कन्सेन्सस बनाकर, एक निर्णय लेकर इस पर चर्चा हो रही है, वैसे ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसके लिए हमारी पार्टी पहले दिन से ही यहां पर कहती रही है कि मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चे मर रहे हैं और केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए मासूम बच्चों को मरने दे रही है। वहां साठ से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं और रोज़ाना मर भी रहे हैं, उसके बाद

[श्री सतीश चन्द्र मिश्रा]

भी केन्द्र की सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की है। समाजवादी पार्टी, जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसने पहले दिन से ही इसका विरोध किया है कि इस बात की चर्चा न हो। अगर इस पर भी चर्चा होती, इस पर भी एक कन्सेन्सस बनता और एक जिम्मेदारी लेकर निर्णय लिया जाता, तो वे मासूम बच्चे, जो मर गए हैं, शायद उनमें से कुछ की जान बचाई जा सकती थी और जो अभी भी मर रहे हैं, हम उनकी जान बचा सकते थे। लेकिन अफसोस यह है कि किसी भी पार्टी ने, चाहे वह विपक्ष की पार्टियां हों या सत्ता पक्ष की पार्टी हो, किसी ने भी इस पर गंभीरता से नहीं सोचा कि इस विषय पर भी एक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा करके इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यह लोकपाल का बिल है और जो बिल पहले आया था, जिसको लोक सभा से पारित किया गया था और पारित करके यहां पर भेज दिया गया था और साथ ही यहां पर यह इच्छा भी दर्शाई गई थी कि इसको पारित कर दिया जाए, उस संदर्भ में आज यह खुशी की बात है कि माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, जिन्होंने इस बिल को यहां पर रखा है, उन्होंने खुद ही इस बात को मान लिया है कि वह एक अधकचरा और दंतहीन बिल था, जिसको लागू कर देने से कोई फायदा नहीं हो सकता था। वे सारे प्रावधान, जो उन्होंने पहले डाले थे, उनको बदलकर जो मामले सिलेक्ट कमेटी में गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए वे आज यह नया बिल लाए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अन्य सदस्यों, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ-साथ मुझे भी सिलेक्ट कमेटी में शरीक होने का मौका मिला था। क्योंकि मैं भी कमेटी का मैम्बर था और हम लोगों ने उसमें जो सुझाव रखे थे, उनमें से काफी सुझाव मान लिए गए हैं। कुछ सुझाव, जो माननीय लॉ मिनिस्टर साहब ने यहीं पर मान लिए हैं, मैं इसके लिए उनको यहीं पर धन्यवाद देता हूं। इसके साथ-साथ मैं उनको इसके लिए भी खास तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शुरू से ही जो बात रखी गई थी, देश के हालातों को देखते हुए जिस तरह से हर संस्था में ऐसे हाल हो रहे हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स/शैड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए, परंतु हो नहीं रहा है, आपने सिलेक्ट कमेटी में उनका रिप्रेजेन्टेशन रखा है। आपने जो सर्च कमेटी है, उसमें भी उनका रिप्रेजेन्टेशन रखा है। आपने इस व्यवस्था को लोकपाल की कमेटी में भी रखा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से जो बात शुरू से कही जा रही थी, आप उसको स्वीकार करते हुए इसमें उसको लाए हैं। मैं इस बात से बिल्कुल राजी नहीं हूं और इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि इस तरह का कोई प्रोविजन लाने से यह अनकांस्टीट्यूशनल होगा। यह किसी भी प्रकार से अनकांस्टीट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। उसमें जिस तरह का कोई भी रिज़र्वेशन नहीं है, जिस तरह के रिज़र्वेशन की बात कहकर कहा जा रहा है कि अगर आप इसको लाएंगे तो यह अनकांस्टीट्यूशनल होगा। हमारी पार्टी इससे मत नहीं रखती है। मैं यह मानता हूं कि आपने ऐसा करके सही किया है। जो अन्य संस्थाएं हैं, जिनका मैं पहले भी कई बार एग्जैम्पल दे चुका हूं कि जहां पर इस तरह के प्रावधान

नहीं हैं, वहां पर इन क्लास के लोगों के साथ हमेशा से ज्यादती होती आ रही है। वहां पर आज भी उनका रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। चूंकि इस बिल को लॉ मिनिस्टर साहब पेश कर रहे हैं, इसलिए यह उनकी नॉलेज में है कि जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह का कोई सिलेक्शन होता है, तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं रखा है।

आप देख लें, ऐसा प्रोविज़न न होने की वजह से आज आपको पूरे देश में हाई कोर्ट्स में गिनती के लोग मिलेंगे, जो शैड्यूल्ड कास्ट के होंगे as High Court judge और सुप्रीम कोर्ट में भी। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय को ही ले लीजिए। जहां तक शैड्यूल्ड कास्ट के रिप्रिजेंटेशन की बात है, जहां पर 160 की स्ट्रेंग्थ है, वहां पर शैड्यूल्ड कास्ट का रिप्रिजेंटेशन शून्य है। वह इसी वजह से है, क्योंकि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आपको आगे चल कर हाई कोर्ट्स में अप्वायंटमेंट्स के सम्बन्ध में इस तरह का प्रावधान सोचना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, जिससे 25 परसेंट जनता, जो शैड्यूल्ड कास्ट को बिलांग करती है, उसके कुछ रिप्रिजेंटेटिव्स उसकी बात सुनने के लिए, उसकी बात समझने के लिए इन जगहों पर भी कुछ लोग वहां बैठे हों।

इसके साथ-साथ जहां तक बिल का सवाल है, मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा। First I would like to ask the hon. Law Minister whether he is proceeding to press the amendment to clause 9 or not. Kindly see it.

SHRI KAPIL SIBAL: It is only clauses 6, 7 and 8.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Because sub-clause 2 of clause 9 says, "Direct the closure of report before the special court against the public servant..." which, I think, can't be sustainable and it would be *ultra vires* provision. Since you have accepted this, I need not speak much on this.

Besides this, what I would say is that you have done a right thing by accepting the Select Committee's recommendation so far as CBI's empowerment is concerned. You have also agreed today that in case of transfer, you would seek permission from the Lokpal. Therefore, that also strengthens the Bill further.

Looking into all these aspects, so far as my party is concerned, we feel, as was said by the Leader of the Opposition, the other Bill also should be brought जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो हमारी पार्टी ने, जब सुश्री मायावती जी वहां की मुख्य मंत्री थीं, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून बनाया और उसको लागू किया। यह बात दूसरी है कि अब वहां सब खत्म हो गया है। जब वहां कोई कानून की व्यवस्था ही नहीं है, तो गारंटी की बात ही नहीं रह गई। पहले हम लोग वहां पर जनहित गारंटी कानून लाए थे और उसको लागू किया था। मैं खुश होता, अगर समाजवादी पार्टी के सदस्य यहां मौजूद होते

[Shri Satish Chandra Misra]

और इस बात को सुनते, लेकिन वे यहां नहीं है। ...**(व्यवधान)**... मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में कानून लाए थे, आपको भी यहां लाना चाहिए।

मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा। इसके पहले कि मैं अपनी आखिरी बात कहूं, मैं श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, जो सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे, को बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सेलेक्ट कमेटी को चलाया, जिस तरीके से सबको मौका दिया, सबकी बातों को सुन कर और सरकार के दबाव में न आकर उन्होंने जिस तरीके से कानून को ड्राफ्ट किया, इस बात के लिए वे खास तौर से बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): सर, मैं बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, चतुर्वेदी जी कांग्रेस के हैं, लेकिन बढ़िया काम होता है, तो सदन कितनी प्रशंसा करता है और वहीं 2जी पर जेपीसी होती है, क्या काम होता है कि सदन में गतिरोध होता है, यह भी देख लीजिए। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): उसका चेयरमैन भी चतुर्वेदी जी को बना दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: देख लीजिए, यह हिन्दुस्तान का लोकतंत्र है कि सब चतुर्वेदी जी की तारीफ कर रहे हैं और 2 जी की जेपीसी ने ऐसा काम किया कि उसको ओन-अप करने में भी शर्म आती है।

श्री सीताराम येचुरी: आपके कहने का मतलब है कि सत्यव्रत जी को जेपीसी का चेयरमैन बनाना चाहिए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आपका ध्यान क्लॉज़ 63 की तरफ ले जाना चाहूंगा। माननीय लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने यह बात कही कि क्लॉज़ 63 के होने की वजह से आपने लोकायुक्त वाला प्रोवीज़न तो हटा दिया, but, within one year, all the States will create an office of the Lokayukta. I think, except Gujarat, almost everywhere there was a Lokayukta. Now, Gujarat also has a Lokayukta. But, the difficulty is that what was being said is probably not there in the provision that now these States will be bound, the draft would be sent to the States and they would also make an enactment of the same nature. Now it is open to them. They will say or an answer from the States can come that they already have a Lokayukta. In Uttar Pradesh the Lokayukta Act is absolutely different where the tenure is extended every now and then. It is now nine years extension. If you see clause 63 of the Bill it says, "Every State shall establish a body to be known as Lokayukta for the State. If not so established, constituted or appointed by a law made by the State Legislature to deal with the complaints relating to corruption against certain public functionaries within a period of one year from the date of

commencement of the Act...." There is no such provision that the draft which will be passed both by Lok Sabha and Rajya Sabha would be sent to the States and they will adopt this and also modify their Acts. It is not there. *...(Interruptions)...* We know that we had opposed that you cannot exercise the powers of the State Governments. But, at least, you could have said that 'we are sending draft legislation, we are sending a model which may be considered and be accepted or adopted.' But that is wanting here. Therefore, the discretion has been left on the State Governments to decide and frame their own Act or continue with the provisions of the Act in whatever manner they feel or like.

SHRI KAPIL SIBAL: The logic of the Leader of the Opposition is that any such direction issued to any State Government would be violative on the federal structure of the Constitution. Therefore, all that we could do is to have a model law and then persuade the State Governments to accept that model law that would be consistent with the federal structure of the Constitution. But my worry is that while we might have a Lokpal here, we may not have a Lokpal in Gujarat or Madhya Pradesh or some other States. *...(Interruptions)...*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: That is a very sweeping remark. *...(Interruptions)...* Are we seeking a consensus or seeking a disruption? *...(Interruptions)...* Are you being fair? *...(Interruptions)...*

SHRI KAPIL SIBAL: No, no, I said 'and other States'. *...(Interruptions)...*

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश): सर, मध्य प्रदेश में भी लागू है। ...**(व्यवधान)**... उत्तराखंड में लागू नहीं है, आप उसकी बात नहीं कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: हां, वह भी कहना चाहिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: मध्य प्रदेश में लागू है। आप गलत बयान मत दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please. All right. *...(Interruptions)...*

SHRI ARUN JAITLEY: It took 46 years to get a Lokayukta; don't worry. *...(Interruptions)...*

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: What I would say is that in this provision there is nothing like as the Leader of the Opposition had said that probably now you will be sending the model to the States and the States may accept it and

[Shri Satish Chandra Misra]

modify their Acts. There is nothing like this. There is no provision of this nature. Therefore, I would suggest that, at least, after this Bill is passed, the Government must take the initiative of sending the Act as a model to all the States and ask them to adopt this and make a request to consider and adopt this within one year period. If they do not do it, then they will face the wrath of public in their States. There may be people who will force them to make the amendments which amendments have now come into this particular Lokpal Bill after great deliberations in the House, in the Select Committee and again in this House. Therefore, this will be an effective Act for the States also. We should endeavour and take all steps to ensure that the States also adopt this particular Act and accept the provisions in their States by amending the provisions. With this, I would say we are wholeheartedly in support of the Bill and we want that the Bill is passed. हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आपके इस बिल के समर्थन में है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sitaram Yechury. *...(Interruptions)...*

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, आपने आधे घंटे के लंच की बात कही थी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think after his speech, we will have thirty minutes lunch-break. *...(Interruptions)...* After his speech, we will have thirty minutes' lunch-break. *...(Interruptions)...* Already you have said that no lunch-break is needed. *...(Interruptions)...*

श्री सीताराम येचुरी: मैं दस मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री थावर चन्द गहलोत: पहले आपने कहा था कि इनके भाषण के बाद लंच होगा।

श्री उपसभापति: लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि लंच नहीं चाहिए। इसमें मेरी गलती कहां है? आपने कहा कि लंच नहीं चाहिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: आपने आधे घंटे के लंच की बात कही थी।

श्री सीताराम येचुरी: सर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है न?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am only saying that only after his speech. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O' BRIEN: Please give us a lunch-break. *...(Interruptions)...*

SHRI SITARAM YECHURY: Since you have called me, should I start speaking? *...(Interruptions)...* Have you given me the permission to speak? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. You speak. After your speech, there will be half- an-hour break for lunch.

SHRI SITARAM YECHURY: Thank you, Sir, for allowing me to speak. उपसभापति महोदय, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जब पिछली बार भी ठीक दो साल पहले, इसी महीने इस तरह से बहस हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि तीन महान वकीलों के बाद आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, यह ज्यादती है। आज भी मैंने यह सोचा था कि मंत्री नारायणसामी जी आएंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी धर्मपत्नी को आज बहुत ही गम्भीर तरीके से स्ट्रोक हुआ। सदन की ओर से we wish her all the best and a speedy recovery. And, because of this, the hon. Law Minister has been substituted here. On my behalf — and I am sure, everybody will associate — I would like to convey a speedy recovery to Shrimati Narayanasamy.

लेकिन, इस दिक्कत के बावजूद मैं यही कहना चाहूंगा कि दो साल पहले इस चर्चा में मैंने यही कहा था कि पहले मुझे एक बात बताइए। देवानंद साहब का एक गाना मुझे याद आ रहा है कि 'कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना'। ...**(व्यवधान)**... ठीक बारह बजे वह सही साबित हुआ, जो उस समय मैं आपसे पूछ रहा था कि बारह बजे वे क्या करेंगे। आपने जवाब नहीं दिया, बारह बजे स्थगित करके आप उठ गए। आप माने मैं चेयर की बात कर रहा हूं कि आज वह नौबत न आए, निशाना वहीं हो और निगाहें भी वहीं हों। तो आज हम चाहेंगे कि यह बिल पारित हो और इसे पारित होने के लिए मैं सत्यव्रत जी को बधाई देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश): साहब, बीवी और गुलाम फिल्म का गाना भी ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: एक और गाना मुझे याद आ रहा है, जिसके बारे में मैं कहूंगा। अफसोस की बात है कि प्रधान मंत्री महोदय अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने हमें अर्थशास्त्र सिखाया था। वे उसी संस्था में थोड़े दिन अध्यापक थे और में छात्र था। जब वे अर्थशास्त्र सिखा रहे थे, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर दो बातें कहीं कि एक तरफ से डिमांड होती है और दूसरी तरफ से सप्लाई होती है। आज हम लोकपाल की बात कह रहे हैं कि देश के अन्दर भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। तो भ्रष्टाचार की डिमांड के ऊपर रोक लगाएंगे, उसके लिए पूरे प्रावधान आपने बनाए, उसके बारे में में बाद में आउंगा, लेकिन भ्रष्टाचार की सप्लाई के बारे में आप चुप हैं। आप सप्लाई के बारे में क्यों चुप हैं, यह बताइए? हम कह रहे हैं कि आप चुनावी संशोधन लाइए ताकि कॉरपोरेट हाउसेज की फंडिंग पोलिटिकल पार्टीज़ को बंद हो, बिना उस सप्लाई के भ्रष्टाचार होता नहीं है। आप उस सप्लाई के बारे में चुप हैं। जयराम जी ने एक गाने की ओर इशारा किया, तो मुझे देवानंद साहब का एक और गाना याद आ रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: साहब, बीवी और गुलाम वाला...

श्री सीताराम येचुरी: सर, वह गाना यह है कि 'आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे-बैठे जीने का सहारा हो गया'। ...**(व्यवधान)**... अब लीडर आफ दि अपोजिशन कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को मत लाओ और ये सप्लाई साइड को छुएंगे नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि बिना सप्लाई साइड को छुए भ्रष्टाचार पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अब लगभग छियालिस साल हो गए हैं, क्योंकि लगभग छियालिस साल पहले 1968 में मोरारजी देसाई साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ने लोकपाल या Ombudsman का सुझाव दिया था। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि लगभग छियालिस सालों में आठ बार यह विधेयक आ चुका है। इन आठों बार में चार बार हमारी वामपंथी पार्टीज़, मुख्य तौर से हम जिन सरकारों का समर्थन करते रहे हैं, हम उनके पीछे इसे लाने के लिए पड़े थे। 2004 में इनको भी याद होगा, जयराम जी को जरूर याद होगा, कि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्राफ्ट हो रहा था, तब इसके बारे में चर्चा करके लिखवाया गया था। अब बड़ी खुशी की बात है कि आज यह विधेयक आ रहा है, इसके अन्दर सहमति है और यह पारित होगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: लेकिन, आप यह उनसे नहीं करवा सके। ...**(व्यवधान)**... जब तक आप उनके साथ थे, आप उनसे यह नहीं करवा सके। ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: अब आप इसे वास्तविकता कहिए, अफसोस कहिए या जो भी कहिए कि जब तक आंखों ही आंखों में इशारा नहीं होता, आप दोनों के बीच में, इस सदन में कुछ सम्भव नहीं है। इसलिए, अब आंखों ही आंखों में इशारा हो गया है, तो यह सम्भव है और यह अच्छी बात है। ...**(व्यवधान)**... यह अच्छी बात है। हम उनको भी बधाई दे रहे हैं, आपको भी बधाई दे रहे हैं कि आज फाइनली यह लोकपाल विधेयक पारित होगा। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं यही चाहूंगा कि इसके बारे में मैं फिर आऊंगा। सर, मैं एक चीज़ यह कहना चाहूंगा कि चार मुख्य बातें थीं, जिन पर पिछली बार हमने आपत्ति जताई थी। उनमें से तीन बातों को तो स्वीकार किया गया और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं, यह बात मैं सत्यव्रत जी से पहले ही कह चुका हूं। मैं उस समय की एक बात क्वोट करना चाहता हूं, जो मैंने बोला था। I quote, "This unqualified assurance must be given to the country; and, the assurance is that we will enact the Lokpal and the Lokayuktas Bill." हमने लोकायुक्ताज़ पर कहा था कि इसके लिए एक मॉडल बिल भेजिए, जो आज दोनों तरफ से स्वीकार हुआ। अब राज्य सरकारें, राज्य असेम्बलीज़ क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, यह उन पर निर्भर है, लेकिन उन सबसे हमारा आग्रह यही है कि इस मॉडल बिल के आधार पर, संविधान के संघीय ढांचे के आधार पर एक साल के अंदर वे अपने-अपने राज्यों में लोकायुक्त लाएं। आज हम यह आश्वासन देश को देना चाहते हैं और हमारी तरफ से हर राज्य असैम्बली को यह संदेश जाना चाहिए। यह बात तो सही हुई। दूसरी बात यह है कि जहां तक अप्वाइंटमेंट का सवाल है, उसको ब्रॉडन करने की बात हुई, लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के बारे में जो आपत्ति थी,

इनके बारे में कंक्रीट सुझाव आए, जिनको हम स्वीकार करते हैं और हम यह मानते हैं कि यह सही है। इसके आधार पर यह जो बिल लाया गया है, हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। तीसरा, जहां तक सीबीआई का सवाल है, वह पेचीदा है और इसके तहत बहुत सारी बातें हैं, जैसे लोकायुक्त के अंदर जो केसेज़ हैं, उन केसेज़ में लोकायुक्त के अधीन ही सीबीआई काम करेगी। हम चाहेंगे कि इसमें इस तरह का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी पूरी तरह से इसका प्रावधान नहीं आया है, लेकिन कुछ हद तक उसकी ओर आप बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इसको और सुधारा जाए। चूंकि 46 साल के बाद फाइनली यह आ रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में इसके अंदर और सुधार होंगे, इस उम्मीद के साथ हम आज इस बिल का समर्थन करते हैं। But, Sir, I would like to continue quoting what I had said earlier. I quote, Sir, "This unqualified assurance we must give to ourselves..." and like I said earlier, "..We should assess the process of maturation of our democracy a little more..." "... and enact an effective Lokpal and a strong Lokpal which is neither the government draft.... nor the Jan Lokpal draft...." at that point of time. "Let us incorporate all the good points and make a new law that will give us a good stage..... for better accountability, better transparency and better administration." सर, ये तीनों प्वाइंट्स हैं - better accountability, better transparency and better administration. अब फिर मैं उसी सवाल पर वापस आ रहा हूं कि इन तीनों के लिए जो मुख्य बात है, वह यह है कि अगर भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाना है, तो आज यह जरूरी है कि दोनों तरफ यानी डिमांड साइड और सप्लाई साइड से भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने की जरूरत होगी।

अब आपके मुलाजिमों के ऊपर कार्रवाई होगी, आपके राजनेताओं पर कार्रवाई होगी, यह बिल्कुल सही है और यह होना चाहिए, लेकिन जहां से भ्रष्टाचार का यह पैसा आ रहा है, अगर आप उनको ही निगरानी से बाहर रखेंगे, तो यह हमारी समझ से सही नहीं होगा। हमारी पार्टी और हमने क्लॉज (14) पर एक संशोधन मूव किया था, वह इस प्रकार है। I quote, " Any corporate body, its promoters, its officers including Director against whom there is a complaint of corruption in relation to grant of Government licence, lease, contract, agreement or any other action including the conduct of public-private partnership projects or to influence Government -policies through corrupt means." Now, Sir, I would like to know what is the objection to this? We have heard the hon. Leader of the Opposition who said that bringing into the ambit of the Lokpai all the private agencies, etc. etc. would be (1) unmanageable; (2) a gross interference into their democratic rights and their privacy. Fine. I am not saying enter into all the areas of private institutions. But whenever a private body, whether it be a corporate or it be a funded NGO, that enters into any contract with the Government or Government agency, if that contract comes under a cloud

[श्री सीताराम येचुरी]

of having been acquired through corruption or through foul means, are you not going to investigate that? How can you keep that out of your ambit? How can you have a Lokpal that will not investigate a private body that indulges in corruption in order to obtain a licence? How are you keeping that out of your ambit? Sir, this Is a very serious matter. I think if you are really, like we said, promising a better accountablity, better transparency and a better administration, this is a serious lacuna that cannot be allowed to go unnoticed, unattended and unaddressed. इसलिए मैं यह चाहूंगा कि सरकार हमारे इस संशोधन को माने और इस स्पिरिट में माने कि यह संशोधन प्राइवेट कॉरपोरेट्स, प्राइवेट एजेंसीज़ या प्राइवेट बॉडीज़ के काम में कोई एन्क्रोचमेंट नहीं है। वे बेशक संवैधानिक अधिकारों के तहत अपना काम करें। उनका बेशक पूरा अधिकार होगा और उसकी पूरी की पूरी रक्षा यह संसद करेगी और यह कानून करेगा, लेकिन जब वे सरकारी काम के लिए अपने टेंडर देते हैं, उनको जो कांट्रैक्ट मिलता है, अगर उसके ऊपर कोई आरोप है, तो उस आरोप की जांच लोकायुक्त के तहत होनी चाहिए, वरना देश के अंदर eliminating corruption at high places is not possible. इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि 46 सालों के बाद आप फाइनली जब यह क़ानून ला रहे हैं, तो हमारी यह उम्मीद है कि आप आज फिर यह सदन 12 बजे तक नहीं चलाएंगे, बल्कि उससे पहले ही यह पारित करेंगे और अचानक उठकर इस सदन को स्थगित नहीं करेंगे, क्योंकि यह मौका फिर नहीं मिलेगा और इसके लिए हमें फिर दो साल इंतजार करना पड़ेगा। आप इस बार जो करेंगे, उसमें मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप इस प्वाइंट को कंसीडर करें।

अब पीपीपी का सवाल है, जिसे आप पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। मेरा यह मानना है कि it is 'private' use of 'public funds'. यह अलग बात है कि इसे आप मानें या न मानें, लेकिन हमारा यह मानना है, लेकिन जब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, जब पब्लिक आस्पेक्ट को प्राइवेट इस्तेमाल करता है, तो क्या उसके अंदर जांच की जरूरत नहीं है जब उसमें भ्रष्टाचार होता है? आपके प्राइवेट पार्टनर्स, जो एयरपोर्ट्स चला रहे हैं, उनके बारे में सीएजी की रिपोर्ट्स आईं। सीएजी एक संवैधारिक संस्था है और उन्होंने यह कहा कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है। अगर आप उसको इससे बाहर रख रहे हैं, तो आप यह बताइए कि देश को दिए आश्वासन को आप किस प्रकार पूरा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम एक इफेक्टिव लोकपाल लाएंगे, एक इफेक्टिव क़ानून लाएंगे? आपको यह मानना पड़ेगा कि यह इफेक्टिव नहीं है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ क़ानून जरूर है, लेकिन यह इफेक्टिव क़ानून नहीं है। जहां तक पीपीपी का सवाल है, तो वह as good as Government business है, क्योंकि 'public is involved as much as 'private' is involved. आप उसको बाहर कैसे रख रहे हैं?

उपसभापति महोदय, आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मेरे तीन मिनट अभी बाकी हैं। आप मुझे माफ करना, मैं शायद हिन्दी में बोल रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ी... या आपको भूख लग रही है?

MR. CHAIRMAN: It is because there is one more speaker from your party.

श्री सीताराम येचुरी: अब चाहे जो भी बात हो, लेकिन अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, इस पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ बोला जा चुका है और सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट में ऑलरेडी ये बातें आ चुकी हैं, जिसे हम सब लोगों ने माना है। इन सभी संशोधनों को मानते हुए मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि हमने क्लॉज़ 14 के लिए यह जो संशोधन मूव किया है, इसके बारे में आप सोचिए। जैसे विपक्ष के नेता ने कहा कि अपनी चर्चा में अभी दो-तीन घंटे और हैं। जैसे उन्होंने आपको किसी बात के बारे में सोचने के लिए कहा, जिस पर हमारा पूरा समर्थन है। जहां पर आपको भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए element of surprise की जरूरत है, वहां पर यह डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं चल सकता कि उनसे पहले अनुमति मांगें। आपने उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया और उस स्पष्टीकरण के आधार पर हम चल रहे हैं कि उसमें यह रहेगा कि वह element of surprise dilute नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी और foreign-funded NGOs का जो यह सवाल है, इस पर मेरा यही आग्रह है कि छः, सात और आठ ही मूव कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। अगर आप बाकी मूव नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर रिलिजियस संस्थाओं के बारे में जो बात की गई, वह बिल्कुल सही है, लेकिन उसी के साथ-साथ चैरिटेबल संस्थाओं के बारे में भी बात की गई। सर, 'चैरिटेबल' की डेफिनेशन क्या होती है? सर, चैरिटेबल के नाम से इस देश के अंदर बहुत कुछ चलता है। जो चैरिटेबल है, हम मानते हैं कि वह चैरिटेबल है। वह नाम से तो चैरिटेबल होता है, लेकिन उसका काम बहुत कुछ होता है।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Charity for whom?

SHRI SITARAM YECHURY:. Charity, not only for whom, but collected from whom? What is the actual work that they are doing? So, I would seriously urge you to reconsider dropping the 'charitable institution' part of that clause. 'Religious', yes. We have the right to religious freedom. Everybody has the right to propagate his religion, and that is something that the Constitution enjoins and that is something that we shall zealously protect. But, in the name of charitable institutions, don't open a way for charity for corruption. You cannot have corruption-oriented charitable institutions. So, 'charitable institutions' is something on which there has to be a serious re-think. Therefore, I would urge the Government to consider these two important omissions that have been left behind in this Bill after all the deliberations that took place over the last two years. One, please bring into its ambit the corporate sector. Electoral reforms is something that we need urgently, that we should talk about. What the Leader of the Opposition said about the Citizens' Charter is absolutely correct. Along with this Bill should come the

[Shri Sitaram Yechury]

Whistleblowers' Bill and that should be a part of, an accompaniment to, this Bill. That too should happen immediately. I wish the Government proceeds in that direction. But in this Bill, please bring in the corporate sector, the supply side of corruption. I would urge the hon. Prime Minister to continue teaching Economics, where he said, you cannot talk of demand without supply. Please do not talk of demand without supply. Unfortunately, his demand for lunch has made him go and somebody else is supplying his lunch! But without the supply of lunch, his demand for lunch would also not be fulfilled, Sir. That is why, demand cannot be fulfilled unless there is supply.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Therefore, now you may conclude.

SHRI SITARAM YECHURY: Therefore, that supply is what I am asking you to tackle too when you are tackling corruption. Please consider this amendment to Clause 14 that we have moved. Please bring in all the corporates, private sector entities, PPP entities and NGOs in relation to Government projects, in relation to the use of Government funds. They should all be brought under the ambit of the Lokpal. And, please seriously consider eliminating the term 'charitable institutions' from the Clause.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Mr. Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY: Please retain 'religious institutions' but not 'charitable institutions', because that can be grossly misused.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have made it very clear.

श्री सीताराम येचुरी: इसलिए मेरा सरकार से यह आग्रह है कि मेरे इन दोनों पॉइंट्स पर वह पुनर्विचार करे और जैसे कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि अभी आपके पास दो-तीन घंटे और हैं या हो सकता है कि पुराने अनुभव के आधार पर हम 12 बजे तक बहस करें, लेकिन आप के पास जो भी समय है, उस में आप मेरे इन पॉइंट्स को स्वीकार करें। आप प्राइवेट सेक्टर को इस के दायरे में लाएं और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में दोबारा विचार करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, you have made it very clear.

श्री सीताराम येचुरी: तभी हम ने देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जो आश्वासन दिया है, उसे हम पूरा करने का काम कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप को समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. The House is adjourned to re-assemble after thirty minutes.

The House then adjourned for lunch at thirty-eight minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at eleven minutes past two of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukhendu Sekhar Roy - party time twelve minutes.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, I thank you for giving me the chance. Our Party, All-India Trinamool Congress, all along was in favour of a stringent law to wipe out corruption, particularly at the highest level. We are happy to note that this Bill has been introduced after a long tug of war on different issues and after a lapse of four decades of formulation of the original Bill, though in a different form. Sir, this Bill is now set to see the light of the day, but had it been enacted earlier, perhaps, the country would not have witnessed the series of scams like Adarsh Awas, Commonwealth Games, 2G, coalgate, helicopter gate and what not. Therefore, although it is better late#than never, I am sorry for the fact that it was not enacted at the appropriate moment, in any event, Sir, my Party had all along advocated for a Lokayukta institution at the State level and I would like to remind the hon. Members, through you, that in the winter session of the year 2011, we had moved dozens of amendments for deletion of the portion which reflected about the establishment of Lokayukta together with Lokpal in the Central Bill. At that point of time, the Government did not accede to our request, although our demand was supported by majority of the parties and there were, perhaps, no two opinions about the fact that if the Central Act provides for a legislation for Lokayukta in the Central Act, it will affect the federal character of the Constitution. And, I would remind again that on different occasions, this Government has tried to encroach upon the authorities of the State Governments and State institutions in different ways. But Article 1 of the Constitution, if we go through it properly, states that India is a Union of States; it is not a unitary State. Since it is a Union of States, the sacred feature of federalism must be respected. उस समय तो हम सरकार के साथ थे। हम सरकार के साथ थे, इसलिए हमने सरकार से अपील भी की, लेकिन सरकार ने उसे माना नहीं। माना ही नहीं। इधर सुबह से मैं बहुत संगीत सुन रहा हूं, इसलिए मुझे भी मोहम्मद रफी साहब का एक पुराना गीत याद आ गया। उसकी एक-दो लाइनें मैं बोलना चाहता हूं। हमारी पार्टी का मकसद ऐसा था, हमने सोचा और बोला भी कि–

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

"चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर,
तुम्हें रुकना पड़ेगा, मेरी आवाज सुनकर"

लेकिन उन्होंने हमारी आवाज़ को नहीं सुना, वे नहीं रुके, तो हमें एक निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक एक जनविरोधी कानून और निर्णय इस सरकार ने लिए, जो इस देश की आम जनता के खिलाफ थे। इसलिए हमने इनका त्याग किया, हमेशा कि लिए त्याग किया। अब शायद वे रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि "साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना..." खैर, यह तो फिल्मी गीतों की बात हो गई। Now, I would like to endorse this Bill in view of the fact that there is no such provision in this Bill accepting that the State Legislatures would enact appropriate legislation for establishment of Loyayukta at the State level.

Some of the hon. Members were suggesting that there should be a model for that. We are opposed to that, Sir, because already in different States, Lokayukta Act exists. In some of the States, there is Lokayukta Act, and, in some of the States, for example, in my State, there is no such existence of any Lokayukta institution. For the last 34 years, the previous Governments could not form any Lokayukta institution in our State but we are ready to do that. But if there are different types of Lokayukta. legislation in different States, let it be continued, or, if you want uniformity, then, all the existing Acts should be given a go-by. Is it possible in the given situation?

Therefore, I support the Bill. The portion which has been mentioned in clause 63 is alright according to us. Now, I want to put a serious question on clause 3(2) of the Bill although we have not given any amendment this time because we do not want to carry a message to any quarter that we are opposed to this Bill. We are not. From day one, we are in favour of the Lokayukta. From day one, we are in favour of Lokpal but in the manner it was moved, and, in the form, it was tried to be enacted, we opposed to that only.

Now, Sir, if we look at clause 3(2), we will find that there is a provision that Lokpal shall consist of a Chairperson, who is or has been a Chief Justice of India or is or has been a Judge of the Supreme Court. Why all the time are such authorities headed by Judges only? It has become a Judges' breeding ground all the time, be it Central Administrative Tribunal, State Administrative Tribunal, Competition Commission and so on and so forth. All these institutions are headed by Judges. Why should it be a breeding ground for the Judges and retired

Judges? This point crept in my mind again when I went through a reported incident of sexual harassment of a law intern by a former Judge of the Supreme Court. It is a * on the part of that person that he is still holding the post of Chairman of West Bengal Human Rights Commission. * on him, and, * on the institution itself, because people will lose faith in institutions. Therefore, I would suggest the Government, particularly, the hon. Law Minister to think and re-think over the issues in the coming days. I do not know whether he will be there or not, whether this Government will be there or not but whoever will be the Law Minister, whichever Party forms the Government, they should have a serious look into this.

Sir, now, I come to clause 3(4). It says, "The Chairperson or a Member shall not be a Member of Parliament or a Member of the Legislature of any State." Why? Already, sub-clause 2 of clause 3 speaks about who will be the Chairman and who will be the Member. Then, what is the need of saying that an elected representative of the Parliament or the Legislature shall not be either the Chairperson or the Member of the Lokpal? According to me, it is a stigma on the elected representatives of Parliament and Legislatures, and Panchayats and Municipalities also. It has been categorically stated in sub-clause 4 of clause 3 that a Member of Parliament or a Member of Legislature or a member of a Panchayat or Municipality shall not be Chairperson or a Member. It is a stigma-as if all the elected representatives of the people are corrupt, as if all the elected representatives indulge in offences involving moral turpitude. This is not a fact. It is true that the people are losing faith in the political leadership because of the monumental scams one after another. But that does not necessarily mean that all political parties or political leaders are corrupt or involved in offences involving moral turpitude. I would request the hon. Law Minister to remove this portion. There is no need for this because this Bill has already provided for as to who a Chairperson or a Member will be. All the time political leadership is treated as a sacrificial goat and others as holy cows. What is going on in our defence? What is going on in our bureaucracy? What is going on in the fourth estate? We have seen that. Recently, a book has been published titled 'The Siege.' What the book says is that there is a honey bee who is divulging our secret and confidential defence documents to foreign countries. I want to know whether any inquiry has been instituted or is being conducted. There is no rejoinder from the Government

*Expunged as ordered by the Chair.

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

authorities against the author of the book or against the contents of the book. What kind of state are we living in? A foreign author writes a book and says that our defence institutions are doing such anti-national activities and the Government is keeping mum. And here is a Lokpal. Bring any Lokpal or Dharmpal, we don't have any objection to any Lokpal or Dharmpal. But that Lokpal or Dharmpal should also look into such kind of things which are appearing here and people across the world have come to know about the situation prevailing in India.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, kindly give me some more time.

Sir, I would like to point out another clause.. It is clause 45. It talks about undisclosed assets. It says, ".. such assets shall, unless otherwise proved, be presumed to belong to the public servant and shall be presumed to be assets acquired by corrupt means;" Sir, I think the word 'presumed' should be replaced with the word 'treated' because the law does not prescribe any presumption. Law does not prescribe any assumption or presumption. The word shouid not be 'presumed' but it should be 'treated.' I would request the hon. Law Minister to kindly consider whether the word 'presumed' should be replaced with the word 'treated' or not. This is my another humble suggestion.

MR. CHAIRMAN: I am afraid your Party's time is over.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, finally, I would like to thank the Government for accepting our suggestions as far as Lokayukta is concerned. Therefore, we wholeheartedly support this Bill. Thank you, Sir.

श्री शिवानन्द तिवारी: चेयरमैन सर, मैं अपनी जनता दल युनाइटेड पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

MR. CHAIRMAN: Party time is twelve minutes.

श्री शिवानन्द तिवारी: चेयरमैन साहब, मुझे खुशी है कि इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चलेगा, उनकी सम्पत्ति को भी अटैच किया जा सकता है। मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि बिहार में जो हमारी सरकार है, उसने करीब पांच-छ: बरस पहले यह कानून बनाया था और इस कानून के अंतर्गत उसने कई भ्रष्ट पदाधिकारियों की सम्पत्ति को जब्त किया है तथा उससे शैड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए

स्कूल खोला है। इस लोकपाल बिल में उस प्रावधान को भी शामिल किया गया है, इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है।

सभापति महोदय, बिहार में अब तक रंगे हाथ घूस लेते हुए जितने पदाधिकारी पकड़े गए हैं, आजादी के बाद बिहार में कभी भी उतने पदाधिकारी नहीं पकड़े गए थे। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार का सवाल उठता रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसका क्या कारण है? हमें इसीलिए संदेह होता है कि हम जो यह लोकपाल बिल बना रहे हैं, यह काफी बेहतर बिल है। इसमें लेफ्ट की तरफ से सीताराम येचुरी जी ने जो संशोधन दिया है, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाए, तो यह बिल और बेहतर हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके हमें यह शंका होती है कि क्या हम लोकपाल बनाकर भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेंगे? जैसे हमने रेप के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी रेप के केस नहीं रुक रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम कानून न बनाएं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप जो भी कानून बनाना चाहते हैं, जब तक आप उसके लायक वातावरण नहीं बनाएंगे तब तक कानून सफल नहीं होगा। आप देखिए कि देश मे इतनी गैर-बराबरी है कि दुनियाभर में यह माना जा रहा है कि जिस समाज में जितनी ज्यादा गैर-बराबरी होगी, उस समाज में उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार फैलेगा। हमारे समाज में पिछले 15-20 बरसों में कितनी गैर-बरारी बढ़ी है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है, जिससे हम इस गैर-बराबरी को आंक सकें। दूसरी ओर हमारे देश में जिस तरह से rampant ढंग से consumerist culture चलाया जा रहा है, लोगों के मन में लालच पैदा किया जा रहा है। इसी पार्लियामेंट हाउस में लोग करोड़, दो करोड़ की गाड़ियों में आते हैं। जो लोग छोटी गाड़ियों में बैठकर आते हैं, उनके मन में भी यह लालच पैदा होगा कि हम भी किसी तरह से उस बड़ी गाड़ी में बैठें। मनुष्य के अंदर जो कमजोरी है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? यदि आप इसको रोकना चाहते हैं, तो इस तरह की जो गैर-बराबरी है, जब तक आप इसको कम नहीं करेंगे, तब तक आप केवल लोकपाल बनाकर इसको नहीं रोक सकते। यह जो बिल आया है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसके साथ यह भी कहना चाहेंगे कि इसके साथ और कार्यवाहियां भी होनी चाहिए, बगैर उन कार्यवाहियों के किए आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं लगा सकते, चाहे आप कितना भी बड़े से बड़ा कानून बनाएं। इसी लोकपाल में यह प्रावधान है कि लोकपाल होगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी उसका चेयरमैन हो सकता है। आप देखिए कि यहां पर टीएमसी के लोग क्वेश्चन ऑवर से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के खिलाफ हल्ला कर रहे थे कि उनके खिलाफ सेक्सुअल हेरेसमेंट का आरोप लगा था, तो इसमें इसी तरह के लोग रहेंगे? हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार का रोग है, यह चारों तरफ सबको प्रभावित कर रहा है। आपको इस मामले में गंभीरता से सोचना होगा। आप इस देश में जिस तरह से consumerist culture बढ़ा रहे हैं और खासकर 90 के बाद यह और तेजी के साथ बढ़ा है। यह कहा गया है कि यह बिल 46 बरस के बाद आ रहा है। हम तो यह कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद ही लोकपाल बनना चाहिए था। जब 1946 में interim सरकार

[श्री शिवानन्द तिवारी]

बनी थी तभी से यह बन जाना चाहिए था। हमें याद है महात्मा गांधी के पास हर महीने भ्रष्टाचार की शिकायतों की सौ के करीब चिट्ठियां आती थीं। जब 1952 में पहली बार elected सरकार बनी थी, उस समय पंडित नेहरू जी की कैबिनेट में श्री सी.डी. देशमुख साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। उन्होंने पहली दफा यह सवाल उठाया कि हमारे देश में ombudsman बनना चाहिए। उस समय कह दिया गया कि ombudsman बनेगा तो इससे तनाव पैदा होगा। लोग असत्य आरोप लगाएंगे और इससे काम करने की क्षमता प्रभावित होगी, इसलिए वह नहीं बना था, जबकि हम लोगों ने देखा था कि इस देश में, 1948 में ही पहला स्कैंडल, जीप स्कैंडल हुआ था। उस समय ब्रिटेन में जो हाई कमिश्नर थे, उनके खिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आरोप लगाया था। हमने यह भी रिकार्ड में देखा था कि लोक सभा में ये सवाल उठाए गए थे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई। उस पर क्वेशचन हुए, क्वेश्चन ऑर्डर पेपर में भी आया, लेकिन क्वेश्चन गायब हो गया। उस समय भी भ्रष्टाचार का इस तरह का मामला आ रहा था, इसके बावजूद भी हमने उस समय ऑम्बुड्समैन नहीं बनाया, इसलिए हम यह नहीं मानते हैं कि यह चालीस वर्षों का मामला है या छियालिस वर्षों का मामला है। 1962 में ही, जब लाल बहादुर शास्त्री जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पर एक कमेटी बनाई थी, जिसको हम लोग संथानम कमेटी के नाम से जानते हैं। उसी के अनुसार सी.वी.सी. का गठन हुआ था, सैंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्न यही है कि हम भ्रष्टाचार पर कहां से नियंत्रण रख पाए हैं? इसलिए जब भी हम कोई कानून बना रहे हों या कोई कानून बनाना चाहते हों, तो हमको समग्र रूप से देखना चाहिए।

हम सदन में आ रहे थे तो हमसे कुछ लोगों ने कहा कि व्हिसल ब्लोअर के बारे में भी सवाल उठाइए। यह सही बात है। लोकपाल के यहां पर कोई कम्पलेन्ट करता है, शिकायत करता है, अगर उस शिकायत करने वाले पर, जिसके खिलाफ शिकायत होती है, वह व्यक्ति हिंसा की कार्रवाई करता है, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है? हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक कानून बनाया था। उसमें क्या हो रहा है? कई जगह जो लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन का सहारा लेकर भ्रष्टाचार के मामले को उठाना चाहते हैं, उनकी हत्या तक हो रही है। हमारे यहां पर भी और देश भर के कई इलाकों में भी हत्याएं हुई हैं। अभी कुछ दिन पूर्व पुणे के बारे में खबर मिली थी कि वहां पर एक व्यक्ति, जो व्हिसल ब्लोअर का काम करता था, उसकी हत्या हो गई। जब तक आप समग्र रूप से इस सवाल को निपटाने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, तब तक यह मामला निपटने वाला नहीं है। इसलिए हमारा यह कहना है कि आप इन सारी चीजों के बारे में सोचिए। आप अकेले लोकपाल के जरिये भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते हैं। भला बताइए कि भ्रष्टाचार की कितनी घटनाएं हुई हैं? हमें याद है कि यहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री जी वहां बैठे थे और कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थीं। उस समय हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर आपने कुर्सी को दाव पर लगा दिया, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचारी आपकी छाती पर चढ़कर देश को लूट रहे हैं। अगर आपने इस

सवाल पर अपनी कुर्सी को दाव पर लगाया होता, तो मेरे जैसा आदमी आपको माला पहनाता। मैं पूछता हूं कि क्या दिक्कत होती है? जिस समय बगैर लोकपाल के भी कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे और रोज-रोज भ्रष्टाचार की कहानियां छप रही थीं, उस समय हम हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रह गए? आज उसी का नतीजा निकला है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई है। यह भी एक चिंता का विषय है कि हम समय रहते कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर पाते हैं। भ्रष्टाचार के कई मामले आए हैं। अभी सुखेन्दु जी उन घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। जब यह बात सामने आती है, उस समय हम तत्काल उन चीजों के खिलाफ एक्ट नहीं करते हैं और जब पानी नाक के ऊपर चढ़ता है, तो जैसे इमरजेंसी में कुरामिन दिया जाता है और हम उस समय कोई कार्रवाई करते हैं, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। बावजूद इसके कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, हमारी गुजारिश है, हम चाहेंगे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को फैलाने वाली, मजबूत करने वाली और ताकत देने वाली जो परिस्थिति बनी हुई है, उस पर आप किसी तरह से नियंत्रण लगाने की कोशिश करें।

अभी लेफ्ट के लोगों ने पीपीपी मॉडल के बारे में कहा। हालांकि हमने संकेत नहीं दिया है, लेकिन लेफ्ट के लोगों ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में कहा है। आज सरकार सारा काम, अधिकांश काम इसी तरह से करा रही है। उस तरीके में भी भ्रष्टाचार का क्या आलम है, यह हम लोगों ने यहीं दिल्ली के हवाई अड्डे के मामले में सी.ए.जी. की रिपोर्ट में देखा है। अगर आप उसको शामिल नहीं करते हैं, तो आप भ्रष्टाचार से मुकम्मल लड़ाई कैसे लड़ पाइएगा? इसलिए हम चाहेंगे, माननीय कपिल सिब्बल साहब से मेरी गुजारिश होगी कि आप इस अमेंडमेंट को भी शामिल कीजिए। तब हमें लगेगा कि हम लोग सचमुच ईमानदारी के साथ मुकम्मल ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।

उसी तरह से हम कहना चाहेंगे, यद्यपि हम नहीं जानते हैं कि यह कैसे होगा, लेकिन हमारे देश में यह जो गैर-बराबरी है, जब तक आप इस गैर-बराबरी को नहीं रोकिएगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आज एक-एक आदमी के मन में यह भावना बसी है। हमारे यहां पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। दूध किसी का धोबी नहीं है कि वह दूध से धोकर लोगों को साफ करे। आज एक-एक आदमी के मन में है कि जिसको मौका नहीं मिल रहा है, वह ईमानदार है और जिसको मौका मिल रहा है, वह कहीं भी मौके को छोड़ता नहीं है। यह हालत हो गई है।

हम लोगों ने पंचायती कानून बनाया। पता नहीं हमारे देश में समय पर काम करने की आदत है ही नहीं। जो पंचायती कानून राजीव गांधी जी के समय में आया, अगर वह पंचायती कानून देश की आजादी के तुरंत बाद आ गया होता, जिस समय देश पर गांधी का प्रभाव था, नेहरू का प्रभाव था, ईमानदारी और सच्चाई थी, तो देश की दिशा दूसरी हो सकती थी। उसी तरह से जो लोकपाल बिल आज आया है, जब सी.डी. देशमुख साहब ने ओम्बुड्समैन का सवाल उठाया था, अगर उस समय ओम्बुड्समैन बन गया होता, लोकपाल बन

[श्री शिवानन्द तिवारी]

गया होता, तो हम भ्रष्टाचार का जो आकार और रूप देख रहे हैं, वह नहीं दिखाई देता। क्या आपका कोई क्षेत्र है? देश की डिफेंस मिनिस्ट्री, इतनी नाजुक, इतनी संवेदनशील मिनिस्ट्री, उसमें क्या हो रहा है, यह कहने की बात है। यह हालत है हमारी? इसलिए हम गुजारिश करेंगे, बावजूद इसके कि हमको बहुत शंका है कि लोकपाल बिल के जरिए हम भ्रष्टाचार पर कारगर ढंग से अंकुश लगा पाएंगे, हम अपनी पार्टी की और से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन साथ-साथ यह भी गुजारिश करते हैं, हमको बिहार में इस बात का तजुर्बा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बावजूद भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, उसी तजुर्बे के आधार पर हम आपको यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के समर्थन में जो वातावरण बना हुआ है, जिस वातावरण को बढ़ाने के लिए, हमने विकास की जो नीति बनाई है, विकास का जो मॉडल बनाया है, जिस ढंग से हम कंज्यूमरिस्ट कल्चर चला रहे हैं, जब तक आप उस पर रोक नहीं लगाइएगा, जब तक आप गैर-बराबरी को कम नहीं कीजिएगा, तब तक भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाना मुश्किल होगा।

इसी के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए और कपिल सिब्बल साहब से गुजारिश करते हुए कि यह जो पीपीपी मॉडल का मामला है, इसको भी उसमें शामिल कीजिए, ताकि आप ज्यादा असरकारी लोकपाल दे सकें, मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Dr. Maitreyan, your party has ten minutes.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): My steps are measured, Sir.

Sir, on behalf of my party, AIADMK and my party supremo and Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, I rise to support the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011. The present Lokpal Bill has come a long way since 2011, at least. The Rajya Saha by taking this Bill today has been successful in removing the taint it has acquired since the black day of 29th December, 2011. In fact, on that day, the combined Opposition had moved a number of amendments which would have strengthened the Lokpal. But sensing that the Government will be defeated on many of the amendments, the Government on that day got the House adjourned. It is to the credit of their own party member, Shri Satyavrat Chaturvedi, Convenor of the Select Committee, who has got many of the amendments which the opposition had moved incorporated into the Report of the Select Committee. Today, because of that it is seeing the light of the day. In fact, I would like to say that the Minister patted on his own back and also on the back of all of us by saying that at last we have reached a consensus. I would like to point out to Shri Kapil Sibal that a consensus was indeed reached on 23rd November, 2012 itself

when the Select Committee submitted its Report to the Parliament. It is the insincerity of the UPA Government which ignored the Report of the Select Committee for more than one year. In fact, we had two Sessions in-between, and now we are in the last week of the third Session. For more than a year the UPA Government slept over this Report. But because of the result of the recent Assembly elections suddenly they find an urge to bring the Lokpal Bill in the last week of this Session. However, it is better late than never. In fact, the new Lokpal, once he assumes the charge in a couple of months from now, will have his hands full because the UPA Government is gifting him with a plethora of corruption cases, starting right from the coalgate, involving the Prime Minister himself, down to the last Minister of the UPA Cabinet. So, the new Lokpal will have his hands full. Probably, his entire term of five years or so will be spent only on the UPA-II. To that extent, at least, they have now done a sort of remedial measures for their own misdeeds. I would like to mention a few points. In fact, in my dissent note in the Select Committee, I had mentioned certain factors. We, on behalf of the AIADMK, stand firm in our views and even though today those views may or may not have been taken into account In the present Bill, I would like to reiterate them. Clause 14 of the Bilhdeals with the jurisdiction of the Lokpal. As per clause 14 (1), the Prime Minister falls under the jurisdiction of the Lokpal. My party is of the strong view that the Lokpal Bill should exclude the Prime Minister since the Prime Minister is already covered under the Prevention of Corruption Act, and any misconduct by the Prime Minister can be investigated otherwise. The functioning of the Lokpal, inclusive of the Prime Minister, will pave the way for a parallel Government which would undermine the authority of the office of the Prime Minister. Even today, we hold this view even though the Government may, probably, buckle under pressure from various quarters. Similarly, our firm view is that, in consonance with our view that the Prime Minister should be kept out of the Lokpal, for the very same reason, the Chief Minister of any State should also be kept out of the purview of the State Lokayukta. I want to reiterate here today if and when a Lokayukta Bill is enacted in the Tamil Nadu Assembly, we will see to it that the Chief Minister of the State is not included in the Lokayukta Act. I had also mentioned in my dissent note about the establishment of the Lokayukta, since article 246 of the Constitution of India provides both for Parliament and State Legislatures to make laws with respect to any matter enumerated in List III of the Seventh Schedule of the Constitution. Also, federalism is a part of the basic

[Dr. V. Maitreyan]

structure of the Constitution and is inviolable. Hence the choice of constituting the Lokayukta should be left to the State Government and the State Government may enact legislation if it deems it necessary. I still reiterate our view that it should not be made mandatory by this present Act, but it should be left to the discretion of State Legislatures as to whether they want a Lokayukta or not.

Finally, before I conclude, I would like to urge upon the Law Minister, who has been overzealous in creating a consensus on this important Bill, that he shows the same zeal in getting the consensus around for the Women's Reservation Bill as well as the Bill for Reservation in Promotions for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. For those two Bills also, he should create a similar consensus, bring them and pass them in the Lok Sabha in this Session itself. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Dr. K. P. Ramalingam. Your party's time is eight minutes.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): *

Respected Chairman, This Bill is a very important Bill. It is of historic importance. After a long gap, this Bill has been taken up for consideration. As far as my party DMK is concerned, we wholeheartedly support his Bill. There are strong reasons behind our support to this Bill. When our leader Dr. Kalaignar was the Chief Minister of Tamil Nadu in the year 1973, he passed the Prevention of Corruption Act, in the legislative assembly of Tamil Nadu. He brought the Chief Minister of the State under the ambit of that Bill.

In the history of Indian subcontinent, forty years ago, that is in the year 1973, then State Government of Tamil Nadu passed a legislation under which the Chief Minister of a state can be enquired. The Act was implemented. We are proud of passing such an Act and the credit goes to our leader Dr. Kalaignar. Due to the outstanding efforts of our leader Dr. Kalaignar, Tamil Nadu has shown the way to the entire India through this Bill. With that honour, I stand in this House to express my opinion.

Though this decision has been taken after a long time, it is a very remarkable decision. All the parties have expressed their views through the Select Committee. Many amendments have been incorporated into the Bill. It is a welcome measure.

*English translation of Original speech made in Tamil.

At the same time, I would like to point out some of my opinions on this issue. Power has to be exercised only by those institutions whose members are elected by people. India is a democratic country. In a democratic set up, the institutions whose members are elected by people should have the power. No nominated institution should have the power over democratic institutions. The members in such nominated institutions, with the pride of being intellectuals, will try to exercise their power over democratic institutions. Then, it will erode the values of democracy. This issue has to be handled cautiously.

India is a democratic country having population of more than 100 crore. If we do not take efforts to protect our democracy, it is like casting aspersions on our Parliament, our legislative assemblies and other elected bodies. It will affect the entire country. Many criticisms are hurled by those people who do not involve themselves in democratic institutions. Many of those critics do not enter politics. If they contest in elections, they do not get people's votes. Such people are criticizing the members elected by people. They cast aspersions on public functionaries. It will set a bad example. If such people are allowed to criticize the Government functionaries, people will lose their faith in the concept of democracy. Aspersions are cast on politicians utilizing the media. They erode the image of all Government institutions. They criticize all public functionaries. They create an impression that none is perfect in politics and no Government institution is perfect.

This Bill has given the authority to C.B.I, to enquire politicians. I would like to register some of my views with regard to C.B.I. Can we accept that C.B.I is functioning in an efficient manner? We can not accept it. Why? What is the reason? During the last ten years, irrespective of the Government in power, many cases have been filed by C.B.I. Many of those cases have been enquired by court. Among those cases, only five percent of the cases have been given conviction. The accused have been acquitted in more than 90 per cent of the cases. That is, many of the people who have been imprisoned during the period of enquiry, are innocent people. Moreover, the media knows most of the activities of C.B.I. Before the C.B.I, reaches a place for enquiry, media reaches there. Who informs the media about C.B.I.'s activities? It seems that CBI rings up the media before going for an enquiry.

Corrupt persons have to be brought to the book. We have no second opinion of the issue. Corruption has to be eliminated. But, at the same time, innocent people should not be affected.

[Dr. K.P. Ramalingam]

My friend Dr. Maitreyan said that Chief Ministers should not be brought under the purview of Lokayukta. That is the view of his party. That is not the view of Tamil Nadu. As far as we are concerned, we support the view that the Chief Minister has to be brought under the purview of this Bill. We have implemented it forty years ago. The Prime Minister, Chief Ministers and other ministers can be enquired under this Bill. But at the same time, care has to be taken that the law should not be misused. Moreover, this institution should not be inimical to democratic institutions.

In the Lokpal and in Lokayuktas, fifty per cent of the members are from Judiciary and the rest are from other discipline. Even among them, I would like to express that majority of them have to be elected by the people. Democratically elected members should have a superior role. Our friend, Mr. Sitaram Yechury from CPI (M) said that religious institutions and charitable institutions should not be exempted from this Bill. We support this view also. But we reiterate that care has to be taken not to misuse this provision also.

Nowadays we read so many news items about saints, who have involved in criminal activities. Some charitable trusts are misusing their money. They should also be enquired under this Bill. But, it does not mean that all saints are criminals.

Sir, in brief, the law should not be misused. Democracy has to be protected. This is our view. I support this Bill. Corruption has to be eliminated. We give more importance to this Bill. Because we have created history forty years ago, by passing a remarkable legislation with the same objective. Our party welcome this Bill. We welcome this Bill with the guidance of our leader Dr. Kalaignar. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Baishnab Parida. Your party has got eight minutes.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Sir, I express my thanks for allowing me to present the views of my party on this historic Bill *i.e.*, the Lokpal and Lokayuktas Bill.

Sir, after long years of wait, struggle by people, many political parties, now, you have arrived at to pass this long expected Bill. Now, I am observing one thing. Many parties, especially the ruling party and its leaders inside this House

and outside, are trying to take the credit for passing this Bill. But, I think, had this wisdom dawn in the minds of leaders of the ruling party and its Government, the present Lokpal Bill would have been passed on 29th December, 2012, with the present amendments. If, on that historic day, this august House could pass this Bill, there would not be a country-wide upsurge of anger and movements which reflected in the recent State elections and resulted in ignominious defeat of the ruling party. That must be kept in mind. It is not voluntarily this Bill has come to this House.

Sir, once John F. Kennedy said this famous sentence. He said, "The victory has many parents, but defeat is an orphan." Now, when the victory comes, many are claiming the 'parenthood.' They want to take the credit and nobody wants to be the 'orphan.' So, Sir, we must also keep in mind that whenever any change or reform comes before this House or in the Lower House in the form of a Bill, it was only after a long years of struggle.

We have the Right to Information and many other legislation. For that, they mobilized millions of people, social organizations, even the Press, and they must be given the credit. That strengthens the democratic structure of our society. Vigilance is the price for democracy and we must encourage and acknowledge the role of the masses. I remember, when Anna Hazare and his team were demonstrating outside the Parliament House and on the streets, some of our friends were jeering at them. I agree that it is the Parliament which has the supreme power to enact laws, but it is the people of India who have given this right to the Parliament. We must reflect the aspirations of the people. The reality of our society must be reflected here, in Parliament.

Sir, corruption has engulfed the entire society, our entire political system, our democratic system and our party system. Without money from corporate houses, without money from illegal sources, we are not able to contest elections. That is the reality that this country is facing. Now, we must think and we must change all this. I must thank the Standing Committee for having presented their recommendations in such a way that we have arrived at a consensus. I appreciate the work done by the Chairman of the Standing Committee, Shri Satyavrat Chaturvedi and, sometimes, I wonder, जब रूलिंग पार्टी में ऐसे लोग हैं, तो वे रूलिंग पार्टी को अच्छे सुझाव क्यों नहीं देते हैं; why are they not giving the right advice to the Ruling Party to move in the right direction? I really wonder about that at times.

[Shri Baishnab Parida]

3.00 P.M.

of course, we have already arrived at a consensus to pass this Bill. We have agreed on all the amendments that the Government has brought before the House.

There is another thing, Sir. I feel it would be a milestone in our quest for an institutional mechanism to combat corruption. Definitely, it is a great weapon in the hands of our people, our political parties and other institutions. But the question is, how far would we be able to utilize this mechanism in an efficient and honest manner? We have passed so many laws. But, we must introspect on one thing: with how much efficiency and honesty have we implemented all those laws?' We did pass laws to combat corruption. But I feel that we did not implement those laws properly. If this historic law also meets that fate, then, who would save this country? So, it is the bounden duty of all the political parties, the Government, all of us and of all the people of this country, to see to it that this Bill is implemented in letter and spirit. I do not wish to go into the amendments that we have proposed. One of them is that no officer should be transferred when the process of investigation is on; that can be done only by the Lokpal. No Government can interfere in this. This is a very good provision. Now, the parrot is out of its cage. Then, the process of selection of the Lokpal, the collegium and other things that we have been talking about here and outside have been considered. I congratulate the hon. Minister for this. The Minister has paid adequate attention to the proposal. If we all work together in solving the very significant and important problems facing us, then, our country can really surge ahead.

We can compete with any advanced country of the world. We have that talent, we have that background and we have that spirit. I want the whole House to rise to the occasion on each and every occasion, on every national problem. It will help us and our country in advancing further in solving the problems.

With these words, I thank you and support this Bill's passage unanimously.

DR. YOGENDRA P. TRIVEDI (Maharashtra): Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this historic Bill, as the Law Minister mentioned in the beginning. So much has been said about corruption. There are some independent organizations world around who are ranking the country according to corruption. We feel sad when India is ranked as 138th in the realm of

corruption, much below even some of the African countries. Much has been said that corruption is like malignant cancer, it eats in the bones and marrows of our life and that it has to be eliminated. So, I will not dilate at length on that. But, if you want to root out corruption on which we are all agreeable, please bear in mind the example of China before us. It must be expeditious, it must be quick, and it must be strict. China should be an example. We had earlier the Benami Transactions (Abolition) Act. But, for long years, we didn't frame the rules. The Central Vigilance Commissioner who was in-charge of administering the Act had said, "It is a toothless tiger." Then, we have the Prevention of Corruption Act, which is also very much there; but, it takes years before a corrupt person is convicted. So many officers in various Departments like Revenue, Excise, Customs, Income-Tax are being tried over the years; the proceedings are going on; yet, they are moving freely. And, after years, they go scot-free and they become experts in their fields. The assessees feel, "This man, even though charged with corruption is going scot-free; he knows the intricacies of the Department, so we must go to him and consult." So, I think, up till now, we have not succeeded much.

Sir, this is an effort which is very brilliantly and valiantly brought about by the Law Minister. I don't want to dilate on other things but I have got two positive suggestions. The first is relating to Amendment Number 6 where you have said that before an investigation takes place, the man should be asked if there is a *prima facie* case against him. This is something which I don't understand. These proceedings are criminal or quasi-criminal, at least in character. To tell an accused why he should not be prosecuted is like giving him a warning, a handle to deal with all the evidence which is lying around. You may be trying to gather the documents; you may be trying to call witnesses; you may be thinking of a search at his place; you may be trying to investigate his undisclosed assets either here or abroad. But, you give him an opportunity to destroy evidence by asking "Why should we not investigate against you?" It is not heard about.

You have got Amendment Number 8 which says that before one is prosecuted, he should be given a chance to prove whether there is a *prima facie* case against him or not. I can understand. But what about asking him before investigation? These are criminal proceedings. If there is any infirmity anywhere, the benefit of doubt will go to the accused. If he can establish that you have called some witness or collected some document without giving him an opportunity,

[Dr. Yogendra P. Trivedi]

he will say, "The entire proceedings are bad and I should be allowed to go scot-free. Because, the benefit of doubt should come to me, I am an accused." The investigation must be done confidentially. You better say that gathering evidence, gathering documents, calling the witnesses will not be considered to be investigation. Investigation is something when he himself is being investigated. But when you are collecting documents, then, you can't say that you must be given, first of all, an opportunity to say that there is a *prima facie* case against you. You are trying to find out a *prima facie* case, and how can you, at this stage, give him an opportunity? I think there is something which should be done. I can imagine Amendment No. 8, which is very necessary; before he is prosecuted, he must be given an opportunity. But if, before the investigation, you tell him that you are investigating against him, he can destroy all the evidence; especially if he has assets abroad, from Switzerland, he can shift it to Malta, Panama or Bahamas, and you will find nothing. So, there is no question of giving an opportunity before investigation or gathering the evidence.

The second suggestion of mine is, you have said that this law is primarily aimed at Government funds. The public money is also Government's money to a certain extent. It ultimately flows in the pockets of the Government in the form of taxes. Supposing there is a huge malpractice in some clubs, in some social clubs, in some NGOs; why should not Lokpal have the ability to go and investigate into it? If the public is being fooled, if the public is being cheated, moneys have been eaten away by somebody, can't the Lokpal go into it, instead of saying, it is not Government's funds, you mend your own ways? The Lokpal should have the ability. You might say here that you will keep a certain limit. If the fraud is to the extent of more than a million rupees, then only the Lokpal will investigate into it, not the small things. But, if there is a huge fraud, and public funds are being looted, then the Lokpal should be able to investigate it. The people should be able to approach the Lokpal. You can't just say that it is not Government funds and it is only public funds. Public funds are ultimately Government funds. The public should not be distinguished from the Government in such a manner. So, Sir, these are my two positive suggestions; firstly, about your Amendment No.6, and the second is about your excluding the NGOs totally. You might put a limit that small, small things will not be included in it. But if there is a fraud to the extent of more than a million rupees, the Lokpal should have the ability to go into it, and try to punish the people very quickly because these are swift measures, these are quick

measures. I am saying that let us bear in our mind the example of China and deal with the issue in the same manner. Thank you very much, Sir, with these remarks we support this Bill.

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Hon. Chairman, Sir, I rise to support this Bill as a citizen of this country. I wish to compliment you, Sir, because we have almost forgotten what a normal debate in this House should be. That debate and discussions have been restored is a great source of reassurance. This Lokpal Bill has been pending for a very long time; it is historical. Finally, fulsome but inconclusive debate took place in 2012. As a consequence of that, a decision was taken to set up a Select Committee of the Rajya Sabha, of which I had the privilege of being a Member. So, I watched the deliberations and participated in these deliberations under the Chairmanship of Shri Satyavrat Chaturvedi and the presence of the Leader of the Opposition, Shri Arun Jaitley, that how the same colleagues of ours from this House and all of us can rise above partisan politics and try to reach a consensus, which might be a compromise, but which is better than no consensus at all. We have recognised the national importance and the priority of the Lokpal Bill. The Right to Information Act had already opened the door to transparency and accountability. The Lokpal Bill now finally fulfills India's desire to be a truly open society. However, I have a word of caution. The role of the State must neither be vetoed nor be undermined in the name of the Lokpal or the Right to Information Act. The role of the State must not be eroded because if extra-constitutional bodies usurp that role and try to rule this country, not as representatives of the people of this nation but as extra-constitutional bodies, it will be disasterous.

Openness must not be permitted to become an excuse to hijack in the name of neo-federalism and in defiance of the Constitution of India. I welcome the march of social reform but with a word of caution. Mr. Minister, I wish to caution you, through the Chairman, against chaos and harassment in society because we can very easily descend to a jungle state and we have to be guard against it. With this word of caution, Sir, a lot of amendments have come. We are holding a debate in this august House after a long interval. It is an occasion to be celebrated. I congratulate you, Mr. Chairman, for presiding over both the chaos and the order in this House and we have been mute watchers, but we have learnt a lot for which I thank you and all the hon. Members across the House. Thank you, Mr. Chairman.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Thank you, Sir. I rise today to speak in support of this historic legislation, which our nation deserves, our nation has waited for, and which it now demands as their right. It is a legislation which is undoubtedly the first serious attempt at directly countering the menace of corruption that has made the Indian nation weak and hollow at its core. To quote the Leader of the Opposition, I quote, "We need to restore faith amongst our people in public life and create an effective mechanism to deal with corruption."

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Sir, Parliament, parliamentarians and indeed political parties have travelled a long distance from those early days of 2011 when the popular people's Jan Lokpal movement was treated with scorn and scepticism. The most often used phrase in those days and I heard it on many occasions was that this was 'temporary' or indeed another choice of word was 'an elitist' phenomenon. The last two years have proved that the desire amongst all Indians for a change in our governance is a sustained and unrelenting one, and our response to them as Parliament has been belated, but worth congratulating.

Sir, I had introduced in the face of such scepticism a Private Member Bill, the Jan Lokpal Bill, 2011, in August, 2011. I too faced some derision and scorn from media and friends alike. But I am proud of the stand that I took and prouder still of the stand of my fellow Members of this House on the near unanimous view of this House in debating and passing of this historical legislation. It is this House that stopped the passage of the weak Bill that was passed in the other House and that further strengthens the prestige of this House and indeed its Members.

Sir, I will not discuss details of the Bill since the hon. Leader of the Opposition and other Members have done so. But there are some who argue that this does not go far enough and have unfortunately characterised it as 'Jokepal'. To them, I say this, please appreciate how far we have come. This Bill lays the basis of a strong institution. Institutions must be given time to take birth, grow and evolve to the needs of the times. To them, and indeed, civil society and media at large, I also say this, please now move the spotlight to the setting up and functioning of this institution of Lokpal. This is just the beginning of a process of reforms and changes in governance that our country is embarking on for the first time since Independence. Instead of being cynical, I would request them to stay

engaged and focussed on the many steps required in the coming months and years.

Sir, while ending, let me say this that this is a historic day. This is probably the single most important legislation that we are passing post-Independence on the issue of governance. Let us understand that we are giving the nation and our people what it seeks from us. Future and current generations will thank us for our near unanimous support for this Bill and our efforts at cleaning up governance. Sir, thank you and Jai Hind.

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया। सबसे पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। संसद के बारे में पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा रही है कि संसद में गंभीर बहस नहीं होती, संसद में चर्चा नहीं होती, पर आज हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि इसी संसद ने तमाम विरोध, तमाम मतभेद, तमाम विचारधाराओं के टकराव के बावजूद देश को यह बताया कि जब महत्वपूर्ण मसले आते हैं, तो संसद मुखरता से बहस करती है। जहां आवश्यकता होती है, समझदारी बनाती है और अगर देश की अपेक्षाओं के अनुरूप उस मामले पर राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता होती है, तो वैसा आचरण करके भी दिखाती है।

माननीय उपसभापति जी, आज जब हम लोकपाल बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें अपने अंदर थोड़ा झांककर देखना पड़ेगा कि आज देश में ऐसी स्थिति क्यों आई है? यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों को आज राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था से इतनी नफरत क्यों हो गई है? मुझे मालूम है कि देश की राजनीति में ईमानदार लोग भी हैं। देश की राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं मानते, बल्कि राजनीति को स्वार्थ-सेवा का माध्यम मानते हैं। आज जब देश के सामने एक नई अपेक्षा आई है, तो हमें उस अपेक्षा के अनुरूप खरा उतरना पड़ेगा। यह बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि यह वही संसद है, जिसने अपने लगभग एक दर्जन सांसदों को उनकी सदस्यता से एक्सपेल किया, जब एक स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने कुछ हज़ार रुपए लेकर सवाल पूछने का काम किया था। उसमें कई पार्टियों के सांसद थे, लेकिन सभी पार्टियां खड़ी हुई कि जो गलत है, वह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद ये सवाल बार-बार उठते थे। स्वाभाविक है, उसके कारण थे। देश में एक तरफ बदलाव हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में युवक लोग हैं, जिनके मन में नई अपेक्षाएं हैं, जो यह मानते हैं कि India deserves better, अच्छा होना चाहिए और दूसरी तरफ ऐसे शर्मनाक भ्रष्टाचार के घोटाले होते हैं, जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि ऐसी बनती है कि लगता है कि India is only a country of scams. इन दोनों में अंतर्विरोध था। आज स्कैम्स के बारे में चर्चा करने का अवसर नहीं है, लेकिन एक सवाल उठाने की इच्छा ज़रूर होती है कि जहां एक

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

तरफ लाखों-करोड़ों के घोटालों की बात हो रही है, वहीं ज़ीरो लॉस की भी चर्चा हो रही है। देश सवाल पूछ रहा है, यह क्या हो रहा है? एक तरफ सी.बी.आई. उन घोटालों में चार्जशीट कर रही है, हज़ारों करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, लोग जेल जा रहे हैं और वहीं पर कहा जा रहा है कि 'The loss is zero'. कई संस्थाएं अपने क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही हैं। यह सारी बहस हमने देखी है, अनास्था का माहौल इसीलिए पैदा हुआ है। आज आपने सुधार किए, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय उपसभापति जी, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जो सेलेक्ट कमेटी ने किया, वह दिसंबर, 2011 में आप कर सकते थे। हम तो आपके साथ खड़े थे। बी.जे.पी. हमेशा से इस बात को कह रही थी कि लोकपाल बिल बनना चाहिए, प्रभावी लोकपाल बिल बनना चाहिए, तो इसके लिए जो आज सेलेक्ट कमेटी का हम इतना साधुवाद कर रहे हैं, चाहे चतुर्वेदी जी का, अरुण जेटली जी का, सतीश चन्द्र मिश्रा जी का या बाकी मेम्बर्स का, तो वह काम आपने खुद कर लिया होता। उस समय तो लोक सभा में हुआ कि नहीं, बिल पारित करना है, इसी स्वरूप में पारित करना है। लोक सभा में एक कमोशन भी हुआ, हमें मालूम है, बहुत लोगों ने कहा कि मामला संवैधानिक है, तो भले ही आप देर से सुधरे, लेकिन देश को लगभग दो वर्षों तक जो प्रतीक्षा करनी पड़ी, यह काम 2011 के दिसम्बर में ही हो जाता, यह बात कहनी आज बहुत ज़रूरी है। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र यहां नहीं हैं, आज वे भी होते, तो अच्छा होता। उनकी आपत्ति है कि हम कानून में एक ऐसा अधिकार दे रहे हैं, जिससे काम करना मुश्किल हो जाएगा। उनके इस प्रश्न का मैं बहुत विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा कि काम करने में कठिनाई तो The Prevention of Corruption Act से भी आ जाती है, तो क्या वह कानून नहीं होना चाहिए? यह कानून 1947 में आया था। आपको मालूम है कि प्रीवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट को हमने 1988 में और कड़ा किया क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार होता है तो देश की, लोकतंत्र की, भारत के संविधान की और भारत की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उनका उत्तर देंगे। यह बहुत जरूरी भी है। अपने समाजवादी पार्टी के मित्रों के सवालों के जवाब में मुझे एक बात और कहनी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पब्लिक इंटरस्ट लिटीगेशन आया। अरुण जेटली जी बैठे हैं, वे देश के बहुत बड़े वकील हैं, सतीश चन्द्र मिश्रा जी हैं, डा. अभिषेक मनु सिंघवी बैठे हैं, कई वकील मित्र बैठे हैं। विधि और न्याय मंत्री जी भी तो देश के बहुत बड़े वकील रहे हैं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: आप कौन से कम हैं? आप सबसे बड़े वकील हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय विधि और न्याय मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी वकालत दुबारा शुरू करने का समय बहुत जल्दी आने वाला है। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं क्योंकि दस साल आपको वकालत छोड़े हो भी गए हैं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): आजकल आप बड़ी अच्छी वकालत कर रहे हैं। हम तो मानेंगे कि आपको दस साल और वकालत करनी पड़े।

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह तो जनता तय करने वाली है। छोड़ दीजिए, जनता अपना संकेत दे रही है।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITELY): We will be luckier than him. *...(Interruptions)...* He who practices will be the luckiest.

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मैं यह बताना चाह रहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन आया – गरीबों के लिए, अपेक्षितों के लिए। लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि some people are trying to convert Public Interest Litigation into *Paisa* Interest Litigation. सुप्रीम कोर्ट ने कॉशन किया तो आज इसका यह मतलब निकालना कि पीआईएल इंस्टीट्यूशन अपने आपमें गलत है, उचित नहीं होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ईमानदारी से काम करेगा, उसको डरने की क्या जरूरत है? जैसा माननीय नेता, विपक्ष ने कहा, काम ईमानदारी से करना चाहिए, देश के हित में करना चाहिए और अच्छे प्रशासक को किसी गलत आदेश के लिए न करना भी सीखना चाहिए। इस देश में इतने बड़े भ्रष्टाचार इसलिए हुए और होते रहे हैं कि बहुत से प्रशासक न करना नहीं सीखे हैं। आज हम देख रहे हैं, बहुत से प्रशासक निर्दोष फंसे हुए हैं क्योंकि शायद अपने राजनैतिक आकाओं के गलत आदेश को वे न नहीं कर सके। शायद लोकपाल बिल हमें प्रेरित करेगा कि हम वह परिवर्तन करें। आज जब हम लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं तो बहुत विनम्रता के साथ जहां हमें देश की अपेक्षाओं की चर्चा करनी है, वहीं मैं बहुत विनम्रता के साथ अन्ना हजारे जी का भी अभिनन्दन करना चाहूंगा। साठ साल से एक प्रक्रिया चल रही थी। अन्ना हजारे जी ने अपने आंदोलन, अपने अनशन और अपने आग्रह से हमें इस बात के लिए प्रेरित अवश्य किया कि लोकपाल को जल्दी पारित करना चाहिए। उनके कई साथी थे। आज कौन कहां है, कैसे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कई उनके कंधों के नीचे बढ़े, उनके कंधों के ऊपर चढ़े और राजनीति की बैसाखी पर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। आज अन्ना जी और उनके अनुयायियों में कैसा वार्तालाप हो रहा है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर मैं बहुत गंभीरता से महसूस करता हूं कि हमें अन्ना हजारे के आग्रह, अन्ना हजारे के अभियान और अन्ना हजारे ने देश के सामने जो प्रमाणिकता रखी, उसका अभिनंदन करना चाहिए। आज यह संसद, जब लोकपाल को एक समन्वय, समझदारी और सद्भाव के साथ पास कर रही है तो मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा- मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़ंस पर आऊंगा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं - कि हमें व्हिसल ब्लोअर बिल को भी जल्दी से पारित करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए व्हिसल ब्लोअर बिल पेंडिंग है, उस पर बहस मैंने ही शुरू की थी। उसके बाद हाउस में वह पास नहीं हो सका। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसे जल्दी से पारित करना चाहिए। जो सिटिज़न चार्टर की बात माननीय नेता, विपक्ष ने कही, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सिटिज़न चार्टर जिन-जिन प्रदेशों में आया है, उसने लोगों को एम्पॉवर किया है और उसके कारण प्रशासन भी कल्याणकारी बना है। It has led to development of a pro-welfare people initiative oriented bureaucracy. मुझे लगता है कि सिटिज़न चार्टर के बारे में बहुत गंभीरता से कहने और समझने की जरूरत है। अब मुझे आपसे एक बात कहनी है। आपने बताया

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

कि सेलेक्ट कमेटी की रेकमेंडेशंस को आपने माना है। अपनी आरम्भिक टिप्पणी में आपने भी कहा कि सेक्शन 20 में काफी कुछ कन्फ्यूज़न था, जिसे सेलेक्ट कमेटी ने क्लैरीफाई किया है। सेलेक्ट कमेटी की जो अनुशंसा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि लोकपाल के पास अगर कोई शिकायत आएगी तो उस शिकायत की प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी या तो वे अपने विंग से कराएंगे अथवा सीबीआई या किसी अन्य के पास भेजेंगे। अगर लगता है कि *prima facie* case disclose होता है, तो सीधे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपने इस अनुशंसा को मान लिया है। अब हमारी समस्या यह है कि जो अमेंडमेंट नम्बर 6 है, जो अभी present shape में है, उसमें आपने लिखा है, "...explanation of the public servant so as to determine whether there exists a *prima facie* case for investigation or not.' यह आपका ऑरिजनल अमेंडमेंट है। आप देश के बहुत बड़े कानूनविद् हैं और अभी देश के कानून मंत्री हैं। आपको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन में accused की कोई भूमिका नहीं होती। An accused comes into focus only when a cognizance is taken, based upon investigation, filing of chargesheet, application of mind by the Magistrate.' आप इन्वेस्टिगेशन करें या न करें, इसके बारे में उनसे पूछने जा रहे हैं। इससे तो आप देश के क्रिमिनल कानून का उल्टा कर रहे हैं। सैंक्शन के बारे में हम समझ सकते हैं, जो आपने बात कही। जब कार्यवाही पूरी हो गई, चार्जशीट पूरी हो गई, तो सैंक्शन के बारे में आपने बताया, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। That is an adequate safeguard available to any public servant. लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के पहले उनसे पूछा जाए तो पूरे इन्वेस्टिगेशन को, जैसा कि अभी त्रिवेदी जी ने बताया - The entire investigation shall be frustrated. The moment you ask against him, he will start all the rearguard action to destroy the evidence and to do everything possible. And, a bureaucrat or a public servant can tamper with it in a very speedy manner. हम इसके बारे में आपसे स्पष्टीकरण जानना चाहेंगे, यह बहुत जरूरी है।

मुझे एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह पूछनी है कि क्या Time frame of trial के बारे में इसमें कुछ करने की कोशिश की गई है? हम इसके बारे में आपका उत्तर चाहेंगे क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आपने इन्वेस्टिगेशन का Time frame दिया है। यह विषय जानना बहुत जरूरी है। हिन्दुस्तान का कानून है, इसे आप जानते हैं कि 'Presumption of the innocence of accused.' करप्शन के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जो guilty हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जिनका इन्वेस्टिगेशन में नाम आया जब तक वे कन्विक्ट नहीं होते, तब तक तो कानून चलेगा। हम आपसे यह अपेक्षा करेंगे कि जब देश भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी गंभीरता से खड़ा हो रहा है, तो speedy trial हो, अगर काई पब्लिक सर्वेंट है, एम.पी. है. मिनिस्टर है, आई.ए.एस., आई.पी.एस. है. कोई भी है, तो आप जेल जाइए, अगर आपने गलत किया है, तो उसका परिणाम भुगतिए। अगर कोई निर्दोष उसमें फंस रहा है, तो trial करके जल्दी से exonerate भी होना चाहिए। इस देश में चिंता की बात यह है कि दस-दस साल trial चलते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के कानून आ रहे हैं,

बाकी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए देश के हित में है कि करप्शन के केसों का प्रॉयरिटी में trial होना चाहिए, उसके बारे में माननीय मंत्री जी आपकी सोच क्या है? जब हम लोकपाल का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ trial को expedite करने का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी रखना पड़ेगा। यह हमारे लिए बड़ी सुखद बात है कि आज देश के कानून मंत्री इस विषय को टेक-अप किए हुए हैं क्योंकि देश के करप्शन केसेज़ और बाकी केसेज़ के trial का इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी क्या सोच है और इसके बारे में आप क्या प्रावधान कर रहे हैं?

माननीय उपसभापति जी, Politicians के बारे में बहुत चर्चा होती है कि Politicians दूसरों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांककर नहीं देखते। आज मैं इस बारे में सार्थक बातें करना चाहूंगा। इस देश में बहुत बड़ी बहस थी कि लोकपाल के दायरे के अंतर्गत प्रधान मंत्री को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मुझे याद है कि जब एनडीए की सरकार थी, उस समय लोकपाल की चर्चा हुई थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले ही कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे लोकपाल के दायरे में लाया जाए। जब लोकपाल की चर्चा चल रही थी, तो यहां भी लम्बी बहस हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ सेफगार्ड के साथ प्रधान मंत्री जी को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। यह भारत की राजनीति की, भारत की संसदीय परम्परा की और देश की जागरूकता की एक बहुत बड़ी विजय है कि आज यही संसद देश को यह संदेश दे रही है कि हम भारत के प्रधान मंत्री को भी लोकपाल के दायरे में ला रहे हैं। एम.पी. पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, इस बात को लेकर बहुत लम्बी बहस हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि grey area है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी थे, आज यही संसद बड़े ही गौरव के साथ एक ऐसा बिल ला रही है, जिसमें मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को पब्लिक सर्वेंट माना गया है with all the consequences. राजनीति और संसद के खिलाफ तमाम नकारात्मक छवि के बावजूद जब अवसर आता है तो यही संसद उठती है। And today, I wish to convey this profound sense of assurance on behalf of all my colleagues present here, the hon. Members of Parliament, that the same Parliament, in one voice, in unison, is going to pass a law, which is certainly going to give a positive message to the country that these parliamentarians can also rise to the occasion when the situation arises.

मुझे एक अंतिम बात कहनी है कि हम लोकपाल बना रहे हैं और एक बहुत ही प्रभावी इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। इस लोकपाल से देश की अपेक्षाएं पूरी होनी हैं। इस बात की विशेष चिंता करने की जरूरत है कि लोकपाल में ऐसे लोग आएं, देश के ऐसे लोग लोकपाल बनें, जो इस गंभीर दायित्व को समझें। लोकपाल में ऐसे लोग भी आएं, जो इस देश की प्रक्रिया को भी समझें। आज मैं यह बात बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, हमने कहा कि इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस लोकपाल बन सकते हैं,

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

अच्छी बात है। हमने उसकी प्रक्रियाओं को भी रखा है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि यह बात मैं संसद के सामने caution में रखूं। अभी हमने कई महत्वपूर्ण पदों पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को रखा है। मैं यहां पर उनका नाम लेने की जरूरत नहीं समझता। उनका कैसा आचरण रहा है? क्या उससे देश की छवि अच्छी बनी है? क्या उससे उस पद की गरिमा को मजबूती मिली है? यहां पर अरुण जी ने बताया है कि किस प्रकार से आप religion-based reservation कर रहे हैं, इससे आप एक नई चिंता पैदा कर रहे हैं। which is not constitutionally permissible. कुछ लोग शैड्यूल्ड कास्ट के बारे में बोल रहे थे। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHANTARAM NAIK: It is representation, not reservation.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं आप जितना विद्वान नहीं हूं, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा बोलने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (गुजरात): यह बिल रिलिजन बेस्ड नहीं है। ...**(व्यवधान)**... उसमें minority reference का कुछ लेना-देना नहीं है। ...**(व्यवधान)**... Minority could be a Sikh; minority could be a Jain; minority could be a Muslim.

श्री उपसभापति: राष्ट्रपाल जी, आप बैठिए, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Shankar Prasad, please proceed.

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आदमी ऐसे ही लोकायुक्त नहीं बनता। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्रवीण जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: सर, इसी के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा मत बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आप लोग ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: राष्ट्रपाल जी, प्लीज़। रवि शंकर जी, आप बोलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, ...**(व्यवधान)**... मैं यह सोच रहा था कि अभी हाल के चुनाव में एक हफ्ता पहले इतनी शर्मनाक हार के बाद कुछ तो शांति रहेगी। बाकी वे शांत नहीं रहना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, चूंकि यह बात उठाई गई है, तो मैं यह कानून पढ़ने जा रहा हूं:-

The proviso at Clause (b) in Section 3 reads, "Provided that not less than 50 per cent of the Members of the Lokpal shall be from persons belonging to the SCs, STs, Other Backward Classes, minorities and women." Minorities' representation is alien to our Constitution. There is representation for SCs, there is representation for STs, there is representation for Other Backward Classes and there is

representation for women, but our Constitution does not envisage representation for minorities. That is what I am saying. And, who is a minority and who is not is too well known. The Constitution knows that and, with great respect to him, I know a little of this branch of law in terms of Supreme Court judgements. यह जो पूरी बात है, वह गलत है, असंवैधानिक है, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि हमें यह कहना है ...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभापति जी, हमें यह कहना है कि जब इतने महत्वपूर्ण अधिकारों के साथ हम इस ऐतिहासिक लोकपाल बिल को पास कर रहे हैं, तो जिसे भी लोकपाल बनाया जाए, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही व्यापक है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट और फेयर है, but the person who becomes the Lokpal must understand the enormity of the power and the enormity of the responsibility. Those who become Lokpal need to understand that India has a Constitution,. India has an institutional system, India has a public opinion and people expect development as well. Therefore, those issues of corruption must be taken very strongly. Those who are guilty must be punished. But the enormity of the power must be understood in the context that they have accountability too. मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब एक ऐतिहासिक अवसर पर हम इस बिल को पास कर रहे हैं, तो माननीय जेटली साहब ने ठीक ही कहा है कि हम कानून से सीखते हैं, भविष्य में आगे और बदलाव करना पड़ सकता है, लेकिन आज सिलेक्ट कमेटी ने इस व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह बिल पास किया है। उस समय मैंने एक बात कही थी, इस पर अच्छी चर्चा हुई है, चतुर्वेदी जी हाउस में नहीं हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कई पार्टियों के लोग सिलेक्ट कमेटी में बैठे थे और सभी का एक स्वर निकला था। माननीय उपसभापति जी, जब हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं, जिसका आपको लंबा अनुभव भी है कि वहां पर भी हम लोगों के अंतर्विरोध होते हैं, लेकिन स्वर एक होता है। आज जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत लोग यहां बैठे हुए हैं और हमारा जेपीसी में भी यही स्वर होना चाहिए था। यदि हमारा जेपीसी में यही स्वर होता तो देश की अपेक्षा कुछ और होती, लेकिन टू जी पर जेपीसी का एक स्वर नहीं था। मैं जेपीसी के एक मैम्बर के रूप में अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं। जब यहीं पर सिलेक्ट कमेटी के काम की प्रशंसा हो रही है, तो मुझे लगता है कि देश को यह बोलना और बताना बहुत जरूरी है। आप यह जो एक ऐतिहासिक बिल लाए हैं, मैं अंत में इस संबंध में सरकार से एक बात कहूंगा कि देर आए, दुरुस्त आए। अगर यही 2011 में लेकर आते तो यह शायद बहुत पहले आ जाता। उपसभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. M.S. GILL (Punjab): Thank you, Sir; you have given me an opportunity. The hon. Minister suddenly asked me to see if I could say something on it. I am

[Dr. M.S. Gill]

grateful to him. Sir, I rise to support this Bill and, of course, like all my colleagues, I am happy that it is a rare occasion, when the House is seriously concerned with a very big piece of legislation. I have been here for many years now, and there are not many occasions, when one can see productive work of debating and listening. रवि शंकर प्रसाद जी, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना है। अगर मैं हिंदी में बोल दूं, तो फिर शायद आप सुनेंगे।

एक माननीय सदस्य: पंजाबी में बोल दीजिए।

डा. एम.एस. गिल: पंजाबी में ये सारे नहीं सुनेंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मेरा नाम रवि शंकर प्रसाद है। आप बोलिए, मैं आपको शांति से सुनूंगा।

DR. M.S. GILL: So, I support this Bill. For the last two-and-a-half-years, there has been a major question on this issue, of having a Lokpal, which will take care of corruption and which will substantially reduce the problem of corruption. I think, we are all happy that today, it is going to be passed here, and later in the other House also. While I support the Bill, I have some views on it. It has been mentioned that the Prime Minister is within the ambit of this Bill and my friend thought, that it is one of the successes and achievements, hat we have put India's Prime Minister under this Bill, like anyone else. I beg to differ. Yes, we are concerned with corruption, and we think anyone can be guilty of it, and, therefore, all people in this Republic, should be subject to investigation under this new extensive legislation. लेकिन हिंदी या पंजाबी में कहते हैं कि दो घर तो डायन भी छोड़ देती है। I have seen five or six Prime Ministers in my experience here, and I can say, that the Prime Minister is a very-very special person. Not today's, not yesterday's, not tomorrow's, but all of them are special. I have had the honour, to work with many of them. At least, I can recall five or six of them. For 130 crore people, whoever rises to that top seat is, obviously, worth watching, and the simple mechanism of catching me as well as you or anybody and everybody should also apply to the PM, because you get a great *josh* suddenly, I think, it comes out of a focus on politics that we should bring him in, I would say, ‘No’. Yes, if a Prime Minister is remiss in anything, there are other mechanisms to deal with him. Even when he is remiss, जिनको हम कहते हैं, आप भी कहते हैं कि इंसान भुल्लनहार है। वह भूल सकता है। इंसान है न, भगवान नहीं है। Even then, you should be graceful to him or her. At least, that is what I would expect. And, if at all this

democracy decides, that he or she is no longer fit to be there, you have other methods, by which he goes away, and then you should leave him alone. But, I think, the PM is in there. It will be there in the Bill. I support the Bill, but I wish it had not come to this.

There is also an implication, that the solution to India's huge multiple problems, and the removal of corruption, lies in this Bill. First of ail, it won't happen in any completeness. It's not that India does not have agencies or laws, to deal with various problems. India has a surplus of laws. In fact, long ago, I had made what I call the GLP. It is Gill's law. What is Gill's law? If people could be happy, by the laws made for their welfare, then India has the highest GLP in the world - Gross Laws Per Person. इस देश में कानून की कमी तो है ही नहीं। सभी का कर दिया, इसका भी कर दिया, उसका भी कर दिया, गरीबी का भी कर दिया, अब यह भी हो जाएगा। We have a Chief Vigilance Commissioner. Now suddenly, he becomes half irrelevant, and there are other mechanisms from the time, I was a civil servant in 1958. It is not as if laws were not there, and I would say, that those were the better times, under those governments. I would say it today looking back on them. Perhaps, those were still early days, when the larger political and administrative system, was more under the great thought of India's independence and the great men who brought it. But, it was there. And, if you have such laws, They must be balanced with something else, the fact that India suffers from a slow speed of governance, speed of decision making. In my career as a civil servant, the initiatives of those who decide — civil servants first and Ministers later — have steadily gone down. For any type of civil servants, more and more enquiries, and more and more worries are there, as our colleagues, who walked away, had said. They had said that nobody will sign a paper. I thought quite some time back, looking back at myself as a Secretary to the Government of India for four-five years, and looking at the situation today, and what I did then, I was very foolish in many things, and I would be hauled up today for many things. I say it here. But, I always had a belief that what I was doing was going to do good to Punjab or India. Today, you can't get away with that. The hon. Law Minister is sitting here. What I used to say, I heard him saying in Mumbai. It was reported. He said कि हम भी दस्तखत करने से डरते हैं। इन्होंने कहा था। सिब्बल जी, आपने कहा था। मैं तो पहले ही अन्दर बैठ कर कहता था। So, there is that worry also, Then how you are going to maintain your growth rate, if everything is being built up, that India's progress depends, on us catching every little thief anywhere in this great

[Dr. M.S. Gill]

sub-continent. I hope you do catch them, and, I am sure it will be *'Ram Rajya* then, but that is a worry I just express, after, I think, you must reduce your suspicion of India's public servants. Don't call it 'नौकरशाही', क्योंकि 'नौकरशाही' बहुत बुरा शब्द है। मैं भी वहां रहा हूं। इसके लिए कोई और हिन्दी शब्द सोचिए। because ultimately, in France and half the world, it is these people, and the large majority them — I see it in my experience even today, — it is they who do great service to this country, high and low. All your programmes, Jairam's or anybody else's, ultimately, are put forward by good public servants, वे चाहे इधर हों या उधर हों, छोटे हो या बड़े हों। So, please give a thought to it.

Sir, there is another thought that worries me. I have great admiration for the Indian judiciary, and they have, in difficult situations in sixty-seven years, given us great service, and, sometimes, supported the Constitution in great ways. But, I do not accept one thing. माफ करना, we have very, very distinguished lawyers of India sitting here, वकील, जज और पुलिस, इंडिया के यही तीन महापुरुष हैं। Rest of the people are also there, whoever they are, ladies and gentlemen, hon. Members of Parliament, 800 of them are there. I don't think that it was so when I was in college, but, there is a domination of these at the moment in this country, and, this is what I see, domination of these three. I think, democracy is larger than that, आखिर में तो आम आदमी आता है। Now, I don't want to use that, क्योंकि इस नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई है, इसलिए मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन खास आदमी मैं कह नहीं सकता इसलिए आम आदमी तो कहना ही पड़ेगा। तो जनता जनार्दन है, उसको भी थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए।

Ravi Shankar ji was very happy that all MPs are under it, in other words, the political class. I am not really out of that, you know my background. But, there is also a feeling that keeps on coming that the politicians में कुछ कमी है, ऐसी बात नहीं है। if I put it that way.

I think, through politics, all parties have served this country for 67 years., and they will go on serving the nation, and, without them, 130-crore people cannot be governed, either by one President, or, one powerful man, or, one group, and, we won't accept it. हम सारे ही अपना-अपना हिस्सा चाहते हैं, इसलिए अपने आप को इस लाइन में इतना पीछे मत करो, I think, there is much to be proud of in India's politics, and, it continues to be that way. I hope that is what will serve India.

Ultimately, in every Act of this country, and, you passed many, everywhere you straightaway say, a Judge, ideally a Supreme Court Judge, ideally a Chief

Justice of India should be the Chairman. मैंने कितने ही देखे हैं। You do not look for a distinguished India, which the English would, or, somebody else would. Those are no good now. 'Distinguished Indian'. You should look for them. Please. Let me put it another way. I was the Chief Election Commissioner, after a very distinguished gentleman, and, I thought up a line, which I said with great belief, that I am a 'Salaried Ceasar'; as Chief Election Commissioner, I am a 'Salaried Ceasar'. Not one Indian had decided that Gill should be so; Please don't imagine, that everything will always be best solved by a Judge, who is also a bureaucrat of a kind, in the legal field, and, the legal people cannot accept a time frame. जजमेंट देने में, केस सुनने में दस साल भी निकल जाएं, बीस साल भी निकल जाएं, उसके बाद आप जजमेंट रिज़र्व भी कर लें, यह सब कुछ अपनी जगह ठीक है।

Don't imagine all the time, that everything can be solved by Judges. Even though we admire them, please look at the rest of Indians also, whoever you choose. This thought comes to me. For example, civil servants, their mind is also legalistic. It is not development or pushing India forward, कानून की अपनी बात क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कह देंगे। There is a limitation there.You should think of others also in this country, who are serving in a worthwhile way. I will finish quickly.

There is a provision for the Chairperson and Members of the Lokpal. उनको कौन देखेगा, अगर कमी हो गई? The mechanism that has been put here, is that one hundred Members of Parliament can give a petition. Am I right? One hundred Members of Parliament can sign a petition against the Lokpal. ठीक है? That is a mechanism available in the Constitution, and that has failed against the judges. I think half of Lokpal would be judges. Once they are in, no matter which way they go, as my friends here from West Bengal were trying to be agitated, you are going to find it very difficult to correct the situation. It is very difficult. I don't know what the answer is. But I think there is a point there.

Finally, this is all to catch and punish people. Why are we looking at the speed of these things? While we admire judges, I think all of us in this country see that एक दफा आपको पकड़ कर ले गए या केस हो गया, then the case can go on for ten years or twenty years. In all sorts of aspects, I see finally after ten years the highest court or the middle court lets you off and says कि आपको छोड़ दिया,

[Dr. M.S. Gill]

आप बरी हो गए। भाई, मेरी जिन्दगी तो खत्म हो गई, मेरा कैरियर खत्म हो गया, मेरी उम्र भी निकल गई, आपने तो आराम से कह दिया we let you go. That side of the thing should also be looked at. I don't know how. Our Law Minister is a wise man and others as well, but you must also take care of the people and their lives. They may be hurt for no good reasons, and there are lots of cases in our history, where people have been smashed by misapplication of law like the Dreyfus case of France. There are plenty of examples. I just leave that as a thought with you. Please look at those people also.

Finally, I don't think I have much to say. Yes, I support the Bill. But please look at other aspects of this issue, and, the problems from other angles. India needs growth. Ultimately, India s problems are poverty, unemployment, food, and all those kinds of things. And to solve those, I hope you don't put sand in the wheels of India's movement, in such a way कि वह इंजन न तो आगे जाएगा और न ही पीछे जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। Thank you.

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, while introducing the Bill, hon. Kapil Sibal has stated that the people of India are fed up with corruption at higher places. It took many years for hon. Kapil Sibal and the ruling party to realize this fact. We in the opposition, the Left has been pointing out that the people of India are fed up with corruption at higher political dispensation. But you were not ready to recognize it. You were not ready to bring this Bill. The Select Committee prepared its final Report one year ago and we have been repeatedly demanding during the last two sessions to bring the Lokpal Bill but you were not ready. Only after receiving a severe blow in the last assembly elections, you realized that people are fed up with corruption. That is the tragedy. And what is the root cause of corruption in India? It is the unholy nexus between the political leadership, the corporate houses and the officialdom or bureaucrats.

This unholy nexus is the cause of corruption in India. By corruption, I do not mean corruption in a village office by a peon or an attendant, but corruption of looting the public money and for looting the public money. A section in the Government and the political leadership are in alliance with the corporate houses and the upper echelons of the officialdom. The question is: Do we have the political will to break this nexus? Here, in this Bill, the main drawback is that the Government did not have it. You are leaving the corporate houses and the private sector which is the main cause, which is breeding corruption, which is bribing the

politicians and which is bribing the officials. The question is: Do you have the guts or the courage to touch them? That is why, I move an amendment and I quote, "Any person who is or has been Chairman or Managing Director of any business entity enjoying benefits such as export incentives, customs and excise tax concessions, etc. and getting contract from Government and public sector undertaking". I don't mean that we have to bring the private sector as a whole under the ambit of this Bill, but those entities which are getting concessions, which are getting money from the Government or the public money, that section has to be included in this Bill. Then only will the people think that we are serious about curbing corruption in India. That is the main drawback of this Bill. Comrade Shri Sitaram Yechury also move a similar amendment and I hope that you will accept that amendment.

Sir, I have another amendment. When we talk about transparency, we want transparency everywhere, but clause 14 says, "Provided further that any such inquiry shall be held *in camera* and if the Lokpal comes to the conclusion that the complaint deserves to be dismissed, the records of the inquiry shall not be published or made available to anyone". Why? Let the people know what was the complaint and why the Lokpal has dismissed that complaint. It is the right of the people to know the cause. Why is there the provision of in *camera?* 'Why are we denying the people to know the complaint and the reasons for dismissal of that complaint? I think the Minister will accept that amendment also.

Sir, along with this, if we are sincere in rooting out corruption in public life, two Bills have to be brought forward, that is, the Citizens' Charter Bill and the Whistleblowers Bill. Both of them are in the list, but I think the Government will wait for another blow and then only will it realise that it has to bring forward such a Bill and give the credit not to the Government, not to your party, but to somebody else. That is what you are doing. You waited for more than one year to bring forward this Bill and now, the credit does not go to Shri Sibal and the Congress Party, but to somebody else. You are eager to placate somebody else. It is not good politics.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why are you so angry?

SHRI M.P. ACHUTHAN: Even though I have got some reservations, I fully support this Bill. I congratulate the Chairman and Members of the Select Committee for making such amendments for which we opposed it one year back. Thank you very much.

4.00 P.M.

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to speak on the Lokpal Bill which is historical and important. 1 shall begin by congratulating the UPA Government for bringing the Bill; and all opposition parties which are supporting it. Having said this, since the beginning of the UPA Government, it was committed to make the social governance — I am not using the word 'political governance' because political governance is one part of the social governance — transparent. It was the commitment of the UPA Government to make social governance of this country, more and more, transparent. That began with the historical legislation which is rather much more historical than this; and that is, the Right to Information Act. To the best of my knowledge, no such legislation prevailed because most of the European countries, without such legal provision, have made their governance transparent. I strongly support the Bill; and I was privileged to work on this Committee initially.

I would like to remind the Members of the august House what Dr. B.R. Ambedkar had said in the Constituent Assembly. He said, "if tomorrow something goes wrong in the Constitution, please don't blame the Constitution. Blame those who implement the Constitution." We have taken so many years to translate Dr. Ambedkar's warning into this kind of legal document. This shows that corruption has become a way of life in the country. Having said this, once the whole issue began like a hot potato, I had suggested in one of my speeches, we have been discussing the issue of corruption without mentioning the sources of corruption. In this country unless you pinpoint the sources, people say, even the most corrupt person feels that he is not corrupt. You have to nominate, you have to identify and you have to pinpoint. Basically according to me, I would advise my friends, not to consider this as a political speech because I have joined politics a bit late. The entire political class in the country irrespective of partisan politics must introspect itself to what extent we are responsible. Our policies, our programmes, our implementation, our logistics which, according to me, are extremely important sources. Connected to this is an electoral reform.

The second is bureaucracy. Sir, bureaucracy can't be exempted because politicians and political class form bureaucracy unless there is some sort of nexus; and I repeat it to be on record, when I refer to the political class, I do not mean

a particular political party. In this country the source of corruption basically is absence of the rule of law. The white people of Europe were successful in implementing democracy, not because they are intrinsically superior to the Asian people. But they have accepted transparency. They have accepted the rule of law. This is with regard to bureaucracy, one example.

When we were having the public sector occupying commanding heights of the economy and contributing significantly, people were talking about the public sector en bloc and lock stock corrupt. During the last 20 years, we are finding that corruption is rampant in the private sector. It was supposed to be the forerunner of the economic growth; and I compliment them.

Next is the judiciary. I don't want to give historical anecdotes of this. But I remember distinctly one hon. Judge of the Supreme Court while commenting about corruption in the judiciary happened to make a statement that 50 per cent Judges of a particular High Court are corrupt. I am not saying this. Even the commonest possible man and woman in the country, those who are illiterate, who do not understand about democracy, who do not understand about judiciary, they also ultimately say, "मैं तुमको कोर्ट में लेकर जाऊंगा।" This means judiciary is the last resort which people are looking at. Judiciary itself is not free from corruption.

Another point is that we are talking about is non-implementation of the schemes. I appreciate this Bill. 1 fully support it. I remember my professor and I would mention his name with great sense of gratification. Prof. M.L. Dhanaplan taught me Economics and I mention it in this august House. I would like to mention in this august House that this country never suffered hon. Law Minister is here because of scarcity or famine of laws and acts. This country suffered because of non-implementation. Today, there are eleven Acts checking the corruption, but no proportionate rules have been made. Therefore, the question is this. Let us take the Public Distribution System. Nearly Rs. 96,000 crores we are spending on the Public Distribution System are for the common people of the country. Straightaway, without going into the logistics, 50 per cent of the money spent on PDS goes waste because of leakages, diversions, etc. Now leakages, diversions, etc. are sophisticated words and vocabulary for corruption. Wheat and rice bags are going to black markets directly from the FCI, rather than reaching the Fair Price Shops. According to me, I am open to correction from any of the hon. Members here, nearly 25 per cent of the Fair Price Shops are given to the relatives of politicians

[Dr. Bhalchandra Mungekar]

in the country across political parties. I was privileged to be the member of the Eleventh Five Year Plan. Between 2004-05 and now, the programmes that the UPA Government has initiated, have not taken place during the earlier 50 years. There are so many programmes. But the benefits of these programmes are not reaching the appropriate people, the desired people and the targeted people only because of corruption, leakages and diversions.

Hon. LoP is not there, but Shri Sitaram Yechury is sitting here. *...(Interruptions)...* Sir, please be kind to me. I will make only two comments before this august House. There are two dimensions of law. First is the legal dimension and second is the moral dimension. Society or instruments of the society make the law. But that is the legal enactment. It does not lead anywhere. For example, we are bringing a legislation giving 33 per cent of seats to women in elections. During the elections which have taken place in the four States, how many political parties have given more than five per cent representation to the women? Have we got any moral right to talk about empowerment of women? I am not talking of any particular political party. I am referring to Dr. Lohia. I am talking about what is the difference between Ukti and Kriti. Therefore, what we are discussing today is the legal dimension of the Lokpal Bill. Law is a necessary condition for social governance, it is not the sufficient condition. The sufficient condition is moral dimension of the legislation. Uniess this society accepts that corruption is immoral, corruption is unacceptable, corruption hits the poor persons more, corruption is against the disadvantaged sections, and corruption essentially is done by the elite people, those who are having the levers of power — of course, levers of power does not mean the ruling political party; becoming Chairman of the Satyanarayan Mahapooja also is a source of power because here he decides how to spend the money — unless the society accepts this moral dimension of law, I do not think law will take it further.

Since beginning, I should be on record despite the fact I belong to the Ruling Benches, I am particularly not comfortable to include the incumbent Prime Minister under the Lokpal. Let me submit for your kind consideration that the Deputy Consulate General of India is my close friend's daughter. She has been arrested under one pretext or the other. At the end, there is a hue and cry in the country. If we include the incumbent Prime Minister, and' the moment it is published that the incumbent Prime Minister has been summoned to appear before the Committee, whichever be the Committee, what moral authority would the Prime

Minister be left with? That is why I would like to put my view on record. I am fully supporting this Bill, but including incumbent Prime Minister will be totally demolishing the moral authority of the Prime Minister.

With these words, I strongly support the Bill and thank you very much, Sir, for your generosity.

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this historic Bill. I am privileged because I was also a part of the Select Committee and got an opportunity to hear very important and informative discussions in the meetings.

Sir, we are accepting the Bill, in the current form, which was accepted by the Select Committee. In the Report of the Select Committee itself, we gave a note because we thought that non-inclusion of some parts would make the Bill ineffective. I would request the Government to accept our Amendments which we are moving here, and these relate to corporates, private sector and PPP which are involved with the business of the Government. Lakhs of crores of funds are involved in PPP projects and in licensing of many of the natural resources. So, we have to include them. Otherwise, what the Congress (I) is doing now will happen again. There is a saying in Malayalam "Adiyumkondu Puliyumkudichu", which means that after getting beaten up, the person is compelled to drink the bitter drink. Even after getting this Report, the Government was not doing anything in the last one year. Now, because of various compulsions, they are doing it. This may again happen if they are not accepting this Amendment. Sir, this Bill will be a paper tiger if we are not considering the developments in the new era, that is, after globalization came into effect. Transparency, as Dr. Mungekar said, is very important. Now there is a belief that all politicians are corrupt and that politics itself is corrupt. Such a campaign is going on. It is being felt that if professionals from outside politics come into power, that will be good. The names of I.T. professionals are also coming up. One thing which I want to say is that for the last twenty years, this country has been run by professionals, non-political bureaucrats. But corruption is rampant even after such a leadership has been there since 1991 when the globalization era was started. So, it is not a matter whether it is a professional, non-political person, bureaucrat or a politician, but it is a matter as to whether the system is following some principles. In a system where a lot of legislation is needed —some other legislations are also pending here like the

[Shri K.N. Balagopal]

Whistleblowers Protection Act, Citizen's Charter and Grievance Redressal Bill —we have to pass them. But, not just this, we need to take into consideration the new system which is coming into force in the country. After 1991, that is, the globalization era, a majority of the Government businesses have got transferred to private people. We can see, in the last ten years, how many corruption cases have come up. There is the case of 2G, K.G., CoalG, VodafoneG, and many other G's. We also have cases relating to the Delhi Airport and Mumbai Airport where lakhs and lakhs of crores of rupees are involved. We are not saying that. The C&AG is saying about that. But the Government is not taking any action and if we are not looking into these questions very seriously, this Act will not be effective. I am very happy that Shri Kapil Sibal is much more matured now than the earlier days. He has brought another Amendment after hearing the discussions, and the total spirit of the Select Committee is accepted now. I thank the hon. Minister because he has brought an Amendment relating to seizure as well, namely, clause 26. But when are you looking into corruption cases, it is not necessary to elaborate upon it. Our President, when he was Finance Minister, stated in Parliament that around twenty lakhs of crores of rupees of blackmoney were lying in European banks. Unofficially, it has been revealed that it is more than Rs. 80 lakh crores. Sir, corruption is there. How is corruption happening? I am losing my belief in many of the systems. In the case of Delhi Airport, with the C&AG Report and facts I sent a letter. Not only I, many of our MPs signed a letter and sent it to the CVC, the Central Vigilance Commission. Nothing has happened not only in this case; Sir, many other cases are there. So, make this Act better than a paper tiger. Many of the Members raised the cases of Toll roads, PPP roads, about how corruption is happening. The price of natural gas in US, after Shale gas finding, is around three dollars per MMBTU. Now we are giving at 8.4 dollars. Many of these kind of cases are coming. I think this area should be included. We moved some amendments, amendment Nos. 14, 15 and 16. It is related to Amendment No. 14. We are requesting the Government to accept that point. Otherwise, the Bill will not be successful. Please take that into consideration. Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

SHRI Y. S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, for giving me this opportunity, as today is our first working day of this Winter Session.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thanks for your kindness.

SHRI Y. S. CHOWDARY: Sir, the concept of Constitutional Ombudsman was first proposed in Parliament by the Law Minister, Shri Ashoke Kumar Sen in the early 1960s. It is very unfortunate that even after 52 years of its first introduction, the Lokpal Bill is still not enacted in India. The Select Committee submitted its Report on 23rd December, 2012, but the Government took almost a year and did not consider even the key recommendations of the Select Committee. For example, the Select Committee recommended that an Investigation Officer's transfer should be cleared by the Lokpal and an errant officer should be raided without the notice; this has not been accepted by the Government. In fact, this particular issue has affected our State of Andhra Pradesh. This Bill had been introduced about a year back. Probably, the entire nation knows about the rampant corruption which took place in the State of Andhra Pradesh, particularly in the last decade, and a case is going on. They have simply allowed the same case and everything to go on and Congress Government, probably, had waited for entering into a deal with party to bring this Bill. It is very unfortunate for me to say that and as a matter of fact, in our country, there is no dearth of laws. We have problems of implementation and execution. In fact, when every new law comes, to the best of my knowledge, every time corruption index goes up. Because of the new law people demand more money and the corrupt people make more money. That is what is going on. However, finally they have brought this Bill. From our party, we would like to support and see that future amendments, time and again, are brought into the Bill. My suggestion is, we can put a proper monitoring system, at least for the first five years, to report to Parliament about implementation and, maybe, there should be quarterly reporting. How many cases are being taken under Lokpal? On Lokpal, we are trying to .take quick decisions on errant cases and many officers, business people, politicians also are jailed in the State of Andhra Pradesh. This Bill, hopefully — with the present cases once it is enacted, can be implemented for pending cases. With all these changes, I support this Bill on behalf of my party. Thank you.

DR. BARUN MUKHERJI (West Bengal): Thank you very much, Sir.

I rise to support this Bill and it has been rightly called by the hon. Law Minister as historical and important. It is really important. When we are committed to fight corruption, it should be treated as one of the tools with which we can fight corruption. But, it is also historical, in the sense, if we go through how the

[Dr. Barun Mukherji]

final Lokpal Bill, which is now being discussed here, has developed. We have been discussing about it for more than two years. It is one good example that how, through conflicts, debates and discussions, we can come to a near consensus. It is one such example. I believe, when it will be enacted, it will have enough scope and strength to fight corruption. But, this may not be foolproof. While implementing this, we may experience some of the drawbacks and the Parliament is open to further amendments in future.

One thing I should request Shri Kapil Sibalji is this. Just now we have received a piece of paper containing another amendment he has moved. I believe that it is his afterthought. I congratulate him for this. The amendment is relating to clause 20. It was already raised in the House before. The amendment reads, "Provided also that the seeking of explanation from the public servant before an investigation shall not interfere with the search and seizure, if any, required to be undertaken by any agency (including the Delhi Special Police Establishment) under this Act." It is a welcome amendment. But, at the same time, I would like to bring to his notice that another amendment has been moved by my learned colleague, Sitaram Yechuryji. It has been proposed, when all the public servants right from the Prime Minister down to Group "D" staff is included under this legislation, what are the reasons for exclusion of corporate sector or NGOs or PPPs. By doing this, I think, we are allowing a lot of scope or source of corruption. We can particularly mention about PPPs. From our experience — everybody can testify this—of PPP projects, mostly the private parties are extracting the major advantages and there is a lot of corruption through it. When corporate or PPP projects or NGOs, who are involved with the Government in getting licence and other things, are spared, I think, it will be, in spite of arriving at consensus on a very good Bill, a very weak point. So, once again 1 request Kapil Sibalji to think over it. He has proved that he can move amendment after giving a thought to any proposal. So, he can, after giving a thought to this, move another amendment. So, my point is, at least, PPP should not be spared completely, because the root of some sort of corruption is still there. So, to make it a foolproof —we can arrive at some consensus so that the whole House can accept it — an amendment can be introduced. It can be just coined in a sentence that this particular sector should be included and it comes under the ambit of this Lokpal Bill.

As I have already told, through conflicts as well as through discussions, we can come to some consensus. We have come over a lot of conflicts. We have to come to some sort of consensus accepting this one.

So, at the fag end of the debate, I once again request the hon. Law Minister to consider inclusion of PPP projects. People are taking advantage of these projects. There are huge commissions involved, and there is huge corruption involved in these.

Once more, I congratulate the introduction of this historic and important Bill. I appeal to the hon. Law Minister to insert one more amendment here and make it foolproof so that we can move ahead in our fight against corruption.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri Birendra Prasad Baishya. Please remember that you have only five minutes.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Thank you, Sir, for having given me the opportunity to speak on this historic Bill.

There is no doubt, Sir, that this is a historic Bill. This is also a historic moment for all of us. I very proudly associate myself with this moment.

I rise here today to support the Bill. Sir, Asom Gana Parishad has always been in favour of a strong Lokpal at the Centre and, simultaneously, strong Lokayuktas at the State level. Corruption takes place not only at the Central level but also at the State level. A strong Lokpal at the Centre and strong Lokayuktas in the States are the need of the hour, Sir. I remember, in 1996, we had the United Front Government at the Centre. In the Common Minimum Programme of the United Front Government, it was laid down that the Prime Minister should be brought under the purview of the Lokpal. On several occasions we have discussed the Lokpal. There have been a lot of discussions. There has been a lot of criticism and debate about whether the Prime Minister should be brought under the purview of the Lokpal or not and whether Members of Parliament should also be brought within the purview of the Lokpal or not. We have already discussed all these aspects. On 29th December, 2011, when this Bill was being discussed in this House, we had expressed our party's view and I remember, on that day, we had very categorically said that the Prime Minister should be brought under the purview of the Lokpal. Not only that, our party had also opined that Members of Parliament should also be brought within the purview of the Lokpal. I am not saying this thing only today. We have taken this stand since 1996. We have never changed our stand. A lot of discussion has already taken place on this Bill in the House. We have always advocated for a strong Lokpal. I remember, in this regard,

[Shri Birendra Prasad Baishya]

there was an all-Party meeting convened by the hon. Prime Minister. We have always supported the creation of a strong Lokpal. We have always taken the stand that the Prime Minister and Members of Parliament should be brought within the purview of the Lokpal. Sir, we have also been discussing a very interesting aspect about the federal structure of the country. But today we are discussing just the creation of the Lokpal. I want to emphasize that we should have strong Lokayuktas in all the States, simultaneously. Without Lokayuktas at the State level, we cannot curb corruption.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY) in the Chair]

To curb corruption, a strong Lokpal and a strong Lokayukta is the call of the hour.

Sir, we had suggested many things on 29th December; we still remember the midnight incident. We had moved certain amendments also. Today, I am happy to see most of the suggestions included in the Select Committee's recommendations. Sir, I must congratulate the Select Committee which has done a tremendous job, a marvellous job under the chairmanship of Shri Chaturvedi. They have included almost all the points in their Report. The House is totally agreeable in passing the Lokpal Bill today, as recommended by the Select Committee.

I have one request. We rise here to support the Bill. I have always advocated federalism. I am always in favour of federalism. We don't want the powers of the State Government to be taken away by the Central Government. But, the country and the House should remember one thing that without a strong Lokayukta, you can't tackle corruption in the country. In the Bill, there is a provision to say that within a year, all the State Governments shall have a Lokayukta. I hope, this provision would be implemented strongly in each and every State.

After a few minutes, Madam, this House is going to pass a historic Bill. This House is going to make a historic contribution to the democratic structure of the country. Today, it is important from another point. It is a very important day for all of us who are sitting here to pass the historic Bill. I am very proud in associating myself with this historic moment.

With these few words, Madam, I, personally, and on behalf of my party, the Asom Gana Parishad, strongly support the Bill. We need to tackle corruption in the

country and the country needs a strong Lokpal; simultaneously, it needs a strong Lokayukta in States. Thank you, Madam.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Madam, I rise to oppose the Lokpal Bill on behalf of my party, the Shiv Sena. The Lokpal Bill, 2011 provides for the establishment of a body of Lokpal for the Union to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and. for matters connected therewith or incidental thereto. Madam, in its interim report on "Problems of Redressal of Citizens' Grievances", submitted in 1966, the Administrative Reforms Commission *inter alia* recommended the setting up of the institution of Lokpal at the Centre. To give effect to this recommendation of the Administrative Reforms Commission, eight Bills on Lokpal were introduced in the Lok Sabha in the past from time to time. However, these Bills lapsed consequent upon the dissolution of the respective Lok Sabha except the Bill of 1985 which was introduced and subsequently withdrawn.

India is committed to pursue the policy of zero tolerance against corruption. India ratified the United Nations Convention against corruption by deposit of Instrument of Ratification on the 9th May, 2011. The Convention envisaged that countries ensure measures in domestic law for criminalisation of offences relating to bribery and put in place an effective mechanism for its enforcement. In brief, a more, effective mechanism needed to be evolved to receive complaints relating to allegations of corruption against public servants including Ministers, MPs, Chief Ministers, Members of Legislative Assemblies and public servants and to inquire into them and take follow up actions. The fact remains that from year 1966 to 2011, absolutely nothing came up towards formation or creation of Lokpal, an anti-graft body at the Centre until anti-corruption activist Anna Hazare appeared at the centre stage in April, 2011, with an overwhelming public response to his movement for framing a Lokpal Bill. The common view of anti-corruption crusader Anna Hazare and people who came out in full support of the anti-corruption campaign was that governance deficit was glaring, political will lacking and Government just not serious about tackling the menace of corruption manifested in the form of black money, corruption in public procurement, slow administration of justice and lack of transparency in the working of institutions entrusted with the task of investigating corruption. And thus, rattled by the public outcry, the Government swung into hurried action and spelt out Lokpal Bill that would give immense powers to the

[Shri Anil Desai]

body of Lokpal to deal with corruption in public life. While conferring the constitutional status to Lokpal it brings the Prime Minister under its ambit, and brings Ministers, MPs, Chief Ministers, MLAs and all categories of government servants under its purview. It also provides for autonomy to investigating institutions like CBI with many other provisions.

Our nation that has accepted parliamentary democracy enjoys the status as a largest democracy in the world. In our set-up, we have legislature, executive and judiciary as three strong pillars of democracy with media as fourth pillar that strengthens our mechanism. Creating another extra constitutional authority like Lokpal would amount to blatant undermining the authority of Parliament and Constitution. The provision of powers entailed in the Lokpal Bill may very well be implemented through our democratic set-up. Moreover, the President of India be empowered with the powers that are meant to be given to the Lokpal. Besides, tomorrow if Lokpal errs or falters, there seems to be no effective provision in the Bill to remove the Lokpal. In short, by creating Lokpal, we should not jeopardize our democracy.

मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि महाभारत में, धर्म की रक्षा के लिए तथा अधर्म के खिलाफ सोचने वाला जैसा युधिष्ठिर था और जिसको इस प्रकार ढूंढ़कर लाया गया था, यहां ऐसा युधिष्ठिर कहां मिलेगा? अगर युधिष्ठिर मिल भी गया तो महाभारत में जिस तरह युधिष्ठिर ने मोहमाया के जाल में फंसकर या जुए के लालच में आकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, तो क्या भरोसा है कि यह आने वाला लोकपाल इस तरह का काम नहीं करेगा? इसीलिए हम यह चाहते हैं कि देश के राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च पद है, यह पद भी इसी पावर के साथ दिया जाए, ताकि इस देश के लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरह से और सम्मानित दृष्टि से पूरी दुनिया में जाना जाए।

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Madam, my party is fully supportive of the Lokpal Bill, which, unfortunately, has been inordinately delayed due to games that were played by certain political parties last year in this House. Our people are fed up with corruption at all levels, which has spread like cancer. Massive scandals have come to light which have disgusted the nation in the last few years, and a strong civil society movement has been created to fight this menace. I think, in a way, this is a reaction to that strong civil society movement that has come about.

Madam, the way agencies like the CBI, IB and Income Tax have been misused by this Government in a brazen manner resulted in the need to free them from

Government's control. Yet, here I may mention that the way the officers are selected to these bodies needs to be looked at. To my question, last week, in Parliament, the Government replied that there is no Selection Board for recruitment to either of these agencies. Officers are recorded from the State Police Departments and they come here on deputation. Who are these officers? These are the street-smart officers who lobby hard and come to the Centre, or, those who the Chief Ministers want to get rid of. So, they are brought to the CBI and the IB. Moreover, I was horrified to learn that there is no training programme for them when they are inducted. In the U.S., in the FBI, in the Scotland Yard, there is a mandatory three years specialized training programme, but we have no such training programme. So, if we have to make these institutions strong, I urge the Government to create a separate cadre for such officers and they be given specialized training.

Madam, while there is no doubt that this Bill is a novel attempt to curb corruption, I feel that even the Lokpal, once it comes into being in the next couple of days, would be toothless unless we do something about our judicial delivery system. If guilty officers or public functionaries are not given exemplary punishment expeditiously, the institution of Lokpal would be rendered totally ineffective. Investment has to be made to improve our judicial delivery system by creating new courts and adding judges, and, if needed, Mr. Minister, by running the courts in two or three shifts every day.

Madam, in the end, while I welcome the Bill, I must admit that I would agree with Prof. Ram Gopal Yadav that the office of the Prime Minister shouJd have been kept outside the purview of this Bill. In the past we have seen how attempts to make a Prime Minister ineffective were made by a certain political party and here I am referring to St. Kits affair where a fictitious account was created in the name of Mr. V.P. Singh's son so tkat he could become ineffective. We have recently seen how telephone calls of European heads of states were tapped by certain agencies. This could happen here and as India becomes a super power, games would be played by international agencies to make the office of our Prime Minister ineffective. They could create fictitious accounts abroad, institute cases abroad so that Lokpal opens investigations against the sitting Prime Minister and renders him or her completely ineffective. So, I would urge the Minister that even now it is not too late; kindly reconsider this and keep the Prime Minister out of its purview. Thank you very much.

श्री रामविलास पासवान (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो गुजराल साहब का यह जो प्रस्ताव है, प्राइम मिनिस्टर के संबंध में सजेशन्स हैं, मैं शुरू से ही इस बात का

[श्री रामविलास पासवान]

हिमायती रहा हूं कि आज यूपीए की सरकार है, कल किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह नहीं पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री के पद को इतना डिग्रेड मत कीजिए कि कोई प्रधानमंत्री निर्णय ही न ले सके। जैसा कहा गया है कि आज ऑफिसर निर्णय नहीं लेते हैं और सारे के सारे ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छोड़कर सोचते हैं कि जो भुगतना होगा वह प्राइम मिनिस्टर भुगते। कल प्राइम मिनिस्टर भी कोई निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि काम नहीं करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। इस डेमोक्रेसी में, जिस डेमोक्रेसी में कोई पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए मेरा यह विचार है कि पूरे सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस दायरे में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मेरी समझ से प्रधानमंत्री को इस दायरे में नहीं लाना चाहिए। जैसा कि अभी गुजराल साहब ने कहा कि कोई भी, कहीं भी जाकर केस कर दे और फंसा दे तो प्रधानमंत्री ऑफिस की जो मर्यादा है, वह खत्म हो जाती है।

एक तो हमारा यह विचार था, दूसरा हमारा यह विचार है, यहां पर श्री अब्बास नकवी साहब जी बैठे हुए हैं, नजमा हेपतुल्ला जी बैठी हुई हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज में पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सिलेक्ट कमेटी बनी, उसने एक निर्णय दे दिया और उस निर्णय में यह कहा गया कि जो शैड्यूल्ड कास्ट्स/शैड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको 50% स्थान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह कहकर कि हिंदू को दिया गया तो ठीक है, मुसलमान को दिया गया तो रिलिजियस है, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। उस पक्ष में भी बैठे हुए जो माइनोरिटी के लीडर्स हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस मुद्दे को, इस मामले में लोगों को राजनीति से बचने-बचाने का काम करें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है। इसमें सिख भी है, ईसाई भी है।

श्री रामविलास पासवान: यह बात भी सही है कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं। माइनॉरिटी में सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, ये सारे के सारे लोग उसमें आते हैं।

तीसरा हमारा यह कहना है कि जो कहा गया कि यह 2011 में पास हो जाता तो बहुत अच्छा होता, एक हिस्टोरिक डे बनता, मैं समझता हूं कि यह उस दिन पास नहीं हुआ तो ठीक हुआ, क्योंकि यदि उस दिन पास हो जाता तो पार्लियामेंट की कोई मर्यादा नहीं रहती। यदि यह उस दिन पास हो जाता तो यह माना जाता कि कुछ लोग जंतर-मंतर पर बैठ गए हैं और मोबोक्रेसी के द्वारा पार्लियामेंट पर निर्णय थोप रहे हैं। आज यह हो रहा है कि यह मामला सेलेक्ट कमेटी में गया और पार्लियामेंट बैठ कर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी ने जो काम किया है, उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। हम सिब्बल साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इसको

बहुत ही पेशेंटली और सभी पार्टीज का कंसेंसस बना कर इसको यहां रखा। जिन लोगों ने इसका विरोध किया है, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है, हम उनके विरोध को गलत नहीं मानते हैं। उनका भी एक तर्क है, उसमें दम है। कोई यहां भगवान का दिया हुआ नहीं है। आज एक पार्टी बनी है — आप। इसके नेता कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, सब बेईमान हो गए हैं। लोकपाल कहेगा कि हम ईमानदार हो गए हैं, दुनिया में सब बेईमान हैं। यहां असम गण परिषद के मैम्बर बोल रहे थे। क्या असम गण परिषद का जन्म करप्शन के खिलाफ नहीं हुआ था? प्रफुल्ल कुमार महंत जी चीफ मिनिस्टर बने थे, वे सबसे यंगेस्ट थे। सब नौजवान आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, क्या उनके खिलाफ चार्ज नहीं लगा? जो लोग जेपी मूवमेंट के खिलाफ में आए, क्या उनके खिलाफ चार्ज नहीं लगा? कुछ लोग यह वाहवाही लूटने के लिए कि एकोऽहं द्वितीयोनास्ति, एक हम ही ईमानदार हैं और बाकी सब बेईमान हैं, हम समझते हैं कि यह हालत नहीं होनी चाहिए। लोकपाल के संबंध में यह जो कंसेप्ट बनता जा रहा है कि सब अफसर्स बेईमान हो गए, क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक के अफसर्स, सब पॉलिटिशियंस बेईमान हो गए और वहां जो बैठेंगे, वे गंगोत्री बन जाएंगे, दूध का धोया हुआ कि वहां से गंगा निकलेगी और पवित्र होगी, यह समय बताएगा। मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सच्ची बात कहता हूं। मैं इसे दिल से सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। हमारे अन्दर कहीं-न-कहीं भय है, सब लोगों के मन में डर है कि इसका रिपरकशन क्या होने वाला है। हम लोग लंगटा राजा की एक कहानी सुनते थे। किसी ने उसको कहा कि देवलोक का बढ़िया कपड़ा लो और वह नकली निकला। उसने उसको जाकर कपड़ा दिखला दिया, उसमें कुछ नहीं था। उसने कहा कि देखो, इस कपड़े को वही देखेगा, जो अपने असली बाप का बेटा होगा। राजा को दिखलाया और पूछा कि कैसा लगा हुजूर, तो राजा ने सोचा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर डर लगा कि अगर मैं कह दूं कि कपड़ा नहीं है, तो यह कहेगा कि असली बाप का बेटा नहीं है, हो सकता है कि यह डाउटफुल हो, तो उसने कह दिया कि बहुत बढ़िया कपड़ा है। फिर प्रधानमंत्री के पास गया और पूछा कि कैसा कपड़ा है, तो उसने भी सोचा कि जब राजा को दिखाई पड़ गया और हमको नहीं दिखाई पड़ा, तो उसने भी कह दिया कि कपड़ा बहुत अच्छा है। सबको दिखला दिया गया और राजा लंगटा करके शाम में हाथी पर बैठा कर शहर में घुमा दिया गया। एक सात साल का बच्चा बाप के कंधे पर बैठा हुआ था। जब उसने देखा, तो उसने कहा कि बाबूजी, यह तो लंगटा राजा कि है। वह उसके मुंह को दबा कर भाग गया। इसलिए कभी-कभी ऐसी होड़ होती है कि जो लोकपाल का सपोर्ट नहीं करे, वह बे-ईमान हो गया, वह करप्ट हो गया। इसलिए लोकपाल का सपोर्ट करना ही है, तो कीजिए। हम लोग तो कम, आप ही लोग ज्यादा भुगतिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप मान रहे हैं कि वे जा रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: हमने कहा कि इसका क्रेडिट तो सरकार ले ही रही है, लेकिन जब भुगतिएगा, तो सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, हम आपसे यह कहने के लिए आए

[श्री रामविलास पासवान]

हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, तो आपने इसमें एनजीओ को क्यों नहीं रखा? अगर आपकी नीयत साफ है, तो आपने इसमें बिजनेसमैन को क्यों नहीं रखा? जब से उदारीकरण की नीति आई है, जब से लिबरलाइजेशन की नीति आई है, तब से करप्शन ज्यादा बढ़ा है। घूस लेने वाला और देने वाला, दोनों अपराधी होते हैं। घूस लेने वाले को आप अपराधी कह रहे हैं और जो घूस दे रहा है, क्या वह बड़ा भारी संत हो गया? अगर आप ईमानदारी की बात करते हैं, तो इसके अन्दर सबको रखना चाहिए था।

इसमें सबसे बड़ा मामला सिटिजन चार्टर का है। बिना घूस के कोई काम नहीं होता है, महीनों-महीनों फाइल पड़ी रह जाती है। आप सिटिजन चार्टर बनाइए। उसका एक टाइम फिक्स कीजिए कि कौन सा काम कितने दिनों के अन्दर होगा। इसलिए हमारे यहां जो सिस्टम है कि ऐक्ट है, फैक्ट है, और टैक्ट है, हमने कहा कि ऐक्ट अलग है, फैक्ट अलग है और टैक्ट अलग है। नेता, नीति और नीयत। अगर हमारी नीयत साफ हो जाए, तो जो वर्तमान कानून है, वह सफिशिएंट है। यदि आपकी नीयत साफ नहीं होगी, तो आप चाहे लोकपाल बिल लाइए, महालोकपाल बिल लाइए, जो पाल लाना है, हर पाल को ले आइए, उससे किसी समस्या का निदान होने वाला नहीं है। जब 10 साल के बाद फिर पार्लियामेंट बैठेगी, तब जाकर यह मंथन करेगी कि हमने इतने उत्साह के साथ जो लोकपाल कानून बनाया था, उसका क्या हश्र हुआ और फिर कोई दूसरा बिल आ जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): मैडम, जो लोकपाल बिल आया है, उस पर सदन आज गम्भीर चर्चा कर रहा है। लोकपाल बिल इसके पहले भी आया था, जिस पर हमारी पार्टी की असहमति थी। मैं समझता हूं कि आज भी हमारे मन में आशंकाएं हैं कि इस लोकपाल का कहीं दुरुपयोग न हो। रामविलास जी ने भी यही बात कही है।

माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि लोकपाल में अच्छे लोग आएं। लोकपाल नौ-सदस्यीय होगा, जिसमें एक चेयरमैन और आठ सदस्य होंगे। लोकपाल एक इग्ज़ाम्पल बने, ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए और उसके लिए मापदण्ड बनाया जाना चाहिए। आप यह कैसे करेंगे, यह आपको देखना होगा। लोकपाल सबसे ऊपर होगा, पार्लियामेंट के ऊपर होगा, माननीय प्रधान मंत्री जी के भी ऊपर होगा और सारे अधिकारियों के ऊपर होगा। कानून तो पहले से ही विराजमान है, लेकिन जब-जब हम कानून बनाते रहे हैं, भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ी समस्या बना रहा है। सारा सदन इस बात से सहमत है।

महोदया, क्या पहले के कानून बनाने के बाद हमने कभी सोचा था कि इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ नहीं सकेंगे। आज लोकपाल बनाने के लिए हम बाध्य हो रहे हैं, सदन बाध्य हो रहा है, चूंकि पहले का जो कानून था, वह इफेक्टिव नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि लोकपाल बनाने के बाद भी शायद, जैसा कि माननीय सदस्य रामविलास पासवान जी और श्रीमान् तिवारी जी ने कहा, यह इफेक्टिव नहीं बन सकेगा और फिर दोबारा से लोकपाल नाम की कोई दूसरी चीज़ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।

आज यह इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि देश के सारे पॉलिटिशयंस चोर हैं। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद और आजादी से पहले भी जिन लोगों ने इस खूबसूरत आजाद हिन्दुस्तान को बनाया, संवारा, वे सारे पॉलिटिशियंस ही हैं, जिनकी दस-दस, बीस-बीस, तीस-तीस साल की तपस्या है। पार्लियामेंट का जो मेम्बर बनता है, वह बहुत मुश्किल से इस संस्थान तक पहुंचता है, मगर यह इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि सारे के सारे पॉलिटिशयंस चोर हैं, केवल कुछ लोग ही साफ-सुथरे हैं।

यहां पर कई लोगों ने कई बातें कही, जिनमें कहा गया कि हम लोकपाल में रिटायर्ड जजिज़ को बहाल करेंगे। क्या उनके ऊपर आज अंगुली नहीं उठ रही है? मैं उनका सम्मान करता हूं। न्यायाधीशों के प्रति, न्यायालय के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन आप दूध के धुले हुए लोग कहां से लाएंगे और कैसे आप उनसे न्याय मांगेंगे, यह आशंका बन रही है।

माननीय मंत्री जी, इस चीज़ को जरूर इंश्योर करना चाहिए कि निश्चित तौर पर इस लोकपाल के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। रामविलास जी व्यावहारिक बात बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर है। लोक-लाज के डर से कि हमारा इम्प्रेशन खराब न हो जाए, इसकी वजह से हम इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा।

आज सबसे अधिक इस देश का पॉलिटिशियन कटघरे में है, जो हिन्दुस्तान को बनाने में अपनी भूमिका अदा करने का काम करता है। एक-एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन एक मिनट के अन्दर आप उसको * बना देते हैं। कुछ एक लोग तो समाज के हर वर्ग, हर तबके में मौजूद हैं, चाहे वह जूडिशियरी हो, पत्रकारिता हो, विधायिका हो अथवा अधिकारी-पदाधिकारी हों सबमें करप्शन आया है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन, सब के सब चोर हैं? ऐसा मैं नहीं मानता। अगर हम यह मंशा लेकर चलेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी।

आज क्या हो रहा है? आज 'आप' पार्टी का जन्म हो रहा है। आज 'आप' पार्टी का जन्म हुआ है और उसका क्या हश्र होने वाला है, यह आगे पता चलेगा। निश्चित तौर पर आज नैतिक बल बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा। हम कानून तो बना देंगे, लेकिन अगर अपने दिल को साफ करने का काम नहीं करेंगे, मन को साफ नहीं करेंगे तो आप चाहे जितने भी कानून बनाएं, निश्चित तौर पर करप्श्न कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले अपने अन्दर झांक कर देखना चाहिए।

हिन्दुस्तान में करप्शन एक बहुत बड़ा संकट है, कोढ़ है, कैंसर है। आम आवाम में हमारे खिलाफ गुस्सा है। यह जो असमानता बढ़ती जा रही है, गैर-बराबरी बढ़ती जा रही है, अगर इस गैर-बराबरी को दूर करने का काम नहीं किया, तो निश्चित तौर पर एक तबका एक वर्ग आगे आएगा और लोकतन्त्र खत्म होता जाएगा।

इस सदन को इस पर निश्चित तौर से सोचना पड़ेगा। केवल कानून बनाने से कुछ

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री राम कृपाल यादव]

नहीं होने वाला है। इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं, जिनसे आज मैं असहमत हूं, मेरी पार्टी भी आज असहमत है। प्रधानमंत्री का पद देश का एक बहुत बड़ा गौरवशाली पद है। उसको हम डॉक में खड़ा करना चाहते हैं! तब उसको मोरल राइट रहेगा? देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उसमें रहेगी? जिस रोज एक झूठा आरोप भी उस पर लगाया जाएगा, उसका मोरल राइट गिर जाएगा और देश की गरिमा गिर जाएगी। इसलिए, मैं इससे असहमत हूं। प्रधानमंत्री के पद को इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए। कम-से-कम कुछ तो गरिमा रखने का काम करें! देश का प्रधानमंत्री सवा सौ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक साधारण-सा आदमी अगर उसके ऊपर कीचड़ उछालने का काम करता है, तो निश्चित तौर पर उसका मोरल राइट नहीं होता है। आज इस पक्ष के लोग हैं, कल उस पक्ष के लोग आने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है। इसलिए, महोदया, मैं आपसे निवेदन करते हुए एक ही बात कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): नहीं, आप इधर देखते हुए बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव: मैडम, भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें 'माइनॉरिटी' शब्द पर सबको बड़ी आपत्ति होती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस देश की आवाम में माइनॉरिटी के करोड़ों लोग हैं, उनको आप इस देश की मुख्य धारा से क्यों अलग करना चाहते हैं? इसमें क्या आपत्ति है, अगर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और मॉइनॉरिटी के लोग रहते हैं तथा महिलाएं रहती हैं? उनसे आपको क्या घृणा है?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): प्लीज़

श्री राम कृपाल यादव: मैं पूछना चाहता हूं कि क्या द्वेष है? यह नफरत की भावना को छोड़िए। उसे गले लगाइए, क्योंकि वह बीस करोड़ की आबादी है, जिसने इस देश को बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करने का काम किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): थैंक यू।

श्री राम कृपाल यादव: वे इस देश के नागरिक हैं। ...**(समय की घंटी)**... क्या आप उनको निकाल देना चाहते हैं? उन्हें उनके हक नहीं देना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**... आप क्या स्थिति पैदा करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी आपके भाई हैं, उनको भी प्यार से गले लगाने का काम कीजिए। उनको भी अधिकार देने का काम कीजिए। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): थैंक यू।

श्री राम कृपाल यादव: अन्यथा, देश अशांत होगा और आप देश की जिस एकता और अखंडता की बात करते हैं, वह असत्य साबित होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): थैंक यू।

श्री राम कृपाल यादव: आप देश को एक करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हटा कर....

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): राम कृपाल यादव जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदया, मैं समझता हूं कि आप अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का काम कीजिए। उन माइनॉरिटी के भाईयों को गले लगाइए। वे आपके साथ भी खड़े रहेंगे। आप उनको अलग मत समझिए। देश का वह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अपने इस अंग को काट कर आइसोलेट करना चाहते हैं! इसलिए, मैं समझता हूं कि इस पर आपकी मानसिकता बदलनी होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।

श्री राम कृपाल यादव: महोदया, मुझे अंतिम बात कहने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): राम कृपाल यादव जी, आपने बहुत अच्छा बोला है। अब नेक्स्ट स्पीकर को बोलना है।

श्री राम कृपाल यादव: महोदया, मैं अंतिम बात कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैडम, आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए।

महोदया, बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि आप लोकपाल तो बना रहे हैं, लेकिन केवल देश तक ही भ्रष्टाचार सीमित नहीं है। यह भ्रष्टाचार नीचे तक, पंचायत स्तर तक चला गया है। जब तक आप लोकपाल जैसे लोकायुक्त का गठन नहीं कीजिएगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित कई स्टेट्स हैं, जैसा कहा गया है – गुजरात, मध्य प्रदेश। यहां लोकायुक्त क्यों नहीं है? मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज लोकपाल बिल पास हो जाएगा, सदन इस पर अपनी मोहर लगा रहा है, मगर आप पहल कीजिए, माननीय मुख्यमंत्रियों को बुलाइए, उनको समझाइए और उसमें प्रावधान कीजिए...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): थैंक यू। थैंक यू, राम कृपाल यादव जी। आपने बहुत अच्छा बोला।

श्री राम कृपाल यादव: कि आप भी अपने स्तर पर लोकायुक्तों की नियुक्ति कीजिए, क्योंकि केन्द्र से ज्यादा करप्शन राज्यों में है। हमारा प्रदेश बिहार भी एक राज्य है। आदरणीय शिवानन्द तिवारी जी के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है। ...**(समय की घंटी)**... ये भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे थे, मगर आज जो बिहार में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ शासन है, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। जहां हाथ लगाइएगा, वहां भ्रष्टाचार होगा। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आप राज्यों में भी लोकायुक्त बनाने का काम जरूर कीजिए, ताकि भ्रष्टाचार नियंत्रित हो सके।

5.00 P.M.

अंत में, जो पोलिटिकल सिस्टम है, इस पोलिटिकल सिस्टम के माध्यम से अच्छे लोग, जो साफ-सुथरी छवि के लोग हैं, जो असली कार्यकर्ता हैं, वे ऊपर नहीं आ रहे हैं। आज चुनाव में जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसमें एम.एल.ए. बनने के लिए लोग करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। तो भ्रष्टाचार कैसे नहीं आएगा? आज तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): राम कृपाल यादव जी, आप प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: आम लोग भ्रष्टाचारियों को लिफ्ट देने का काम कर रहे हैं। इसलिए, सम्पूर्ण जनता में जब तक करप्शन से लड़ने की, करप्शन को दूर करने की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक केवल किसी सांसद पर थोपना या किसी पोलिटिशियन पर थोपना, उचित नहीं होगा। ऊपर से नीचे तक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा और आम जनता, जो सवा सौ करोड़ जनता है, उसकी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है।

मैं पुन: भारी मन से ही सही, इस लोकपाल बिल का समर्थन करते हुए और आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं विशेष तौर पर माननीय कानून मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही, मैं सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन श्री चतुर्वेदी जी तथा उसके सभी सदस्यों के प्रति, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस लोकपाल विधेयक पर काम किया, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Thank you. Now, Shri Ranbir Singh Prajapati. Mr. Prajapati, you have five minutes.

SHRI NARESH GUJRAL: Madam, you didn't say 'five minutes' to those Members!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): We have said, five minutes to all Members, Mr. Gujral. Please let me negotiate with the Members. Kindly let me run the House.

श्री रणवीर सिंह प्रजापति (हरियाणा): धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इस ऐतिहासिक बिल, लोकपाल बिल पर बोलने का मौका दिया। देश की जनता की मांग थी कि एक मजबूत लोकपाल बिल सरकार लेकर आए। प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, वरना जनता आपको दरकिनार कर देगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Can we keep the volume down, please? There is a lot of cross-conversation and we are not able to hear.

श्री रणवीर सिंह प्रजापति: मैडम, आज जनता के दबाव के कारण ही सरकार यह लोकपाल बिल लेकर आई है। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने हमेशा ही सशक्त लोकपाल बिल का समर्थन करने का काम किया है। हमने तो सर्वदलीय मीटिंग में भी यह कहा था कि प्रधानमंत्री जी का पद और सीबीआई को लोकपाल के दायरे में होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई लगातार सरकार के इशारे पर काम कर रही थी। पिछले समय में काफी ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें यह साफ दिखाई देता है कि जो लोग सरकार के साथ थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद उन लोगों का कुछ नहीं हुआ और जो लोग सरकार के विरोधी थे, वे सीबीआई के षड्यंत्र के शिकार हुए। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी अगर कॅन्विक्ट हुए, तो वे सीबीआई के शिकार हुए, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं थे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। आज पूरे देश की जनता ने यह मांग की और देश के अंदर अन्ना हजारे के नेतृत्व में इसके लिए बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए। देश की जनता ने इस बात की मांग की कि सशक्त लोकपाल बिल आए। पहले इस मौजूदा सरकार की यह मंशा नहीं थी, इसलिए 2011 में यह आधा-अधूरा लोकपाल बिल लेकर आई थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर, चाहे वह सीबीआई का मामला हो या प्रधानमंत्री पद का मामला हो, कुछ शर्तों के आधार पर ये दोनों बातें लोकपाल के दायरे के अंदर आई हैं। इस बात की हमें खुशी है और हम अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजनीति में स्वीकृति और विकृति दोनों हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज सदन में स्वीकृति का प्रारूप ज्यादा दिखाई दिया।

महोदया, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, जो सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, वे निश्चित रूप से कांग्रेस के सदस्य हैं और उनकी प्रतिबद्धता अपने दल के साथ है। इसके बावजूद यह देख कर अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल, अरूण जेटली जी, अशोक गांगुली जी और लगभग सभी सदस्यों ने जिन्होंने अपना वक्तव्य यहां रखा, उन्होंने सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की। यही लोकतंत्र की मर्यादा है और यही लोकशाही की गरिमा का असली स्वरूप है, लेकिन अपनी बिरादरी के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। आज जो राजनीतिक और एक्जीक्युटिव की गरिमा घटी है, आदरणीय रामविलास जी, इसके लिए दोषी कोई और नहीं, दोषी हम और आप हैं। हमारा यह लक्ष्य रहता है कि कैसे हम हर मुद्दे का छिद्रान्वेषण करके उसको बड़ा प्रारूप दें और उसे बड़ा प्रारूप देकर एक दूसरे के कद को घटाएं। इसी वजह से ज्यूडिशियरी और हमारे पत्रकार बन्धु क्षमा करेंगे, वे हमारे ऊपर हावी हो गए हैं और हम महत्वहीन होते जा रहे हैं। मैं भारी मन से नहीं, बहुत अच्छे मन से इस बिल का समर्थन इसलिए करना चाहता हूं कि हमारी पुरानी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अगर महिला आरक्षण बिल हो, उसका विरोधा करेगी, महिला सुरक्षा बिल हो, उसका विरोध करेगी और अब जब

[श्री अमर सिंह]

लोकपाल बिल हो, तो इसका विरोध करेगी कि अगर कहीं महिला आरक्षण बिल पास होगा, तो पुरुषों का अधिकार-वंचन हो जाएगा, महिला सुरक्षा बिल पास होगा, तो हम महिला कर्मचारी नहीं रखेंगे, बलात्कार का आरोप लग जाएगा और अगर कहीं लोकपाल का विधेयक आएगा, तो फिर हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, कानून के बोझ तले हम बहुत बुरी तरह से दब चुके हैं।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

एक बात यह उठाई गई कि कई बार ऐसा होता है कि लोग 10-10 साल तक जेल की यंत्रणा सहते हैं और उसके बाद बरी हो जाते हैं, लेकिन उनके जो 10 साल जेल में बीतते हैं, उसका क्या होगा? मैं भी भुक्तभोगी हूं, मैंने भी ढाई महीने तक जेल की यंत्रणा भोगी है, फिर मुक्त हो गया हूं, लेकिन मुक्त होने के बाद अभी भी जब मैं सवेरे उठता हूं तो कभी-कभी तिहाड़ जेल का वह भजन याद आता है – *ऐ मालिक तेरे बन्दे हम, ऐसे हों हमारे करम*। अब हमारे करम चाहे जैसे थे, लेकिन हमें वह भजन याद आता है। हम मुक्त हो गए, लेकिन हमारा वह ढाई महीने का बन्धन हमारे जीवन पर अमिट छाप छोड़कर चला गया है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि समय का अभाव है। यहां हमारे दोस्त, रवि शंकर प्रसाद जी बैठे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां बात लोकपाल की हो रही है। बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत आदर के साथ हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि यहां पर लोकपाल की बात के अंदर घोटालों की बात भी हो गई। मैं परोक्ष रूप से कहना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। यह कहा गया कि जीरो लॉस है। यह बात सिर्फ राजनेता नहीं कह रहे हैं। एक न्यायमूर्ति, जो टू जी का मामला देख रहे हैं, उन्होंने लोगों को बंदी बना दिया है और उसी न्यायमूर्ति के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस कपाड़िया ने अपने अवकाश प्राप्त करने के दिन यह कहा कि प्रिवेंटिव लॉज और एक्चुअल लॉज में अंतर है, उसका आप क्या करिएगा? मुख्य न्यायाधीश एक बात कह रहे हैं, न्यायमूर्ति दूसरी बात कह रहे हैं। यह विरोधाभास इसलिए है कि एक्जिक्यूटिव में एकता नहीं है। हम लोगों ने अपनी गरिमा को कम किया है, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। इससे पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं शीला दीक्षित को 15 साल तक दिल्ली की सेवा करने के लिए अभिनंदित करता हूं। यही लोकशाही की मर्यादा है, यही लोकशाही का तकाजा है। ऐसे लोग जो क्रिकेट के खेल में जीत जाते हैं, लेकिन जिन्हें क्रिकेट नहीं आता, वे कहते हैं कि हम खेलेंगे जरूर, लेकिन हमें नॉट आउट करना, कैच आउट मत करना या बॉल आउट मत करना, हमारे ऊपर कोई नियम नहीं चलेगा, कोई कानून नहीं चलेगा। उनके लिए अरूण जेटली जी का बयान बिल्कुल सही है। भले ही वे भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारी-उनकी विचारधारा में विरोध रहा हो, लेकिन बयान शानदार है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक सार्वजनिक बयान दिया है। अगर हम लोग एक दूसरे की

गरिमा को, एक दूसरे को इस तरह से गिराएंगे, तो ऐसे ही लोग आएंगे, इस शून्य को ऐसे ही लोग भरेंगे, जो जीत तो जाएंगे, लेकिन उनको आर्ट ऑफ गवर्नेंस का पता नहीं होगा, जो जिम्मेदारी लेने से भागेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकें। भ्रष्टाचार की बात करने वाला हर सदस्य अपने दिल पर हाथ रखकर बताए, चाहे वह फंसा दिया गया हो या सच में भ्रष्टाचारी हो अथवा नहीं हो, चाहे सच्चा मुकदमा है या झूठा मुकदमा है, लेकिन ऐसा कौन-सा नेता है, किस दल का नेता है जिसके ऊपर आय से अधिक सम्पत्ति का मामला न हो, घपले और घोटाले का मामला न हो?

"यार हमारी बात सुनो,
ऐसा एक इंसान चुनो,
जिसने पाप न किया हो,
जो पापी न हो।"

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग क्रेडिट ग्रैबिंग या श्रेय लेने के चक्कर में न पड़ें। आज बहुत दिन बाद संसद एक साथ बैठकर एक नियम, एक कानून पर बहुत विचार के बाद एक निर्णय पर पहुंची है और उसको पारित करने जा रही है। आइए, हम सब मिलकर एक बार यह भूल जाएं और यह जो वकीलों की चर्चा होती है, हम तो इस बात से खुश हैं कि कल फिर कोई मुकदमा लग जाए। कोई भी वकील खाली होगा, आप खाली रहेंगे तो रवि शंकर भाई, आप खड़े जो जाइएगा। आप कपिल जी को खाली करेंगे तो वे हमारे मित्र हैं, वे हमारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे। वकील मिलने चाहिए, क्योंकि राजनीति करने वालों को और मेरे जैसे बीमार आदमी को वकील और डॉक्टर की बड़ी जरूरत है। इन शब्दों के साथ, इस बिल का मैं दिल से समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. That concludes the discussion on the Bill; the hon. Minister to reply.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I, first of all, would like to thank the distinguished Members of this House who have unanimously, I think, without exception supported this Bill. And, I have to say that when I rose to initiate the debate, or continue with the debate, I tried to keep politics out of it because I thought this was an issue which impacts 120 crore people of this country, and if you were to bring politics into it, it would derail the debate. There were a couple of discordant notes about the '*sharmnak* defeat' and things like that, and I will not rise to the bait because I think that we still must rise above these things. Perhaps, these remarks could have been avoided. Defeat and victory are part of politics. We have

[Shri Kapil Sibal]

been defeated several times before; we shall be defeated again. You have been defeated several times before. You will be victorious or you may be defeated, that only time will tell. But, no defeat is *sharmnak;* it is the way you look at it is *sharmnak.*

Having said that, Sir, I will just refer to the points made by the distinguished Leader of the Opposition in this House and he made three distinct points. First of all, he said that he was a little concerned about the fact that at the time of initiating investigation, the delinquent officer is being given a right to represent. Well, the background to this, and I can share that with him., though I am bringing the amendment to ensure that at the time of raid, seizure and search, there is no opportunity given to the officer, was that under the present system of things, a Group 'A' and a Group 'B' officer has the protection of section 6(a) of the Delhi Special Police Establishment Act even at the time of starting an investigation. The reason is that most of these officers are Joint Secretaries and above and if a process is started against them and there is absolutely no explanation sought from them, it would do some injustice to them. So, it has been done with that intent in mind. It is not an opportunity to hear that we were giving them; it is that in the event a prosecution is to be started and there are certain materials and documents available, they can be asked for an explanation and that is all that is given. So, having given an explanation to them, we are also making sure that if the department or the investigating agency is to seize and search, there should be no impediment in their way and it is-in that context that this particular provision was incorporated, and I am sure the distinguished Members of this House will understand the intent behind it. That is point number one.

Point number two that was mentioned was that there is a section, section 63, now in the Act where we hope now that all State Governments will take note of the fact that we have passed a very strong, a very independent Lokpal Bill to deal with the menace of corruption and we hope that every State Government will take this as a model Bill and then, in the course of the next one year, draft the legislation consistent with this particular one. We, of course, cannot give a direction because Legislatures in States have plenary powers. We cannot interfere with those processes and the Legislature ultimately will have to decide on its own as to what kind of Bill should be passed. But, I must say and I want to place it on record that while we debate these issues in this House and as political parties are involved, the real test of every national party or State party, if they really

believe in dealing with corruption, is as to how quickly they pass this Bill in the State in which they are in power. If they do not do so, then, the people of this country will realize that you spoke with one voice in this House, and, you are double-speaking in the place in which you are in power. I am sure that forty-six years will not pass when State Governments will adopt this particular Bill by the respective Legislatures in the next 365 days. But, yes, it is inconsistent with the principle of federalism for us to give any direction to any State Government.

The third point, which the distinguished Leader of the Opposition made, was in respect of the reservation for religious minorities. Sir, he is a very dear colleague of mine, and, I would like to draw his attention to Article 16(4) of the Constitution, which is the only article which provides reservation in the context of employment. If you carefully look at the words of Article 16, you will find that 16(4) is the provision which provides reservation. I will just read it out. You are familiar with it, but there may be other distinguished Members who are not. It says, "Nothing in this Article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State." The policy of reservation applies when you are serving under the State. The policy of reservation does not apply when you are not serving under the State. This is a unique piece of legislation. This is not service under the State. In fact, we are doing just the opposite. We are trying to put in place individuals, who are Lokpals, who are not under the service of the State, who are independent in the exercise of their power, and, therefore, there is a big distinction between serving under the State, and, appointing a representative group of people which represents the democratic fabric of this country in the Lokpal to ensure that no particular community is dealt with in an unjust manner, and, we have seen that happening. We have seen that happening in various parts of the country. So, that is my response to the distinguished Leader of the Opposition.

There are several other issues, which have been raised. Sitaram ji, in fact, raised the issue of supply and demand, and, he mentioned his mentor in that context, who always talked about supply and demand in the classroom. I can assure you that we are dealing with the issue of supply and demand as well. We are dealing with the issue of supply in the Prevention of Corruption Act. As you are aware, that Amendment Bill is already in place. It is the Prevention of

[Shri Kapil Sibal]

Corruption (Amendment) Bill, 2013. It is pending in the Lok Sabha, and, that Bill actually deals with the supply side corruption. So, I want to inform my distinguished friends, yes, we are cognizant of that fact. We are not bringing it under the Lokpal but we are certainly bringing it under the Prevention of Corruption Act so that supply-side corruption can also be dealt with effectively.

Sukhendu ji talked about some clauses in the Bill, and, said, why should we have Judges appointed in the Lokpal; fifty per cent of them would be Judges? Well, we do it because we believe that when you are dealing with complex legal issues, complex financial issues or some other kinds of complex issues, we need some legal training, and, what better training than that of a person who has been a Judge of the Supreme Court, or, a Chief Justice of a High Court, or, a Chief Justice of India. He also mentioned about the fact as to why should we not have Members of Parliament or the Members of the Legislative Assemblies in the Lokpal. The reason is simple. They are subject to investigation.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: I did not say that. I only said, there was no need to have brought the provision of debarring the Members of Parliament because you have already said that such and such people will be the Chairperson or the Members.

SHRI KAPIL SIBAL: That is what I said. We are debarring them because there is a conflict of interest. The purpose of this law is to deal with the Members of the Parliament and the Members of the Legislative Assemblies, and, if they are the ones who are going to be represented in the Lokpal, there is going to be a problem, there is going to be a conflict of interest. If they belong to a particular political party, they may be biased in the processes within the Lokpal itself. So, we do not want that conflict to happen.

Shivanand Tiwari ji, I think, you made a very, very important point. The point, I think, has been reverberating in this House. Many hon. Members, in fact, spoke about it. You can have a Lokpal. And legislation is all work in progress because legislation essentially is a response to what people want. It is the surge of opinion within society that sensitises the legislature to actually come up with a legislation to deal with society. But the response of the people keeps on changing because the needs of the people keep on changing. Therefore, legislation is always work in progress. If you want to deal with corruption, law alone will not ensure

elimination of corruption. I am of the firm belief of that. By itself, the laws will help deal with those who are corrupt but laws will not deal with the impetus of human beings to be corrupt. It will deter human beings perhaps if the law is effectively administered. But it is the inequality within the society जो गरीब और अमीर आदमी के बीच का अंतर है, लिबरलाइजेशन की रेजीम के द्वारा आज काम हो रहे हैं, जब तक हम उस divide को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम इसकी लड़ाई पूरी तरह से नहीं लड़ पाएंगे। तो यह बहुत जरूरी बात है, यह जो आर्थिक अंतर आया है, इसके लिए हमें और जोर लगाना पड़ेगा और सरकार कोशिश कर रही है कि आम आदमी के लिए हम काम करें। मैत्रेयन जी ने भी बहुत सी बातें कही हैं। He talked about December, 2011. The fact of the matter is that this is really what democracy is all about and that despite the fact that we have differences of opinion, we can get together and we can ultimately arrive at a consensus. There is no need to score brownie points that I was responsible for the consensus or somebody else was responsible. It is the collective will of this House which ultimately has delivered. We need to congratulate the collective will of this House in which the Leader of the Opposition is a part, Shri Satyavrat Chaturvedi is a part, and every Member of this House who was represented in the Committee is a part and I congratulate all of them.

All the other distinguished Members, namely, Ramalingamji, Paridaji, Trivedi *sahib,* Ashok Ganguly *sahib,* Chandrasekhar *sahib* and Ravi Shankar Prasadji, ultimately supported the Bill. They mentioned that we should bring some of the other legislations. I just want to mention that this Government, in fact, is the one that has brought these legislations to the House either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha. These are the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013; the Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of Their Grievances Bill, 2011; the Public Procurement Bill, 2012; and the Bill to address foreign bribery as required under Article 16 of the UNCAC. These are pending in the Lok Sabha. The Judicial Standards and Accountability Bill and the Whistle blowers' Protection Bill, 2011 are pending in the Rajya Sabha. If both the Lok Sabha and the Rajya Sabha had actually been functioning on a daily basis, hopefully these Bills would have been passed. But, unfortunately, we had not had the time for one reason or another. But I don't blame anybody because this is not the time to blame. Let us all try and work extra hours to bring these Bills to the House and to have them passed so that we don't have to blame each other as to why you did not bring it and why you did not pass it. It is with this intent that I have not responded to some of the discordant notes.

श्री रामविलास पासवान: सर, प्रधानमंत्री जी के बारे में ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: As far as the issue of Prime Minister is concerned, this, by and large, is the consensus of the House that the Prime Minister should be included. *...(Interruptions)...*We respect individual opinion. *...(Interruptions)...* We respect opinions of individual Members. But that is the consensus of the House. The UPA stands by that consensus. I am sure the BJP or the NDA also stands by this consensus. I think the Left parties are also agreeable to it. Yes, there are points of view which we respect. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. *...(Interruptions)...* Let the hon. Minister continue. प्लीज, बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, with these words, I commend the Bill to this House. *...(Interruptions)...*

DR. V. MAITREYAN: What about *...(Interruptions)...*

श्री सभापति: प्लीज, आप अपनी बात कह चुके हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव: प्रधानमंत्री जी को इस दायरे में नहीं लाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप अपनी बात कह चुके हैं। Thank you very much. Now, I put the motion to vote. The question is:

> That the Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruptions against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 13 were added to the Bill.

Clause 14 - Jurisdiction of Lokpal to include Prime Minister, Minister, Members of Parliament, Groups A, B, C and D Officers and Officials of Central Government

MR. CHAIRMAN: In clause 14, there are four amendments. Amendment (No.14) by Shri Sitaram Yechury, Shri K.N. Balagopal, Shri C.P. Narayanan and Shri P. Rajeeve. Are you moving?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I move:

14. That at page 8, *after* line 27, the following be *Inserted,* namely:-

"(i) any corporate body, its promoters, its officers including Director against whom there is a complaint of corruption in relation to grant of Government licence, lease, contract, agreement or any other including the conduct of the Public Private Partnership (PPP) projects or to influence Government policy through corrupt means".

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.14) moved by Shri Sitaram Yechury, Shri K.N. Balagopal, Shri C.P. Narayanan and Shri P. Rajeeve to vote.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, we want division. ...*(Interruptions)*... Sir, it is a very important point. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It is clear in the voice vote. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, it is a very important point. ...*(Interruptions)*... Most of the projects are run by PPP mode. ...*(Interruptions)*... It should come under the purview of the Lokpal. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the point is, the hon. Minister has assured that the Prevention of Corruption (Amendment) Bill has already taken this point into account. So, there is no contradiction with the Government as well. They also agree with this point. Our contention is that in the Lokpal, since the Government also agrees with it, since they have also brought forward an amendment to the other law and since there is no dispute, why don't they bring it in this legislation as well? That is the point. This is not a point of dispute because the hon. Minister himself has said that the Government is for it and we are happy. We are glad that the Government is for it. So, we are saying that bring it in this legislation as well. That is the point.

MR. CHAIRMAN: Yechuryji, the point is, the House has expressed its opinion. ...*(Interruptions)*... There is no ambiguity about it. ...*(Interruptions)*... Please don't press it. I think the views of the House are clear. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, we entirely agree with the spirit of what he has said. ...*(Interruptions)*... We are going to take this forward. It will be a part of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill. ...*(Interruptions)*... Let us see the experience of that and then, we will come back to it if it is necessary. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, the entire economy of the country is run on PPP mode. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Just one minute please. *...(Interruptions)...*

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am only submitting. *...(Interruptions)...* Sir, I entirely appreciate your sentiments. I entirely. appreciate the sentiments of the House and also that of the ruling benches who have assured that they are going to take this on board. The point is, there is a great degree of agitation because most of the country is now being run on the PPP mode. Sir, please understand the sentiment. Tomorrow, there may be any other agitation. It would call us uncivil society; a civil society will come and they will say that they want a review of your electricity bills here. All of them are PPP projects. Now, we don't know who is going to run the Government in Delhi. *...(Interruptions)...* Now, if that happens, all of us are going to succumb tomorrow. *...(Interruptions)...* When you say overrule it, all of you are going to succumb tomorrow when they say review that. *...(Interruptions)...* Therefore, let this be decided. It will take two minutes. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You have made your point. *...(Interruptions)...* The point is, you have made your point in the debate. *...(Interruptions)...* You moved an amendment. The view of the House is crystal clear. So, why do you want to press for a division? *...(Interruptions)...* The record of the House is there. *...(Interruptions)...*

SHRI P. RAJEEVE: It should be recorded. *...(Interruptions)...*

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it will be faster. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: The 'noes' have it is crystal clear. *...(Interruptions)...* There is no ambiguity about the opinion in the House. *...(Interruptions)...* The 'noes' have it. *...(Interruptions)...* The amendment is negatived? *...(Interruptions)...*

SHRI P. RAJEEVE: No, Sir, it should be as per the rule. *...(Interruptions)...*

SHRI K.N. BALAGOPAL: No, Sir. It should be as per the rule. *...(Interruptions)...*

SHRI P. RAJEEVE: We are demanding division on this clause. It is our right. How can you deny it?

MR. CHAIRMAN: it is seven Members against rest of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: We are seeking division on our amendment. It is as per the rules. Sir, seek voting, not counting. Please read the rules. ...*(Interruptions)*... It is not counted orally. The Chair should put the amendment to vote as per the rules. How could the Chair deny it? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Yechury, please.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, please put the amendment to vote; and we seek a division on it. It will be done much faster than this. Please ask for the division and finish off.

MR. CHAIRMAN: If you insist, yes, of course. Let the Lobbies be cleared. The question is:

That at page 8, *after* line 27, the following be *inserted*, namely:-

> "(i) any corporate body, its promoters, its officers including Director against whom there is a complaint of corruption in relation to grant of Government licence, lease, contract, agreement or any other including the conduct of the Public Private Partnership (PPP) projects or to influence Government policy through corrupt means".

The House divided.

Ayes - 19

Achuthan, Shri M.P.

Baidya, Shrimati Jharna Das

Baishya, Shri Birendra Prasad

Balagopal, Shri K.N.

Behera, Shri Shashi Bhusan

Chakraborty, Shri Shyamal

Chatterjee, Shri Prasanta

Mohapatra, Shri Rabinarayan

Mukherji, Dr. Barun

Narayanan, Shri C.P.

Parida, Shri Baishnab

Pradhan, Shrimati Renubala

Rajeeve, Shri P.

Rangarajan, Shri T.K.

Seema, Dr. T.N.

Sen, Shri Tapan Kumar

Tirkey, Shri Dilip Kumar

Tiwari, Shri Shivanand

Yechury, Shri Sitaram

Noes - 160

Abraham, Shri Joy

Adeeb, Shri Mohemmed

Aga, Ms. Anu

Aiyar, Shri Mani Shankar

Ali, Shri Munquad

Ali, Shri Sabir

Anand Sharma, Shri

Ansari, Shri Salim

Antony, Shri A.K.

Arjunan, Shri K.R.

Ashk Ali, Tak, Shri

Baghel, Prof. S.P. Singh

Balaganga, Shri N.

Balmuchu, Dr. Pradeep Kumar

Bandyopadhyay, Shri D.

Batra, Shri Shadi Lal

Bernard, Shri A.W. Rabi

Bhattacharya, Shri P.

Bora, Shri Pankaj

Bose, Shri Srinjoy

Budania, Shri Narendra

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chaturvedi, Shri Satyavrat

Chavan, Shrimati Vandana

Chowdary, Shri Y.S.

Chowdhury, Shrimati Renuka

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Darda, Shri Vijay Jawaharlal

Dave, Shri Anil Madhav

Deora, Shri Murli

Dua, Shri H.K.

Dwivedi, Shri Janardan

Faruque, Shrimati Naznin

Fernandes, Shri Oscar

Ganguly, Dr. Ashok S.

Gehlot, Shri Thaawar Chand

Gill, Dr. M.S.

Goud T., Shri Devender

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Dr. Akhilesh Das

Gupta, Shri Prem Chand

Haque, Shri Md. Nadimul

Hashmi, Shri Parvez

Heptulla, Dr. Najma A.

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jain, Shri Ishwarlal Shankarlal

Jaitley, Shri Arun

Jangde, Dr. Bhushan Lal

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Jinnah, Shri A.A.

Jois, Shri M. Rama

Kalita, Shri Bhubanesbwar

Kanimozhi, Shrimati

Karan Singh, Dr.

Karimpuri, Shri Avtar Singh

Kashyap, Shri Narendra Kumar

Katiyar, Shri Vinay

Keishing, Shri Rishang

Khabri, Shri Brijlal

Khan, Shri K. Rahman

Khan, Shri Mohd. Ali

Khanna, Shri Avinash Rai

Khuntia, Shri Rama Chandra

Kidwai, Shrimati Mohsina

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Krishna, Shri S.M.

Kshatriya, Prof. Alka Balram

Kujur, Shri Santiuse

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kurien, Prof. P.J.

Kumar, Shri Pramod

Lakshmanan, Dr. R.

Mahra, Shri Mahendra Singh

Maitreyan, Dr. V.

Malihabadi, Shri Ahmad Saeed

Mandaviya, Shri Mansukh L.

Manjunatha, Shri Aayanur

Misra, Shri Satish Chandra

Mitra, Dr. Chandan

Mukut Mithi, Shri

Mungekar, Dr. Bhalchandra

Nadda, Shri Jagat Prakash

Naik, Shri Shantaram

Nandi Yellaiah, Shri

Naqvi, Shri Mukhtr Abbas

Natarajan, Shrimati Jayanthi

Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

O'Brien, Shri Derek

Pande, Shri Avinash

Pandya, Shri Dilipbhai

Parmar, Shri Bharatsinh Prabhatsinh

Paswan, Shri Ram Vilas

Patel, Shri Ahmed

Pathak, Shri Brajesh

Patil, Shri Basawaraj

Patil, Shrimati Rajani

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punj, Shri Balbir

Rai, Shrimati Kusum

Rajan, Shri Ambeth

Rajaram, Shri

Ram Prakash, Dr.

Ramalingam, Dr. K.P.

Ramesh, Shri Jairam

Rangasayee Ramakrishna, Shri

Rao, Shri V. Hanumantha

Rapolu, Shri Ananda Bhaskar

Rashtrapal, Shri Praveen

Rathinavel, Shri T.

Ratna Bai, Shrimati T.

Ravi, Shri Vayalar

Reddy, Shri Palvai Govardhan

Reddy, Dr. T. Subbarami

Roy, Shri Sukendu Sekhar

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Rupala, Shri Parshottam Khodabhai

Sadho, Dr. Vijaylaxmi

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Saini, Shri Rajpal Singh

Sancheti, Shri Ajay

Sanjiv Kumar, Shri

Seelam, Shri Jesudasu

Shanta Kumar, Shri

Sharma, Shri Raghunandan

Sharma, Shri Satish

Shukla, Shri Rajeev

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Birender

Singh, Shri Ishwar

Singh, Shri Jai Prakash Narayan

Singh, Dr. Kanwar Deep

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri N. K.

Singh, Shri Veer

Singh Badnore, Shri V. P.

Singhvi Dr. Abhishek Manu

Solanki Shri Kaptan Singh

Soni, Shrimati Ambika

Sood, Shrimati Bimla Kashyap

Soz, Prof. Saif-ud-Din

Stanley, Shrimati Vasanthi

Sudharani, Shrimati Gundu

Syiem, Shrimati Wansuk

Tariq Anwar, Shri

Tarun Vijay, Shri

Thakor, Shri Natuji Halaji

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Dr. Prabha

Thangavelu, Shri S.

Trivedi, Dr. Yogendra P.

Tyagi, Shri K. C.

Vasan, Shri G. K.

Vegad, Shri Shankarbhai N.

Vora, Shri Motilal

Waghmare, Dr. Janardhan

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Ram Kripal

MR. CHAIRMAN: The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now take up Amendments (Nos. 17 and 18) moved by Shri D. Raja and Shri M.P. Achuthan. Shri D. Raja is not there. Are you moving your Amendment, Mr. Achuthan?

SHRI M.P. ACHUTHAN: Yes, Sir. I move:

17. That at *page* 7, lines 35 to 37 be *deleted.*

18. That at page 8, *after* line 27, the following be *inserted,* namely;-

"(i) any person who is or has been Chairman or Managing Director of any business entity enjoying benefits such as export incentives, customs and excise tax concessions, etc., and getting contract from Government and public sector undertaking".

The questions were put and the motions were negatived.

Clause 14 was added to the Bill.

Clauses 15 to 19 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now clause 20. There are seven Amendments (Nos. 4 to 9 and 25) by the hon. Minister.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I only move Amendments (Nos. 6, 7, 8 and 25).

Clause 20 — Provisions relating to complaints and preliminary inquiry and investigation

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

6. That at page 10, *after* line 13, the following proviso be *inserted,* namely:-

   "Provided also that before ordering an investigation under clause (b), the Lokpal shall call for the explanation of the public servant so as to determine whether there exists a *prima facie* case for investigation."

7. That at page 10, line 16, the word "may" be *deleted.*

8. That at pages 10, line 23, *for* the words "to decide" the words "and after giving an opportunity of being heard to the public servant, decide" be *substituted.*

25. That at *page* 10, *after* line 13, the following proviso be *inserted* namely:-

   "Provided also that the seeking of explanation from the public servant before an investigation shall not interfere with the search and seizure, if any, required to be undertaken by any agency (including the Delhi Special Police Establishment) under this Act".

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

Clauses 21 and 22 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, clause 23. There is one Amendment (No.10) by Shri Kapil Sibal. Are you moving it?

SHRI KAPIL SIBAL: No, Sir.

Clause 23 was added to the Bill.

Clause 24 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now clause 25. There is one Amendment (No.11) by Shri Kapil Sibal. Are you moving it?

SHRI KAPIL SIBAL: No, Sir.

Clause 25 was added to the Bill.

Clauses 26 to 29 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now clause 30. There is one Amendment (No.15) by Shri Sitaram Yechury, Shri K.N. Balagopal, Shri C.P. Narayanan, and Shri P. Rajeeve. Are you moving it?

Clause 30 — Confirmation of attachment of assets

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I move:

15. That at page 14, *after* line 22, the following be *inserted,* namely:-

(5) The Lokpal may take *suo moto* action in any case where it has reason to believe that a lease, licence, contract or agreement or any other Government action was obtained by corrupt means and after hearing the parties if it so decides it may investigate such a case.

(6) The Lokpal may recommend blacklisting of a film, company, contractor or any other person involved in an act or corruption.

(7) The concerned public authority shall either comply with the recommendation or reject the same within a month of receipt of the recommendation:

Provided that in the event of rejection of the recommendation, the Lokpal may approach the appropriate Court for seeking directions to be given to the public authority.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 30 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now clause 31. There is one Amendment (No.16) by Shri Sitaram Yechury, Shri K.N. Balagopal, Shri CP. Narayanan, and Shri P. Rajeeve. Are you moving it?

Clause 31 — Confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits arisen or procured by means of corruption in special circumstances

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I move:

That at page 14, *after* line 38, the following be *inserted,* namely:-

"(3) The Lokpal may recommend that,-

(i) if any company or any of its officers, director is found guilty for any offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 that company and all companies promoted by any of that company's promoters shall be blacklisted and be ineligible for undertaking any Government or contract work in the future.

(ii) a sum equivalent to the loss entailed to the public exchequer shall be recovered through the confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits.

(4) The public authority shall either comply with the recommendation or reject the same within a month of receipt of the recommendation:

Provided that in the event of rejection of the recommendation, the Lokpal may approach the appropriate Court for seeking directions to be given to the public authority.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 31 was added to the Bill.

Clauses 32 to 63 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: I shall now take up The Schedule. In The Schedule there are eight Amendments (Nos. 12, 13 and 19 to 24) to be moved by Shri Kapil Sibal. Are you moving the amendments?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am not moving Amendments (Nos. 12 and 13) but I am moving Amendments (Nos. 19 to 24.) Sir, I move:

The Schedule

19. That at page 23, line 9, *for* the figure "2012'", the figure "2013" be *substituted.*

20. That at page 24, line 27, *for* the figure "2012", the figure "2013" be *substituted.*

21. That at page 24, line 32, *for* the figure "2012", the figure "2013" be *substituted.*

22. That at page 24, line 38, *for* the figure "2012", the figure "2013" be *substituted.*

23. That at page 25, line 4, *for* the figure "2012", the figure "2013" be *substituted.*

24. That at page 25, line 29, *for* the figure "2012", the figure "2013" be *substituted.*

The questions were put and the motions were adopted.

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: I shall now take up Clause 1. There is one Amendment (No. 2) by Shri Kapil Sibal.

CLAUSE 1 - Short Title, Extent, Application and Commencement

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

2. That at page 2, line 4, *for* the figure "2012" the figure "2013" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: I shall now take up the Enacting Formula. There is one Amendment (No. 1) by Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

Enacting Formula

1. That at page 2, line 1, *for* the word "Sixty-third", the word "Sixty-fourth" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Preamble and Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Kapil Sibal to move that the Bill be passed.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Anand Sharma to make a Statement on the outcome of the 9th Ministerial Conference of WTO held at Bali from 3rd to 7th December, 2013.